शीर्ष अदालत ने पर्वतमाला के लिए समिति गठित करने का प्रस्ताव रखा, 21 जनवरी को अगली सुनवाई

अरावली से जुड़ा आदेश स्थगित

सुनवाई 1

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों और पर्वतमाला की नई परिभाषा स्वीकार करने वाले अपने आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी। मामले में अगली सुनवाई 21 जनवरी 2026 को होगी।

अदालत ने चिंता जताई कि एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट और कोर्ट की टिप्पणियों को गलत समझा जा रहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत तथा न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की अवकाशकालीन पीठ ने इस मुद्दे की व्यापक और समग्र समीक्षा के लिए इस क्षेत्र के विशेषज्ञों को शामिल कर एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने का प्रस्ताव रखा। पीठ ने अरावली पहाड़ियों और पर्वतमालाओं की परिभाषा और संबंधित मुद्दों के संबंध में स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई की।

पीठ ने कहा कि इस अदालत का मानना है कि समिति द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों के साथ-साथ इस अदालत द्वारा 20 नवंबर, 2025 के फैसले में निर्धारित निष्कर्षों और निर्देशों को स्थगित रखा जाए। शीर्ष अदालत ने कहा कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर स्पष्टीकरण की जरूरत होगी। अदालत ने केंद्र सरकार और अन्य को नोटिस जारी कर मामले को आगे की सुनवाई के लिए 21 जनवरी को सूचीबद्ध किया।

कोर्ट ने नए खनन पट्टे पर रोक लगा दी थी : सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों और पर्वतमालाओं की एक समान परिभाषा को 20 नवंबर को स्वीकार कर लिया था तथा विशेषज्ञों की रिपोर्ट आने तक दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान एवं गुजरात में फैले इसके क्षेत्रों में नए खनन पट्टे देने पर रोक लगा दी थी। अदालत ने अरावली पहाड़ियों और पर्वतमालाओं की सुरक्षा के लिए अरावली पहाड़ियों और पर्वतमालाओं की परिभाषा पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था।

29 पृष्ठों का फैसला सुनाया था: अदालत ने टी. एन. गोदावर्मन तिरुमुलपाद मामले में लंबे समय से जारी पर्यावरण मुकदमे से उत्पन्न स्वतः संज्ञान मामले में 29 पृष्ठों का फैसला सुनाया था। पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने इस नई परिभाषा का कड़ा विरोध करते हुए आशंका जताई थी कि इससे पहाड़ियों को खनन, रियल एस्टेट और अन्य परियोजनाओं के लिए खोलकर उन्हें नुकसान पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने यह भी आशंका जताई थी कि अरावली क्षेत्र में खनन बढ़ाने की सोच भविष्य के लिए खतरनाक है।

राजस्थान कांग्रेस ने फैसले का स्वागत किया : राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने अरावली पर्वतमाला की नई परिभाषा से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट के 20 नवंबर के आदेश पर सोमवार को रोक लगाए जाने का स्वागत किया।

केंद्र संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध : केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं की एक समान परिभाषा को स्वीकार करने वाले अपने पुराने फैसले पर रोक लगाने का सोमवार को स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सरकार इनके संरक्षण और बहाली के लिए प्रतिबद्ध है। यादव ने एक 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली पर्वतमाला से संबंधित अपने फैसले पर रोक लगाने और मुद्दों का अध्ययन करने के लिए एक नई समिति के गठन के संबंध में उसके निर्देशों का स्वागत करता हूं।

> संरक्षण की जरूरत P06

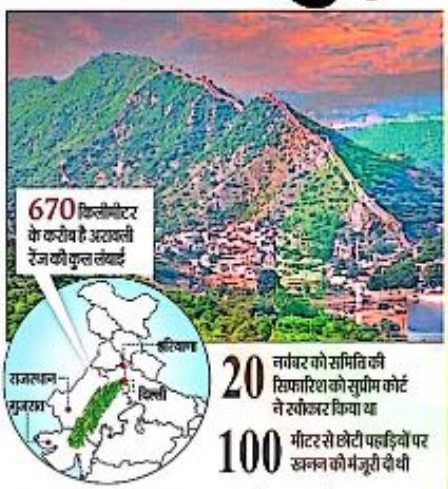

20 नवंबर को समिति की सिफारिश को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया था

100 मीटर से छोटी पहाड़ियों पर खनन की मंजूरी दी थी

उत्तर भारत का सुरक्षा कवच है अरावली

अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, बल्कि उत्तर भारत का सुरक्षा कवच है। यह थार रेगिस्तान के पूर्व की ओर विस्तार को रोकता है। चाहे ही दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहरों के लिए एक विशाल 'बफरिंग' के रूप में काम करता है। यहां 300 से अधिक पक्षी प्रजातियां और तेंदुए जैसे जंगली जानवर पाए जाते हैं। हालांकि, नई परिभाषा के बाद भी टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क और वाइल्डलाइफ सेंचुरी के रूप में घोषित अरावली के इलाके पूरी तरह सुरक्षित हैं। वहां किसी भी तरह के खनन या निर्माण की अनुमति नहीं है।

ये थी नई परिभाषा

समिति ने अनुशंसा की थी कि 'अरावली पहाड़ी' की परिभाषा अरावली जिलों में स्थित ऐसी किसी भी भू-आकृति के रूप में की जाए, जिसकी ऊंचाई स्थानीय भू-स्तर से 100 मीटर या उससे अधिक हो। इसके अलावा 'अरावली श्रृंखला' एक-दूसरे से 500 मीटर के अंदर दो या अधिक ऐसी पहाड़ियों का संग्रह होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को प्रस्ताव में नई परिभाषा पर आदेश जारी किया था।

कब क्या हुआ

- **20 नवंबर 2025 :** सुप्रीम कोर्ट ने मंत्रालय की समिति की सिफारिश स्वीकार की।
- **16 दिसंबर :** नए अरावली अभियान से पूर्व संरक्षण प्रयास गहनता जुड़े।
- **20 दिसंबर :** अरावली बचाने के लिए उदयपुर में वकीलों ने प्रदर्शन किया।
- **25 दिसंबर :** केंद्र ने अरावली में नई खननों पर रोक लगाई।
- **27 दिसंबर :** अरावली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया।
- **29 दिसंबर :** सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश पर रोक लगाई।

सेंगर की सजा निलंबन के फैसले पर अदालत की रोक

सुनवाई 2

- सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा
- कोर्ट ने कहा, कई अहम प्रश्न विचारणीय हैं

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2017 के उन्नाव दुष्कर्म मामले में भाजपा से निष्कासित नेता कुलदीप सेंगर की उम्रकैद को निलंबित करने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी तथा न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की अवकाशकालीन पीठ ने सेंगर को नोटिस जारी कर सीबीआई की याचिका पर जवाब मांगा जिसमें हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। सीबीआई की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया। पीठ ने कहा कि वह इस मामले पर गौर करेगी।

पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट के 23 दिसंबर के आदेश पर सेंगर को हिरासत से रिहा नहीं किया जाएगा। पीठ ने कहा कि इस मामले में कानून के कई अहम प्रश्न विचारणीय हैं और मामले की सुनवाई चार सप्ताह बाद के लिए स्थगित कर दी।

हाईकोर्ट ने उन्नाव दुष्कर्म मामले में उम्रकैद काट रहे सेंगर की सजा को यह कहते हुए निलंबित कर दिया था कि वह पहले ही सात साल और पांच महीने जेल में बिता चुके हैं।

जेल में ही रहेंगे सेंगर : फिलहाल सेंगर जेल में ही रहेगा क्योंकि वह पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में 10 साल की सजा काट रहा है। दुष्कर्म और इससे जुड़े अन्य मामले अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उत्तर प्रदेश स्थित सिंगल अदालत से दिल्ली स्थानांतरित किए गए थे।

> गलती सब करते हैं P07

ऐलान: पूरे भारत में घुसपैठियों की पहचान करेंगे: अमित शाह

बोरदुवा (असम), एजेंसी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देशभर में बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। विपक्ष पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटबैंक मानती है।

गृह मंत्री शाह सोमवार को नागांव जिले में वैष्णव संत श्रीमंत शंकरदेव के जन्मस्थान बटाद्रवा थान में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिये असम के लोगों, उनकी संस्कृति, जमीन और पहचान के लिए खतरा हैं। इसके बावजूद कांग्रेस घुसपैठियों को वोट बैंक की खातिर संरक्षण देती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार न सिर्फ असम बल्कि पूरे भारत में बांग्लादेश से आकर रह रहे अवैध प्रवासियों की पहचान करेगी।

गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के लोगों की सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा सुनिश्चित की है। इसके साथ ही राज्य में चहुंमुखी विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया है।

असम के नागांव जिले में सोमवार को जनसभा के दौरान गृहमंत्री अमित शाह। • एजेंसी

शाह ने कहा कि हिमंत के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के कब्जों से एक लाख बीघा से अधिक जमीन से घुसपैठियों को हटाकर मुक्त किया जा चुका है। शाह ने अगले चुनाव में फिर भाजपा चुनने की अपील करते हुए कहा कि असम की घुसपैठियों से मुक्ति सुनिश्चित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को पांच साल और दें।

आफत : राजधानी में सुबह दृश्यता घटकर 50 मीटर रह गई थी

दिल्ली पर कोहरे, ठंड और प्रदूषण की मार

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली पर कोहरे, ठंड और प्रदूषण की तिहरी मार पड़ रही है। सोमवार सुबह घने कोहरे से दृश्यता घटकर 50 मीटर रह गई। मंगलवार को भी घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया।

मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 31 दिसंबर तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह स्थिति एक जनवरी तक बनी रह सकती है।

दिल्ली के सफदरजंग केंद्र में दिन का अधिकतम तापमान 20.3 डिग्री दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 0.1 डिग्री सेल्सियस कम है। रविवार की तुलना में इसमें 2.2 डिग्री की गिरावट आई है। न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। जो कि सामान्य से 1.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है।

पंजाब से बंगाल तक छाई कोहरे की चादर : कोहरे की चादर केवल दिल्ली में ही नहीं बल्कि पंजाब से लेकर बंगाल तक छाई हुई है। मौसम विभाग के पास मौजूद उपग्रह के चित्र बताते हैं कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश-ओडीशा के कुछ हिस्सों और पूर्वोत्तर के राज्यों में कोहरे की घनी चादर छाई हुई है। मंगलवार के दिन भी यह कोहरे की चादर बनी रहने की संभावना है।

गंभीर श्रेणी में पहुंची दिल्ली की हवा : दिल्ली में ठंड और कोहरे के साथ मिलकर प्रदूषण और घातक हो गया है। सोमवार को दिल्ली की वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच गई। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 401 दर्ज किया गया, एक दिन पहले यह 390 था। दिल्ली के दस इलाकों में वायु गुणवत्ता 400 अंक के पार दर्ज किया गया।

सोमवार सुबह करीब आठ बजे कुछ ऐसा था मेरठ एक्सप्रेसवे का हाल। • साकिब अली

कोहरे के कारण उड़ानें रद्द, ट्रेनें देरी से पहुंचीं

नई दिल्ली। दिल्ली में सोमवार को घने कोहरे से विमान और रेल सेवाएं प्रभावित रहीं। दृश्यता कम होने की वजह से कुल 130 विमानों को रद्द करना पड़ा। आठ विमानों को डायवर्ट किया गया और 200 विमानों ने देरी से उड़ान भरी। वहीं, दिल्ली में 100 रेलगाड़ियां देरी से पहुंचीं और तीन दर्जन देरी से रवाना हुईं।

130 उड़ानों को कोहरे के कारण रद्द करना पड़ा

135 रेलगाड़ियां देरी से आईं या रवाना हुईं

नए साल पर हो सकती है राहत की बारिश

दिल्ली वालों के लिए नया साल हल्की राहत लाने वाला साबित हो सकता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि एक पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से दिल्ली व आसपास के क्षेत्रों में एक जनवरी को हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इसके चलते तापमान में गिरावट होगी और गलन वाली सर्दी हो सकती है। जबकि, अगर बारिश का स्तर थोड़ा ज्यादा होता है और हवा की गति बढ़ती है तो दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति से भी कुछ हद तक राहत मिल सकती है।

संबंधित खबरें P05,06

चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल और गिरावट का संयोग

नई दिल्ली, एजेंसी। चांदी की कीमतों में सोमवार को भारी उतार-चढ़ाव आया। वायदा कारोबार में सुबह इसके दाम 2,54,174 रुपये प्रति किलोग्राम के सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंच गए। लेकिन दोपहर बाद जोरदार मुनाफावसूली होने से इसमें 24,474 रुपये की तेज गिरावट आई। इसके साथ ही चांदी 2,29,700 के निचले स्तर पर पहुंच गई।

गिरावट सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी कीमतों में उतार-चढ़ाव दिखा। हालांकि, वायदा करोबार में आई इस गिरावट का असर हाजिर बाजार (सर्राफा बाजार) पर नहीं पड़ा। व्यापारियों की लगातार खरीदारी के कारण दिल्ली में चांदी 3,650 रुपये बढ़कर 2,40,000 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। शुक्रवार को चांदी 2,36,350 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। विश्लेषकों का कहना है कि

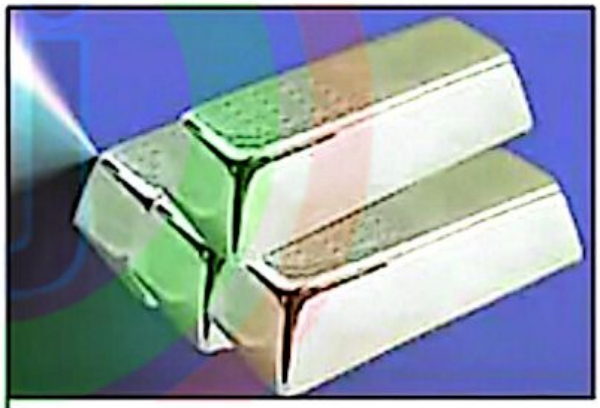

24 हजार रुपये से अधिक गिरावट दर्ज की गई

भर सकती है फर्राटा

चीन की सरकार निर्यात लाइसेंस को लेकर नियम लागू कर सकती है, जिससे चांदी का निर्यात सीमित हो सकता है। ऐसे में दुनियाभर में चांदी की किल्लत हो सकती है, जिससे इसकी कीमतों में तेज उछाल देखने को मिल सकता है।

वायदा-हाजिर में अंतर

वायदा में स्टॉक एक्सचेंज की तर्ज पर कमोडिटी एक्सचेंज में कारोबार होता है। अक्सर असली सोना-

अमेरिका संयुक्त राष्ट्र को केवल दो अरब डॉलर देगा

- पहले करीब 17 अरब डॉलर की मदद मिलती थी
- लाखों लोग भुखमरी का शिकार हो सकते हैं

जिनेवा, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की ओर से सोमवार को घोषणा की गई कि वह संयुक्त राष्ट्र मानवीय सहायता कार्यक्रम के लिए सिर्फ दो अरब डॉलर देगा की सहायता देगा।

ट्रंप प्रशासन बीते कुछ समय से संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न मानवीय कार्यक्रमों के लिए दी जाने वाली फंडिंग में भारी कटौती कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र के डाटा के अनुसार, हाल के वर्षों में अमेरिका द्वारा यूएन को सालाना करीब 17 अरब डॉलर की आर्थिक मदद दी जाती थी। इनमें से 8-10 अरब डॉलर तो अमेरिका द्वारा स्वैच्छिक योगदान के तौर पर दिए जाते थे और साथ ही अरबों डॉलर संयुक्त राष्ट्र सदस्यता की फीस के तौर पर दिए जाते थे। साथ ही अन्य पश्चिमी देशों ने भी संयुक्त राष्ट्र की फंडिंग में कटौती की है। इस कटौती का असर संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न मानवीय योजनाओं पर पड़ा है, जो फंडिंग से वित्तपोषित होती हैं।

कटौती करने के फैसले को लेकर आलोचकों का कहना है कि इससे लाखों लोग भुखमरी के शिकार हो सकते हैं और लाखों लोगों को विस्थापन और बीमारियां झेलनी पड़ सकती है।

साल की शुरुआत में सख्ती शुरू की थी : ट्रंप ने फरवरी में ऐलान किया था कि वह अमेरिकी सरकार की प्रमुख विदेशी सहायता एजेंसी यूएस एड को बंद करके उसे विदेश मंत्रालय में शामिल करेंगे।

केंद्रीय गृह मंत्रालय तैयार करवा रहा डेटा बेस, मुख्य जांच एजेंसियां समन्वय बना रहीं

एकीकृत डेटाबैंक से थमेगा अपराध

तैयारी

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। केंद्र सरकार आतंक और अपराध से निपटने के लिए डेटा बैंक की मजबूती पर जोर दे रही है। एजेंसियों से कहा गया है कि वे लगातार आतंक और अपराध से जुड़ा डेटा बेस अपडेट करें और नई जानकारियों को उपलब्ध डेटा में जोड़ते रहें। अधिकारियों ने बताया कि आने वाले वर्षों में आतंक और अपराध से जुड़े डेटाबेस में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसके माध्यम से डेटा विश्लेषण भी होगा।

अधिकारियों के अनुसार, अभी अपराध और आतंक की गतिविधि से जुड़े कई प्रकार के डेटा केंद्रीय स्तर पर अलग अलग तरीके से एकत्र किए जाते हैं। इसी तरह से कई राज्यों में भी डेटा संग्रह का काम किया जा रहा है। बताया कि हर राज्य से मिलने वाले इनपुट को केंद्रीय स्तर पर एकीकृत करने की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं, ताकि जब भी किसी राज्य पुलिस या एजेंसी को जरूरत हो वह इसका इस्तेमाल कर सके।

अधिकारियों ने बताया कि डेटा पर व्यापक स्तर पर काम हो रहा है। एनआईए की कॉन्फ्रेंस में जिस डेटाबेस का उद्घाटन गृहमंत्री अमित शाह ने किया था, वह भी इसी दिशा में बड़ा कदम है। यह डेटाबेस एआई से संचालित है, जिससे जांच अधिकारी संगठित अपराधियों के बारे में व्यापक जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। यह डेटाबेस सभी राज्यों से संगठित अपराधियों से संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर), आरोपपत्र, फाइलें और अन्य महत्वपूर्ण इनपुट को एकीकृत करता है, जिससे जांच एजेंसियों को वास्तविक समय में ये जानकारी उपलब्ध हो जाती है।

अपराधियों का आतंकियों से गठजोड़ चुनौती: अधिकारियों का कहना है कि संगठित अपराध नेटवर्क का आतंकी समूहों से गठजोड़ नई चुनौती पेश कर रहा है। इसलिए अपराधियों की पूरी अपराध कुंडली एजेंसियों के पास होना जरूरी है। इसे देखते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने राज्य पुलिस बलों और राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड (नैटग्रिड) के सहयोग से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क डेटाबेस (ओसीएनडी) तैयार किया है।

डेटाबेस में फिंगरप्रिंट और आवाज मिलान भी संभव: अधिकारियों ने बताया कि प्रोफाइल की जानकारी के अलावा, डेटाबेस में आवाज मिलान की सुविधा और संगठित अपराधियों का फिंगरप्रिंट डेटा भी मौजूद है। इससे जांच एजेंसियों को उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने में मदद मिलती है।

पहले फिंगरप्रिंट का डेटा अलग से जुटाया जाता था, जिसे अब नई व्यवस्था में एकीकृत किया गया है।

'एक डेटा, एक एंट्री' के तहत जिम्मेदारी: केंद्र सरकार 'एक डाटा, एक एंट्री' के सिद्धांत पर काम कर रही है। इसके तहत एनआईए को आतंकवादी मामलों से संबधित नेशनल डेटाबेस तैयार करना है। इसी तरह एनसीबी को नारकोटिक्स मामलों से संबधित नेशनल डेटाबेस बनाने की जिम्मेदारी मिली है।

ईडी को आर्थिक मामलों से संबधित डेटाबेस और एनसीआरबी को फिंगरप्रिंट डेटाबेस, नफीस एवं यौन अपराधियों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने की जिम्मेदारी दी गई है।

ऐसे काम करता है ओसीएनडी

- यह गृह मंत्रालय के तहत आतंकवाद विरोधी और आंतरिक सुरक्षा के लिए एक मास्टर डेटाबेस है
- यह एक एकीकृत डेटा-साझाकरण मंच है, जो कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियों का समर्थन करता है
- यह डेटाबेस एआई-संचालित है जो चैटजीपीटी की तरह काम करता है
- संगठित अपराधियों के बारे में सभी जानकारी संबंधित जांच अधिकारियों को तुरंत प्रदान करता है

राज्यों में भी हो रहीं महत्वपूर्ण पहल

1 हिमाचल में डीएनए आधारित डेटाबेस की शुरुआत की है, इससे जघन्य अपराधों की जांच के अलावा अज्ञात शव की पहचान और गुमशुदा व्यक्तियों की तलाश में भी मदद मिलेगी, इसका सॉफ्टवेयर अमेरिका से मंगाया गया था

2 महाराष्ट्र में ऑटोमेटेड मल्टी मॉडल बायोमेट्रिक आइडेंटीफिकेशन सिस्टम (एएमबीआईएस) के तहत फिंगरप्रिंट,फोटोग्राफ और रेटिना स्कैन डेटा संरक्षित करने से सुरक्षा एजेंसियों को जांच में खसी मदद मिल रही है

नसों और टैटू की पहचान भी होगी

अधिकारियों ने बताया कि अपराध और अपराधियों के डेटाबेस को अंतरराष्ट्रीय मानकों तक ले जाने का प्रयास जारी है। हार्ड बायोमैट्रिक्स पर भी काम चल रहा है। इसके तहत हाथ की नसों, टैटू आदि के जरिए भी पहचान संभव हो सकेगी। इसके अलावा भगोड़े अपराधियों, संदिग्ध अपराधियों, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकी संगठनों और व्यक्तियों के डेटा पर भी अलग अलग एजेंसियां काम कर रही हैं।

रिपोर्ट : औद्योगिक उत्पादन दो साल की नई ऊंचाई पर पहुंचा

नई दिल्ली, एजेंसी। खनन और विनिर्माण क्षेत्रों के मजबूत प्रदर्शन से नवंबर महीने में देश के औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि दर दो साल के उच्च स्तर 6.7 प्रतिशत पर पहुंच गई।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के मुताबिक, औद्योगिक उत्पादन को मापने वाला औद्योगिक उत्पादन सूचकांक नवंबर, 2024 में पांच प्रतिशत बढ़ा था। इससे पहले औद्योगिक उत्पादन का उच्च स्तर नवंबर, 2023 में 11.9 प्रतिशत दर्ज किया गया था।

त्योहारों से पहले कई उपभोक्ता वस्तुओं पर जीएसटी की दरों में 22 सितंबर 2025 से कटौती की गई थी। इससे जीएसटी दरों में कमी का लाभ उठाने के लिए विनिर्माण ऑर्डरों में तेजी आई। इसके साथ एनएसओ ने अक्तूबर 2025 के लिए औद्योगिक उत्पादन वृद्धि के आंकड़े को भी संशोधित कर 0.5 किया गया है।

औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी का आम लोगों पर असर

औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी का मतलब है कि अर्थव्यवस्था की सेहत बेहतर हो रही है। इसका सीधा लाभ नौकरी, आय, व्यापार और सरकारी सेवाओं के जरिए आम आदमी तक पहुंचता है। हालांकि इसका पूरा असर दिखने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन संकेत सकारात्मक माने जाते हैं।

1 रोजगार के अवसर बढ़ेंगे

जब फैक्ट्रियां और उद्योग ज्यादा उत्पादन करते हैं, तो उन्हें अधिक मजदूर, तकनीशियन और कर्मचारियों की जरूरत होती है। नए रोजगार पैदा हो सकते हैं।

2 आमदनी में सुधार

उद्योगों की स्थिति बेहतर होने पर वेतन में वृद्धि, ओवरटाइम और बोनस मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इससे लोगों की खरीदने की ताकत सुधरती है।

3 सुविधाएं और बेहतर होंगी

उद्योगों के अच्छे प्रदर्शन से कर संग्रह बढ़ता है। सरकार के पास शिक्षा, स्वास्थ्य पर खर्च के लिए ज्यादा संसाधन होते हैं, जिसका फायदा लोगों को मिलता है।

4 महंगाई पर मिला-जुला असर

ज्यादा उत्पादन से वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ती है, जिससे दाम स्थिर रह सकते हैं। यदि कच्चा माल महंगा है या ब्याज दरें ऊंची हैं, तो महंगाई पूरी तरह कम होना जरूरी नहीं।

5 छोटे कारोबारों को सहारा

बड़े उद्योगों की रफ्तार बढ़ने से छोटे उद्योगों, ट्रांसपोर्ट, पैकेजिंग और सप्लाई चेन को भी काम मिलता है। इससे स्थानीय कारोबार को फायदा होता है।

6 शेयर बाजार, निवेश पर असर

उत्पादन में तेजी से बाजार में भरोसा बढ़ता है। म्यूचुअल फंड और शेयर में निवेश करने वालों को फायदा हो सकता है। हालांकि, असर हर व्यक्ति पर एक जैसा नहीं होता।

उपलब्धि | भूटान के युवा गेंदबाज ने म्यांमार के खिलाफ तीसरे मैच में हासिल की उपलब्धि, मलेशिया के स्याजरुल का रिकॉर्ड तोड़ा

टी-20 में आठ विकेट लेकर सोनम ने बनाया विश्व रिकॉर्ड

नई दिल्ली, एजेंसी। भूटान के युवा स्पिनर सोनम येशे ने पुरुषों के टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा लिया है। वह एक मैच में आठ विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज (पुरुष या महिला) बन गए हैं।

बड़ी जीत दिलाई : बाएं हाथ के स्पिनर सोनम ने 26 दिसंबर को भूटान के गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी में म्यांमार के खिलाफ तीसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले के दौरान यह उपलब्धि हासिल की। इस 22 वर्षीय गेंदबाज ने सात रन देकर आठ विकेट लिए जिससे भूटान ने म्यांमार को 45 रन पर आउट कर दिया।

इससे पहले भूटान ने नौ विकेट पर 127 रन बनाए थे। इस तरह से भूटान ने 82 रन से बड़ी जीत हासिल की।

भूटान क्रिकेट ने एक्स पर पोस्ट किया, एक यादगार स्पेल। सोनम येशे ने अविश्वसनीय प्रदर्शन करके चार ओवर में सात रन देकर आठ विकेट लिए और इस तरह से नया विश्व रिकॉर्ड बनाया।

येशे हालांकि अगले मैच में सोमवार को सिर्फ एक विकेट ही ले सके। अब तक उनके नाम 35 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में 38 विकेट दर्ज हो चुके हैं।

इद्रस ने लिए थे सात विकेट : अभी तक किसी भी गेंदबाज ने किसी भी तरह के टी-20 मैच में आठ विकेट लेने का कारनामा नहीं किया था। इससे पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का रिकॉर्ड मलेशिया के तेज गेंदबाज स्याजरुल इद्रस के नाम था। इनके अलावा बहरीन के अली दाऊद ही एकमात्र ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में सात विकेट लिए हैं।

ये तीन रिकॉर्डधारी

सोनम येशे (भूटान)
8 विकेट, 7 रन-बनाम म्यांमा (2025)

स्याजरुल इद्रस (मलेशिया)
7 विकेट, 8 रन-बनाम चीन (2023)

अली दाऊद (बहरीन)
7 विकेट, 19 रन-बनाम भूटान (2025)

- येशे ने जुलाई 2022 में मलेशिया के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय पदार्पण किया था। पहले ही मुकाबले में उन्होंने प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए 16 रन पर तीन विकेट झटक लिए।

इन दोनों के नाम भी उपलब्धि : अगर टी-20 मैचों की बात करें तो नीदरलैंड्स के ऑलराउंडर कॉलिन एकरमैन ने 2019 में लीसेस्टरशर की तरफ से बर्मिंघम बियर्स के खिलाफ 18 रन देकर सात विकेट जबकि बांग्लादेश के तेज गेंदबाज तस्कीन अहमद ने इस साल के शुरू में दरबार राजशाही के लिए खेलते हुए ढाका कैपिटल्स के खिलाफ 19 रन देकर सात विकेट चटकाए थे।

■ ध्रुव ने महज 101 गेंद पर 160 रन ठोके ■ दिल्ली की जीत, पर ऋषभ पंत नाकाम ■ अभिषेक शर्मा नहीं चले, पंजाब की हार

जुरेल के जोरदार सैकड़े से यूपी विजयी

विजय हजारे ट्रॉफी

राजकोट, एजेंसी। भारतीय वनडे टीम के बैकअप विकेटकीपर को लेकर खासतौर पर है। ईशान किशन की वापसी फिर चर्चा में है और ऋषभ पंत को मौजूदा भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच ध्रुव जुरेल ने विजय हजारे ट्रॉफी में 101 गेंदों पर नाबाद 160 रन ठोककर ऐसी दस्तक दी, जिसे किसी पैरवी की जरूरत नहीं।

प्लेयर ऑफ द मैच जुरेल की शानदार पारी की बदौलत उत्तर प्रदेश ने सात विकेट पर 369 रन बनाए और बड़ौदा को 54 रन से शिकस्त दी। जुरेल का यह विजय हजारे ट्रॉफी में पहला शतक है। कप्तान रिंकू सिंह ने भी जुरेल का बेहतरीन साथ दिया। उन्होंने 67 गेंदों पर 63 रन बनाए। एक समय यूपी ने 92 रन पर तीन विकेट गंवा दिए थे। तब जुरेल और रिंकू ने चौथे विकेट के लिए 131 रनों की साझेदारी कर बड़े स्कोर की नींव रख दी। 39वें ओवर में रविंद्र सलाम ने रिंकू सिंह को आउट कर इस साझेदारी का अंत किया। इसके बाद जुरेल ने निचले क्रम के बल्लेबाज प्रशांत के साथ मिलकर छठे विकेट के लिए 122 रन की साझेदारी यूपी के सलामी बल्लेबाज अभिषेक गोस्वामी ने भी अर्धशतक (51) लगाया।

बाद में बल्लेबाजी करने उतरी बड़ौदा की पूरी टीम निर्धारित 50 ओवरों में 315 रन का स्कोर ही बना सकी। बड़ौदा के लिए कप्तान कृणाल पांड्या ने सर्वाधिक 82 रनों की पारी खेली। इसके अलावा शाश्वत रावत (60) ने अर्धशतक लगाया। अन्य बल्लेबाजों में विष्णु सोलंकी (43), अतीत सेठ (46), शिवालिक शर्मा (30) ही कुछ संघर्ष कर सके। चार बल्लेबाज दहाई आंकड़े तक नहीं पहुंचे।

उत्तर प्रदेश के लिए जीशान अंसारी ने तीन विकेट लिए। समीर रिजवी और अभिजय निगम को दो-दो विकेट मिले। इस जीत से टीम तीन मैचों में 12 अंक के साथ तालिका में शीर्ष पर पहुंच गयी जबकि जम्मू कश्मीर, विदर्भ, यूपी और बंगाल की टीमों के नाम आठ-आठ अंक हैं।

ध्रुव की यादगार पारी

160* रन | 101 गेंदें | 15 चौके | 8 छक्के | 158.41 स्ट्राइक रेट

पारी की रफ्तार

जुरेल 45वें ओवर में बल्लेबाजी करने उतरे। तब टीम स्कोर 77/1 था। इसके बाद ध्रुव पारी की रफ्तार बढ़ाते गए-

- 50 रन : 42 गेंदों में
- 50 से 100 : 36 गेंदों में
- 100 से 150 : सिर्फ 19 गेंद

रिकॉर्ड बुक में शामिल

पहला लिस्ट-ए शतक
- उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर (लिस्ट-ए)
- 100 से 150 के बीच सबसे कम गेंदों में पहुंचे जो किसी भारतीय विकेटकीपर का लिस्ट-ए क्रिकेट में रिकॉर्ड है।

पिछला कीर्तिमान
159 अर्जुन यादव (2022 बनाम महाराष्ट्र)

158* माधव डोरिक (2021 बनाम मुंबई)

साझेदारी
131 रन रिंकू सिंह के साथ
6.55 रन रेट प्रति ओवर

फॉर्म मीटर
विजय हजारे ट्रॉफी में ध्रुव की पिछली पारियां: 80, 67
भारत-ए के लिए दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो शतक (फर्स्ट क्लास)

हरियाणा ने गुजरात को पीटा

हरियाणा ने गुजरात को 26 रन से हराया। हरियाणा पहले बल्लेबाजी करते हुए 299 रन पर सिमट गई। जवाब में गुजरात की टीम भी 273 रन पर ढेर हो गई।

पंजाब से जीता उत्तराखंड

अभिषेक शर्मा, हर्षिमरन जैसे बल्लेबाजों के बावजूद पंजाब को उत्तराखंड ने पांच विकेट से मात दे दी। पंजाब ने आठ विकेट पर 269 रन बनाए। उत्तराखंड ने 48वें ओवर में लक्ष्य पा लिया।

शार्दुल-मुलानी ने मुंबई को जिताया

जयपुर, एजेंसी। शार्दुल ठाकुर और शम्स मुलानी की घातक गेंदबाजी के बाद अंगकृष रघुवंशी और सिद्धेश लाड की संयमित बल्लेबाजी से मुंबई ने विजय हजारे ट्रॉफी एलीट ग्रुप-सी मुकाबले में छत्तीसगढ़ को नौ विकेट से हरा दिया। टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनने वाली मुंबई ने शार्दुल (चार विकेट) और मुलानी (पांच विकेट) के दम पर छत्तीसगढ़ को 38.1 ओवर में 142 रन पर समेट दिया। जवाब में मुंबई ने 24 ओवर में एक विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। अंगकृष 68 व लाड 48 रन बनाकर नाबाद रहे।

हिमांशु की पारी से जीता मध्यप्रदेश

अहमदाबाद, एजेंसी। हिमांशु मंत्री की शानदार पारी और गेंदबाजों के संयुक्त प्रयास से मध्यप्रदेश ने विजय हजारे ट्रॉफी एलीट ग्रुप-ए मैच में केरल को 47 रन से शिकस्त दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए मध्यप्रदेश 214 रन पर सिमट गया, जिसमें मंत्री ने 93 रन की अहम पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करने उतरी केरल की टीम मध्यप्रदेश के गेंदबाजी आक्रमण के सामने 167 रन पर ढेर हो गई। शुभम शर्मा ने तीन विकेट लिए, जबकि सरांश जैन और शिवांग कुमार को दो-दो सफलता मिली।

रेलवे के खिलाफ मुकाबले में भी खेलेंगे विराट कोहली

विराट कोहली

नई दिल्ली, एजेंसी। दिग्गज भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली छठे जनवरी को बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई उत्कृष्टता केंद्र में रेलवे के खिलाफ दिल्ली की ओर से विजय हजारे ट्रॉफी का मुकाबला खेलेंगे। यह जानकारी दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) के अध्यक्ष रोहन जेटली ने सोमवार को दी।

उन्होंने कहा कि कोहली ने टूर्नामेंट में तीन मैच खेलने की उपलब्धता जताई है। बीसीसीआई ने केंद्रीय अनुबंधित खिलाड़ियों के लिए विजय हजारे ट्रॉफी के कम से कम दो मैच खेलना अनिवार्य किया है, हालांकि कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी घरेलू वनडे श्रृंखला की तैयारी के लिए तीसरा मुकाबला भी खेलना चाहते हैं। जेटली ने कहा, 'फिलहाल वह खेल रहे हैं और तीन मैचों के लिए उपलब्ध हैं।'

कोहली ने दिल्ली के लिए शुरुआती दो मुकाबलों में शानदार फॉर्म दिखाई थी। उन्होंने क्रमशः 131 और 77 रन बनाए। इसी दौरान उन्होंने लिस्ट-ए क्रिकेट में सबसे कम पारियों में 16,000 रन पूरे करने का रिकॉर्ड भी बनाया। कोहली ने यह उपलब्धि 330वीं पारी में हासिल कर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 391 पारियों में यह मुकाम पाया था। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज 11 जनवरी से शुरू होगी।

दिल्ली की जीत में प्रियांश आर्य और तेजस्वी चमके

बेंगलुरु, एजेंसी। सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्य और तेजस्वी दहिया के आक्रामक अर्धशतकों की बदौलत दिल्ली ने विजय हजारे ट्रॉफी ग्रुप-डी मुकाबले में सौराष्ट्र को तीन विकेट से हरा दिया।

321 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली ने 48.5 ओवर में सात विकेट खोकर जीत दर्ज की। विराट कोहली की गैरमौजूदगी और कप्तान ऋषभ पंत की साधारण पारी के बावजूद दिल्ली ने दबाव में संयम नहीं खोया।

प्रियांश ने 45 गेंदों पर 78 रन बनाकर लक्ष्य का आधार रखा, जबकि तेजस्वी ने 51 गेंदों में 53 रन की उपयोगी पारी खेली। हालांकि ऋषभ पंत 26 गेंदों पर महज 22 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन तेजस्वी ने मध्यक्रम को संभाले रखा। अंत में हर्ष त्यागी (49) और नवदीप सैनी (नाबाद 34) की अहम साझेदारी ने दिल्ली को जीत की दहलीज पार कराई। दोनों ने अंतिम ओवरों में बाकी रन बल्लेबाजी की।

इससे पहले सौराष्ट्र ने विश्वराज सिंह जडेजा (115) व रुचित अहिर (नाबाद 95) की पारियों से सात विकेट पर 320 रन बनाए। गेंदबाजी में दिल्ली के लिए सैनी ने तीन विकेट लिए। इस जीत से दिल्ली तीन मैचों में 12 अंकों के साथ ग्रुप-डी में शीर्ष पर पहुंच गई।

उम्मीदें 2026

साल 2026 बैंकिंग, वेतन, डिजिटल भुगतान और आम उपभोक्ता से जुड़े कई अहम नियम बदलाव लेकर आ रहा है। इन बदलावों का असर सीधे हमारी जिंदगी और खर्च की योजना पर दिखेगा। सबसे बड़ा बदलाव 8वें वेतन आयोग को लेकर होने जा रहा है। इससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारियों की मासिक आय में बदलाव होगा।

नए साल में बैंकिंग, डिजिटल भुगतान के नियम बदलेंगे

1. आठवां वेतन आयोग प्रभावी होगा

सरकार जल्द ही छठा वेतन आयोग लागू करने वाली है। उम्मीद लगाई जा रही है कि छठा वेतन आयोग एक जनवरी 2026 से प्रभावी हो जाएगा। हालांकि, लागू होने में समय लग सकता है। इसके बाद वेतन, पेंशन और भत्तों में अहम संशोधन हो सकते हैं। वेतन कितना बढ़ सकता है, इसका आधिकारिक आकड़ा अभी तय नहीं है। लेकिन शुरुआती अनुमानों के मुताबिक 20-35% तक बढ़ोतरी संभव मानी जा रही है।

2. आधार-पैन लिंकिंग

आधार को पैन से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है। जो लोग तय तिथि तक लिंक नहीं करेंगे, उनका पैन कार्ड एक जनवरी से निष्क्रिय हो जाएगा। फिर जुर्माना देकर इसे लिंक करना होगा। लिंक न होने की स्थिति में खाते से जुड़ी सुविधाएं रुक सकती हैं।

3. वाहनों के दाम में वृद्धि

एक जनवरी 2025 से कई कंपनियां अपने वाहनों की कीमत में बढ़ोतरी करने वाली हैं। इन कंपनियों में निसान, वीएमडब्लू, एमजी मोटर और रेनॉल्ट जैसी कंपनियां शामिल हैं। अन्य कार निर्माता कंपनी भी अपने वाहनों की कीमत में बढ़ोतरी कर सकती हैं।

4. क्रेडिट स्कोर का अपडेट अब तेज

क्रेडिट स्कोर के अपडेट की रफ्तार बढ़ाई जा रही है। जहां पहले यह अपडेट 15 दिन में होता था, वहीं अब हर हफ्ते स्कोर अपडेट होगा। समय पर किस्त चुकाने का फायदा जल्दी दिखेगा और कर्ज की स्वीकृति की प्रक्रिया ज्यादा सटीक होगी।

5. सीएनजी-पीएनजी सस्ती होने की संभावना

यूनिफाइड टैरिफ सिस्टम में बदलाव का असर गैस कीमतों पर दिख सकता है। खाते के मुताबिक सीएनजी ₹1.25 से ₹2.50 प्रति किलो तक सस्ती हो सकती है। वहीं, पीएनजी में ₹0.90 से ₹1.80 सस्ते तक की राहत संभव है। इसका सीधा फायदा उपभोक्ताओं को मिलेगा।

6. यूपीआई और डिजिटल भुगतान के कड़े नियम

डिजिटल धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए यूपीआई, मोबाइल नंबर और बैंक खाते से जुड़े नियम सख्त होंगे। सिम सत्यापन और डिजिटल पहचान पर खास जोर रहेगा, जिससे ऑनलाइन फ्रॉड के मामलों में कमी आएगी।

7. लोन पर राहत, एफडी, छोटी बचत के नियमों में फेरबदल

नए साल की शुरुआत के साथ कई बड़े बैंकों ने कर्ज की ब्याज दरों में कमी के संकेत दिए हैं। इससे होम लोन और पर्सनल लोन लेना अपेक्षाकृत सस्ता हो सकता है। दूसरी ओर, फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों में भी बदलाव होंगे। इसके अलावा सरकार एक जनवरी से छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में भी बदलाव कर सकती है। ये दरें तिमाही आधार पर रिवाइज होती हैं।

केंद्र ने 79 हजार करोड़ की रक्षा खरीद को दी मंजूरी

नई दिल्ली, एजेंसी। रक्षा मंत्रालय ने तीनों सेनाओं की युद्धक क्षमता बढ़ाने के लिए 79 हजार करोड़ के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरीदी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने लंबी दूरी की मिसाइलों, रडार और अन्य आधुनिक उपकरणों की खरीद के लिए यह मंजूरी दी है।

सोमवार को रक्षा मंत्रालय बताया गया कि डीएसी ने सेना के लिए मिलिटरी प्लेटफार्म, आर्टिलरी रेजिमेंट के लिए लोइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी है। इनके अलावा पिनाका रॉकेट सिस्टम के लिए लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट, गोला-बारूद की खरीद को भी स्वीकृति दी गई है। एमके-2 प्रणाली सामरिक युद्ध क्षेत्र और अंदरूनी इलाकों में सेना की महत्वपूर्ण संपत्तियों की रक्षा के लिए तैनात होगी।

मानवरहित हवाई खतरों का पता लगाना आसान होगा : सेना के लिए खरीदे जा रहे लोइटरिंग म्यूनिशन का इस्तेमाल सामरिक लक्ष्यों पर सटीक हमले में किया जाएगा। वहीं, लो लेवल रडारों की मदद से कम ऊंचाई पर उड़ने वाले और छोटे मानवरहित हवाई खतरों का पता लगाना आसान होगा।

सेना को यह मिलेगा

- लंबी दूरी तक मार करने वाले गाइडेड रॉकेट
- इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन प्रणाली
- एमके-2 इंटरडिक्शन सिस्टम

नौसेना के लिए यह मंजूर

- हाई फ्रीक्वेंसी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो (एचएफ एसडीआर) मैनपैक
- हाई एल्टीट्यूड लॉग रेंज (हेल) रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम (आरपीएएस)

वायुसेना को ये मिलेंगे

- ऑटोमेटिक टेकऑफ लैंडिंग रिकॉर्डिंग सिस्टम
- एस्ट्रा एमके-2 मिसाइलें
- फुल मिशन सिमुलेटर, स्पाइस - 1000 लॉग रेंज गाइडेंस किट

'सार्वजनिक उपक्रमों में पूर्व सैनिकों की भर्ती की जाए'

मांग

नई दिल्ली, एजेंसी। रक्षा मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने इस बात पर चिंता जताई है कि पूर्व सैनिकों को सरकारी नौकरियों में नियमानुसार वरीयता नहीं मिल रही है। नेता विपक्ष और समिति सदस्य राहुल गांधी ने पूर्व सैनिकों के इलाज में होने वाली समस्याओं का मुद्दा रखा।

सोमवार को सांसद राधामोहन सिंह की अध्यक्षता वाली समिति में पूर्व सैनिकों के लिए पुनर्वास नीतियों, स्वास्थ्य सुविधाओं पर चर्चा हुई। इस दौरान सदस्यों ने कहा कि सरकारी नौकरियों में 10 से 25 प्रतिशत पूर्व सैनिकों को भर्ती करने का प्रावधान है। इसके बावजूद महज 1.9 प्रतिशत ही पूर्व सैनिकों को नौकरी मिल रही है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि पूर्व सैनिकों को प्राइवेट अस्पतालों में रेफर किए जाने पर उन्हें इलाज और एडमिशन में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

गंभीर रोगों के लिए सिर्फ 75 हजार मिल रहे: राहुल गांधी ने कहा कि पूर्व सैनिकों को कैंसर और किडनी

देश के 741 जिलों में लागू है मनरेगा: मंत्रालय

बैठक के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से प्रजेंटेशन में बताया गया कि दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर मनरेगा अभी 741 जिलों में लागू है। 2.69 लाख ग्राम पंचायतों में 57 प्रतिशत महिलाओं के साथ 12 करोड़ से अधिक सक्रिय कार्मिक इसमें जुड़े हुए हैं। कुल मिलाकर 15 करोड़ से अधिक परिवार और 26 करोड़ लाभार्थी मनरेगा में शामिल हैं। समिति अध्यक्ष उलका ने बताया कि सदस्यों ने मनरेगा और वीबी जी राम जी के विभिन्न पहलुओं पर बात की। चर्चा हुई कि अगले छह माह में आगे कैसे बढ़ना है।

कैसे संभव है और सुझाव दिया कि इस सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए।

वीबी जी राम जी को लागू करने पर विमर्श: एक अन्य बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति ने अगले छह माह में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (वीबी जी राम जी) को लागू करने पर विमर्श किया। कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उलका की अध्यक्षता

अमेरिकी राष्ट्रपति बोले- वार्ता कठिन, विफल होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता

रूस और यूक्रेन शांति समझौते के करीब: ट्रंप

रूस यूक्रेन युद्ध

पाम बीच, एजेंसी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के साथ हुई बैठक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार देर शाम कहा कि रूस-यूक्रेन शांति समझौते के बेहद करीब हैं। दोनों के बीच युद्ध रुकने की इतनी अच्छी स्थिति पहले नहीं बन पाई थी।

ट्रंप ने कहा, दोनों देश समझौते के करीब पहुंच रहे हैं। हालांकि, यह बहुत जटिल मुद्दा है, लेकिन मुझे उम्मीद है इसका समाधान निकलेगा। ट्रंप ने यह भी माना, वार्ता आसान नहीं है और टूट भी सकती है। ऐसा होने पर युद्ध सालों लंबा खिंच सकता है। कहा, जेलेंस्की संग बैठक से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उनकी फोन पर ढाई घंटे बहुत अच्छी वार्ता हुई। दोनों नेताओं ने यूरोप के कई नेताओं से फोन पर बात की, जिनमें यूई की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी के नेता शामिल थे।

फ्लोरिडा में रविवार रात शांति समझौते को लेकर हुई बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी समकक्ष वोलोदिमिर जेलेंस्की। • एएफपी

जेलेंस्की ने मांगी 50 साल की सुरक्षा गारंटी

यूक्रेन युद्धविराम को लेकर फ्लोरिडा में रविवार को ट्रंप के साथ बैठक के बाद सोमवार को यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने बातचीत का विवरण साझा किया। उन्होंने ट्रंप से देश की सुरक्षा की 50 साल की गारंटी मांगी। जेलेंस्की ने सोमवार को बताया, ट्रंप ने उन्हें 20 सूत्रीय शांति प्रस्ताव के बारे में जानकारी दी, जिसकी चर्चा ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ की थी। जेलेंस्की ने स्पष्ट किया, रूस के साथ कोई बातचीत तभी संभव है जब राष्ट्रपति ट्रंप और यूरोपीय नेता दस्तावेजों पर सहमति बनाएं।

कई जटिल मुद्दों पर अब भी मामला अटका

बैठक के बाद ट्रंप-जेलेंस्की ने संयुक्त पत्रकार वार्ता में कहा कि कई जटिल मुद्दे अब भी बाकी हैं जिनमें यह प्रश्न भी शामिल है कि रूस के कब्जे वाले यूक्रेनी क्षेत्रों का क्या होगा और यूक्रेन के लिए ऐसे सुरक्षा आश्वासन कैसे सुनिश्चित किए जाएं कि भविष्य में उस पर फिर हमला न हो। जेलेंस्की ने ट्रंप के प्रयासों के लिए उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा, यूक्रेन शांति के लिए तैयार है।

रूस बोला, अमेरिका ने की फोन वार्ता की पहल

मॉस्को। ट्रंप द्वारा पुतिन से वार्ता को लेकर रूस ने कहा कि फोन वार्ता की पहल अमेरिका की ओर से हुई है। पुतिन के विदेश मामलों के सलाहकार यूरी उशाकोव ने कहा कि बातचीत मैत्रीपूर्ण, सद्भावनापूर्ण और काम-काज संबंधी रही। ट्रंप और पुतिन ने जेलेंस्की से ट्रंप की मुलाकात के बाद शीघ्र फिर बात करने पर सहमति जताई।

रूस ने रातभर हमले किए

कीव। फ्लोरिडा में रविवार रात जब ट्रंप और जेलेंस्की युद्धविराम को लेकर वार्ता कर रहे थे, उस समय रूस ने यूक्रेन के दोनेत्सक में रातभर हमले किए। रूस ने इस क्षेत्र के कई जिलों को निशाना बनाया, जिससे 100 से ज्यादा घरों को क्षति पहुंची। हमले में तीन लोगों की मौत हुई है।

यक्ष एप पुलिस अफसरों-थानेदारों पर भी रखेगा नजर

■ विधि सिंह

लखनऊ। पुलिस मंथन में लांच 'यक्ष एप' सिर्फ अपराधियों पर ही नहीं बल्कि जिलों में तैनात पुलिस अफसरों, थानेदारों व बीट सिपाही पर भी नजर रखेगा। किसी जिले में अगर थाना व बीट स्तर पर गैंगस्टर, हिस्ट्रीशीटर और अन्य अपराधियों का डाटा समय से नहीं फीड किया जा रहा या बीट सत्यापन में लापरवाही हो रही है, तो इसका अलर्ट एसटीएफ मुख्यालय के अलावा बड़े अफसरों तक भी पहुंचेगा। अलर्ट पर संबंधित पुलिसकर्मी को एक चेतावनी दी जाएगी। लापरवाही पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

यक्ष एप का कंट्रोल रूम एसटीएफ मुख्यालय में काम करने लगा है। इसमें तैनात पुलिसकर्मियों को विशेष ट्रेनिंग दी गई है। इससे प्रदेश के सभी 75 जिलों से डाटा फीडिंग पर निगरानी रखी जा रही है। इसमें कोई भी दिक्कत आने पर जिलों के पुलिसकर्मियों को ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है। इस एप का लोकार्पण 27 दिसंबर को मुख्यमंत्री ने पुलिस मुख्यालय में किया था। डीजीपी राजीव कृष्ण और एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने इस एप का पूरा परीक्षण करने के बाद इसे तैयार किया है।

सांकेतिक इमेज

दिखेगा पूरा ब्योरा

सीसीटीएनएस पर मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस जब भी चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करेगी, उससे जुड़े अपराधी का पूरा ब्योरा एप पर दिखने लगेगा। इससे जानकारियां अपडेट हो सकेंगी।

कोई भी भाषा समझ सकेगा

किसी अपराधी की आवाज का नमूना लिया जाता है और उसकी उसका मेल पहले से फीड आवाज से हो जाता है तो तुरन्त इस बारे में पता चल जाएगा। खास बात यह है कि दुनिया की किसी भी भाषा में अपराधी बोले, यक्ष एप उसका मिलान कर लेगा।

पुलिस की कार्यप्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन होगा

- थानों की बीट व्यवस्था पहले से मजबूत होगी
- जिला बदर, वांछित अपराधियों का हर अपडेट मिलता रहेगा
- सजायाफ्ता अपराधियों की लगातार निगरानी
- एआई आधारित फेस रिकग्निशन से संदिग्ध अपराधियों की पहचान
- क्राइम जीपीटी से अपराध संबंधी हर डाटा का विश्लेषण
- अपराध से जुड़े प्रश्न साधारण भाषा में पूछने की सुविधा
- जघन्य वारदात पर संदिग्ध अपराधियों का तुरन्त ब्योरा स्क्रीन पर होगा

पुलिस प्रगति एक क्लिक पर

यक्ष एप कंट्रोल रूम का नोडल अधिकारी एसटीएफ के डिप्टी एसपी दीपक कुमार सिंह को बनाया गया है। नोडल अधिकारी के मुताबिक कंप्यूटर की स्क्रीन पर किसी भी जिले का अपडेट लिया जा सकता है। जिले का नाम सेलेक्ट करते ही वहां से फीड हर डाटा स्क्रीन पर दिख जाएगा। अगर किसी बीट सिपाही या थानेदार ने कोई जानकारी देने में देरी की है, तो उसका अलर्ट आ जाता है। साथ ही अपराधियों से जुड़े किस कॉलम में सूचना पूरी नहीं दी गई है, यह भी फ्लैश होने लगता है। संदिग्ध अपराधियों के फोटो कॉलम में कौन सी फोटो लोड हो रही है, यह भी दिखाई पड़ता है।

यूपी के कई मंत्रियों की नींद उड़ी, कुर्सी बचाने के लिए दिल्ली की दौड़

योगी मंत्रिमंडल में नए वर्ष पर बड़े बदलाव की अटकलें

फेरबदल

लखनऊ, विशेष संवाददाता। यूपी भाजपा अध्यक्ष के पद पर पंकज चौधरी की ताजपोशी के बाद अब सबकी निगाहें योगी मंत्रिमंडल के विस्तार पर है। चर्चाओं का बाजार गर्म है। वह भी कई तरह की। एक ये कि क्या गुजरात का प्रयोग यूपी में भी दोहराया जाएगा। इसी चर्चा ने तमाम मंत्रियों की नींद उड़ा दी है, तो बहुतों की उम्मीदों को पंख लगा दिए हैं। कुर्सी बचाने और पाने की चाहत वालों ने दौड़ शुरू कर दी है। संभावना जताई जा रही है कि टीम योगी में यह बदलाव फरवरी माह में हो सकता है। नये साल के आगाज के साथ ही भाजपा यूपी में मिशन-2027 की तैयारियां और तेज कर देगी। संगठन से लेकर सरकार तक सबकुछ दुरुस्त करने की तैयारी है।

गुजरात जैसा प्रयोग दोहराए जाने की चर्चा से बेचैनी

54 मंत्री वर्तमान में योगी मंत्रिमंडल में हैं जबकि 60 हो सकते हैं

- फरवरी में टीम योगी में हो सकता है बड़ा बदलाव
- कुर्सी बचाने व पाने के लिए दिल्ली दौड़ व अनुष्ठान चालू

पिछले विधानसभा चुनाव से पहले बदलाव हुआ था

अब बारी सरकार में बदलाव की है। 2022 के विधानसभा चुनाव में जाने से कुछ माह पहले भी मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था। जातीय गुणा-गणित के तहत कई चेहरों को टीम योगी में शामिल किया गया था। मगर इस बार चर्चाएं थोड़ी अलग है। दरअसल प्रदेश सरकार में कई मंत्रियों के कामकाज को लेकर तमाम शिकायतें हैं। कुछ से दिल्ली दरबार खुश नहीं है, तो कइयों की कार्यशैली से मुख्यमंत्री नाराज हैं।

खुल सकती है कई विधायकों की लाटरी

ऐसे में चर्चाएं योगी मंत्रिमंडल में बड़े बदलाव को लेकर है। ऐसा यदि हुआ तो तमाम विधायकों की लाटरी खुल सकती है। इसी चर्चा से कई मंत्री बेचैन हैं। ज्योतिषी से समय दिखवाने के साथ ही अनुष्ठान भी शुरू करा दिए गए हैं। कई विधायकों ने भी पूजा-पाठ शुरू करा दिए हैं। एक और चर्चा किसी दलित को तीसरा डिप्टी सीएम बनाए जाने की भी है।

यूपी बोर्ड | एसडीएम की रिपोर्ट पर होता है बोर्ड परीक्षा के केंद्रों का निर्धारण, नकल निवारण अधिनियम 2024 में राजकीय और एडेड पर भरोसा

प्रतियोगी परीक्षा में राजकीय-एडेड, बोर्ड में वित्तविहीन कॉलेज पसंद

प्रयागराज, मुख्य संवाददाता। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में नकल माफिया की दखल खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ पीसीएस से लेकर शिक्षक भर्ती तक की परीक्षाओं में राजकीय और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को केंद्र बनाया जा रहा है ताकि नकल या पेपरलीक की आशंका न रह जाए। इसके लिए बकायदा उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम 2024 लागू करते हुए नकल करने या कराने वालों के लिए एक करोड़ तक जुर्माना

और आजीवन कारावास की सजा तक का प्रावधान कर दिया है।

वहीं दूसरी ओर 10वीं-12वीं की परीक्षा में इस अधिनियम का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है और आज भी वित्तविहीन स्कूल पहली पसंद बने हुए हैं। शासन की ओर से एसडीएम की अध्यक्षता में गठित की

- वित्तविहीन स्कूलों को नहीं दी जाती प्रतियोगी परीक्षा की जिम्मेदारी
- यूपी बोर्ड की परीक्षा में 314 राजकीय विद्यालयों का केंद्र काटा

गई आधारभूत सूचना ओं के आधार पर यूपी बोर्ड ने ऑनलाइन माध्यम से 7448 (910 राजकीय, 3484 एडेड और 3354) केंद्र निर्धारित किए थे। हालांकि आपत्ति निस्तारण के नाम पर जिलों से निर्धारित केंद्रों की संख्या 8033 हो गई। इनमें 596 राजकीय, 3453 एडेड और 3984 वित्तविहीन स्कूल शामिल हैं। आश्चर्य की बात है कि सभी 75 जिलों ने 314 राजकीय विद्यालयों के केंद्र काट दिए, जबकि यूपी बोर्ड ने इन 314 स्कूलों को जिम्मेदार अफसरों की संस्तुति पर केंद्र बनाया था। ऐसे में सवाल है कि जब जिले की रिपोर्ट पर ही केंद्र बनाए गए थे तो ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि आपत्ति निस्तारण के दौरान उन्हें परीक्षा कराने के योग्य नहीं समझा गया। यह स्थिति तब है जबकि यूपी बोर्ड ने पहले से ही 208 राजकीय विद्यालयों को केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया से बाहर कर दिया था क्योंकि पिछले तीन साल से इन स्कूलों के केंद्र जिला समिति से निरस्त हो जा रहे थे।

8033 केंद्रों पर ही होगी हाईस्कूल-इंटर की परीक्षा

प्रयागराज, मुख्य संवाददाता। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 प्रदेशभर के 8033 केंद्रों पर ही होगी। बोर्ड ने पहले चरण में ऑनलाइन माध्यम से 7448 केंद्र बनाए थे। पहले चरण में मिली आठ हजार से अधिक आपत्तियों के निस्तारण के बाद जिलों से 8033 केंद्र बनाए गए थे। दूसरे चरण में बोर्ड को छात्रों, अभिभावकों, प्रधानाचार्यों और प्रबंधकों से 3053 आपत्तियां मिली थीं। इन आपत्तियों का परीक्षण करने के बाद प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, बरेली और गोरखपुर के संभागीय क्षेत्रीय कार्यालयों ने जिला विद्यालय निरीक्षकों से समन्वय बनाते हुए निराकरण कराया है। मुख्य रूप से जिन बच्चों के केंद्र दूर चले गए हैं या जिन केंद्रों पर क्षमता से अधिक परीक्षार्थी आवंटित हो गए हैं, उनका समाधान ही कराया गया है। बोर्ड सचिव भानुकी सिंह के अनुसार 24 दिसंबर को हुई पीसीएस केंद्र निर्धारण समिति के अनुमोदन के बाद 8033 केंद्र निर्धारित किए गए हैं। केंद्रों की सूची बोर्ड की वेबसाइट, एक्स और फेसबुक एकाउंट पर अपलोड कर दी गई है।

यूपी में तीन लाख अपात्रों की रोकी गई वृद्धावस्था पेंशन

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। राज्य सरकार ने जांच के बाद इस साल 3.32 लाख मृतक और अपात्र वृद्धावस्था पेंशनधारकों के नाम हटाए हैं। पिछले साल 1.77 लाख लोगों के नाम सूची से हटाए गए थे। समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आठ माह में प्रदेश भर में 9.83 लाख नए पात्र वृद्धों को पेंशन योजना से जोड़ा गया है।

उन्होंने बताया कि यूपी में वृद्धावस्था के कुल पेंशनधारक 67.50 लाख हो गए हैं। डिजिटल मॉनिटरिंग से वृद्धावस्था पेंशन योजना को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया गया है। वर्ष 2024 में 61 लाख वृद्धों को पेंशन दी जा रही थी, वर्ष 2025 में यह संख्या 67.50 लाख हो गई है। योजना की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए विभाग द्वारा नियमित सत्यापन और समीक्षा की जा रही है। उन्होंने बताया कि योजना में डिजिटल मॉनिटरिंग, आधार आधारित सत्यापन और सतत निगरानी की व्यवस्था लागू की गई है। इससे पेंशन वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शी और भरोसेमंद बनी है।

फैमिली आईडी से हो जाएगी स्वतः पहचान

समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने बताया कि नई व्यवस्था के मुताबिक वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्रों की पहचान और सत्यापन अब फैमिली आईडी 'एक परिवार एक पहचान' प्रणाली के माध्यम से स्वतः किया जाएगा, जिससे किसी भी पात्र व्यक्ति से 60 वर्ष का होते ही उसकी पेंशन खाते में पहुंचेगी।

पेंशन का लाभ केवल वास्तविक और पात्र वृद्धजनों तक ही पहुंचे इसकी व्यवस्था की गई है। उप निदेशक अमरजीत सिंह ने बताया कि विभाग की प्राथमिकता है कि कोई भी पात्र वृद्धजन पेंशन लाभ से वंचित न रहे।

फैसला : शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा, रिक्ति 25 हजार से कम नहीं होगी

चतुर्थ चरण की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जनवरी से

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। चौथे चरण की शिक्षक भर्ती (टीआरई-4) प्रक्रिया जनवरी से शुरू होगी। इसके लिए 15 जनवरी तक बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेज दी जाएगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सोमवार को सूचना भवन सभागार में आयोजित प्रेसवार्ता में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रिक्त पदों का आरक्षण के हिसाब से रोस्टर क्लियरेंस कराया जा रहा है। टीआई-4 में 25 हजार से कम रिक्ति नहीं होगी।

शिक्षा मंत्री ने बताया कि टीआरई 4 के तहत विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति के लिए 31 जिलों से रिक्ति मिल चुकी है। शिक्षक भर्ती के अलावा हाईस्कूलों में 5500 पुस्तकालयाध्यक्षों नियुक्ति संभावित है। इसकी रिक्ति भेजने के पहले संबंधित विषय की एसटीईटी (माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा) ली जाएगी। विशेष विद्यालय अध्यापक के 7279 पदों पर नियुक्ति के लिए रिक्ति भेजी जा चुकी है।

उन्होंने कहा कि आगामी सत्र से शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) को सख्ती से लागू कराया जाएगा। बच्चों की डुप्लीकेसी रोकने के लिए प्राइवेट स्कूलों के बच्चों की भी आधार सीडिंग करायी जाएगी। आरटीई कानून का पालन नहीं करने वाले स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई होगी। इसके तहत निजी स्कूलों को 25 प्रतिशत कमजोर और गरीब वर्ग के बच्चों का नामांकन लेना है। इस मौके पर अपर मुख्य सचिव डॉ. बी. राजेन्दर, सचिव दिनेश कुमार, उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. एनके अग्रवाल, निदेशक प्रशासन मनोरंजन कुमार, उपनिदेशक जनसंपर्क दिनेश कुमार मौजूद रहे।

बीपीएससी से 227195 शिक्षकों की नियुक्ति: शिक्षा मंत्री ने बताया कि तीसरे चरण तक कुल 2 लाख 27 हजार 195 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। सक्षमता पास करने वाले 2,66,786 विशिष्ट शिक्षक बने हैं। राज्य में 28,748 प्रधान शिक्षक और 4699 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति हुई है। 2005 में राज्य में शिक्षा का बजट 4341 करोड़ था जो वर्ष 2025 में बढ़कर 72,652.44 करोड़ हो गया है।

बीपीएससी को 15 जनवरी तक भेजी जाएगी अधियाचना

07 हजार 279 पदों पर विशेष स्कूल शिक्षक भर्ती होंगे

31 जिलों से मिल चुकी है शिक्षकों की रिक्ति

- हाईस्कूलों में 5500 पुस्तकालयाध्यक्षों की भी नियुक्ति संभावित
- आरटीई कानून का पालन नहीं करने वाले स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई होगी

पटना स्थित सूचना भवन सभागार में सोमवार को टीआरई 4 के बारे में बताते शिक्षामंत्री सुनील कुमार।

मंत्री अशोक चौधरी की सहायक प्रोफेसर पद पर नियुक्ति मामले में विवि सेवा आयोग से राय मांगी

ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी के सहायक प्रोफेसर नियुक्ति से जुड़े सवाल पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि उनकी नियुक्ति को लेकर बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग से अनुशंसा मिली थी। विभागीय स्तर पर समीक्षा के दौरान प्रमाणपत्र में कुछ कमियां पायी गई हैं। इसलिए शिक्षा विभाग ने आयोग से राय मांगी है। जून 2025 में आयोग ने अशोक चौधरी की राजनीति विज्ञान में सहायक प्रोफेसर पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसा शिक्षा विभाग को भेजी थी।

रील्स बनाने में मशगूल शिक्षकों पर कार्रवाई होगी

स्कूल के दौरान शिक्षकों और अधिकारियों के रील्स बनाने के सवाल पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि गलत काम करने वालों पर कार्रवाई होती है। उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार के मामले में बेतिया और किशनगंज के जिला शिक्षा पदाधिकारी जबकि मुजफ्फरपुर के क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक पर कार्रवाई की गई है।

प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय और डिग्री कॉलेज स्थापित होंगे

शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रत्येक प्रखंड के एक विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्य के ऐसे प्रखंडों में जहां डिग्री कॉलेज नहीं हैं, वहां नए डिग्री कॉलेज की स्थापना होगी। राज्य के पुराने एवं प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की रिक्ति मांगी गई है। पढ़ाई बाधित नहीं हो इसके लिए अतिथि शिक्षक रखने के लिए कहा गया है।

पटना और अन्य जिलों में भी कोहरे और कनकनी ने बढ़ाई लोगों की परेशानी

सितम: बिहार में आज शीत दिवस का अलर्ट

पटना, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। घने कोहरे और सर्द हवा से भीषण ठंड की मार झेल रहे बिहार के लोगों को चार जनवरी तक राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए शीत दिवस और घने कोहरे की चेतावनी जारी की है।

राज्य के अधिकतर जिलों में शीत दिवस जैसी स्थिति बनने को लेकर ऑरेंज अलर्ट और कई जिलों के एक या दो स्थानों पर घने कोहरे का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। राज्य में तीन दिनों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव के आसार नहीं है। सर्द पछुआ हवा की रफ्तार बढ़ने से राज्य भर में कंपकंपी छूट रही है। सोमवार को राज्य के अधिकतर इलाकों में आठ से 10 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा चली।

उत्तर बिहार के ज्यादातर जिलों में कोहरा छाया रहा। फारबिसगंज और नालंदा शीत दिवस की चपेट में रहा। ज्यादातर शहरों के तापमान में बढ़ोतरी हुई। राज्य का न्यूनतम 8.4 से 13.5 और अधिकतम तापमान 13.5 से 17.7 डिग्री के बीच रहा। बिहार का सबसे कम तापमान 8.4 डिग्री फारबिसगंज में और सबसे अधिक तापमान 17.7 डिग्री विक्रमगंज में रिकॉर्ड हुआ। वहीं सुबह के समय सबसे कम दृश्यता 600 मीटर पूर्णिया में दर्ज की गई। पटना में लगातार नौवें दिन धूप नहीं निकलने के कारण लोग ठंड से बेचैन रहे। पटना के न्यूनतम तापमान में 1.7 डिग्री की बढ़ोतरी और अधिकतम में 1.3 डिग्री की गिरावट आई। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2.1 डिग्री का ही अंतर रहा। इससे दिन में भी ठंड का एहसास हुआ। पटना का अधिकतम 14.7 और न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री रिकॉर्ड हुआ।

ठंड से दो लोगों की मौत: बोचहां और औरंगाबाद में ठंड से दो लोगों की मौत हो गई। बोचहां के चौपार निवासी अमीना खातून को सुबह में ठंड की वजह से अटैक आया। अस्पताल में उनकी मौत हो गई। वहीं, औरंगाबाद के गोह में बस में सफर कर रहे एक अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई। ▶ देखें P 04

पछुआ हवा के थपेड़ों ने हाड़ कंपाया

नेहरू पथ से सोमवार को सर्द पछुआ हवाओं के बीच गुजरतीं लड़कियां।

दिल्ली एयरपोर्ट से 128 उड़ानें रद्द

नई दिल्ली, एजेंसी। देश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। सोमवार को घने कोहरे के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर 128 उड़ानें रद्द कर दी गईं। आठ को डायवर्ट किया गया, जबकि 200 सेवाएं देरी से चलीं। दिल्ली हवाई अड्डे पर दृश्यता 50 मीटर रह गई। एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली एयरपोर्ट पर घने कोहरे और कम विजिबिलिटी के कारण 64 जाने वाली और 64 आने वाली उड़ाने रद्द की गई। उधर, कश्मीर में बर्फबारी की संभावना है।

04 जनवरी तक भीषण ठंड से राहत मिलने की संभावना नहीं

08 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली पछुआ हवा

पटना के 14 विमान रद्द, तेजस 17 घंटे देर से पहुंची

कोहरे के कारण सोमवार को भी तेजस राजधानी और संपूर्ण क्रांति सहित 15 ट्रेनें देरी से पटना पहुंची। तेजस राजधानी एक्सप्रेस 17 घंटे और संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस 16 घंटे की देरी से पटना जंक्शन पहुंची जबकि अमृत भारत एक्सप्रेस 11 घंटे की देरी से आई। वहीं पटना हवाई अड्डे से आने-जाने वाले 14 विमानों को रद्द कर दिया गया। 17 विमानों का डेढ़ घंटे तक की देरी से परिचालन हुआ।

सौगात | एक नमो भारत रैपिड, 11 अमृत भारत, एक राजधानी जैसी प्रीमियम ट्रेनें मिलीं, बिहारशरीफ-अस्थावां-बरबीघा एवं बरबीघा-शेखपुरा नई रेल लाइन का निर्माण कार्य पूरा हुआ

पटना में मेट्रो का दीदार हुआ, राज्य को 36 नई ट्रेनें मिलीं

अलविदा 2025

पटना, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। बिहार में 2025 में रेल सेवा का विस्तार हुआ। यात्रियों को ज्यादा प्रीमियम ट्रेनें मिलने से रेल सफर आसान हुआ। कम समय में तुरंत सफर होने लगी। मेट्रो की सेवा शुरू करने वाला बिहार देश का 12वां राज्य बन गया। नमो भारत, नमो भारत रैपिड, अमृत भारत, राजधानी सहित 36 नई ट्रेनों की सौगात मिली। 12 एक्सप्रेस और तीन पैसेंजर ट्रेनों के परिचालन में विस्तार किया गया। हालांकि, साल के अंत में रेल किराए में बढ़ोतरी से यात्रियों को चोट लगी हुई।

राजधानी पटना में साल अक्टूबर 2025 को मेट्रो रेल सेवा शुरू हो गई। पहले चरण में प्रायोगिक कॉरिडोर के लूप जलालपुर बस टर्मिनल से भूतनाथ रोड तक के बीच मेट्रो का परिचालन शुरू किया गया। अभी यात्रियों बस स्टैंड से भूतनाथ तक के बीच आने-जाने वाले मेट्रो सफर का लुत्फ उठा रहे हैं। सुबह आठ बजे से रात के आठ बजे तक परिचालन हो रहा है। भूतनाथ से आईएसबीटी तक आने और जाने के लिए यात्रियों को 15-15 रुपये किराया देना पड़ रहा है। दूसरे चरण में जनवरी 2026 से भूतनाथ से मलाही पकड़ी के बीच मेट्रो का परिचालन शुरू किया जाएगा।

इसके बाद मेट्रो का परिचालन 6.107 किमी में शुरू हो जाएगा। इससे पहले देश के 11 राज्यों दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, बंगाल, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, केरल, गुजरात और मध्य प्रदेश में मेट्रो सेवा शुरू है।

2.9 किलोमीटर में दौड़ रहा रही मेट्रो : पटना मेट्रो का निर्माण के कॉरिडोर में पांच जर किया जा रहा है। दोनों में 32.497 किलोमीटर लंबे ट्रैक और 12-13 एलिवेटेड व अंडरग्राउंड स्टेशनों का निर्माण किया जा रहा है। जिसमें दानापुर, खुशरू मोड़, अलीगंज मोड़, पटलिपुत्र, रुकनपुरा, राजा बाजार, चिड़ियाघर, विधान भवन, बिस्कुट भवन, पटना जंक्शन, तुलसीन केंद्र, गांधी मैदान, पीएमसीएच, पटना विश्वविद्यालय, मोहनपुर लक्ष्य स्टेडियम, राजेंद्र नगर, मलाही पकड़ी, श्रीकृष्णपुरी, भूतनाथ, जोरे मंदिर, आईएसबीटी, जलनपुरा, रामकृष्ण नगर और मोहनपुर मेट्रो स्टेशन शामिल है। इसके पहले चरण में भूतनाथ से जोरे मंदिर होते हुए आईएसबीटी तक 2.9 किलोमीटर में मेट्रो चल रही है।

06 अगस्त को आईएसबीटी से भूतनाथ तक पटना मेट्रो की सेवा शुरू हुई, जनवरी में भूतनाथ से मलाही पकड़ी तक मेट्रो चलेगी

दो कार्गो टर्मिनल चालू

राज्य में दो नये कार्गो टर्मिनल चालू किए गए। इसमें लोग पहली (कम दिया। लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड एवं बिहार अक्षय ऊर्जा विद्युत निगम लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड, शामिल है। इसी कंपनियों के माल ढुलाई के लिए उपयोग में लाया जिया गई है।

नई रेललाइन का निर्माण हुआ

बिहार शरीफ-अस्थावां-बरबीघा एवं बरबीघा-शेखपुरा नई रेल लाइन का निर्माण, दरभंगा से बंद ढुमरी तक 22 किमी लंबी रेलवेज का कार्य पूरा हो गया है। 22.5 किमी लंबे रेल-दरभंगा-बिहटा-बरबीघा-शेखपुरा नई लाइन परियोजना का आरंभ भाग पूरा हो चुका है। मसौढ़ा-बिहटा खंड का शेखपुरा हो गया है। अस्थावां-बुलेवा खंड नई रेल लाइन परियोजना के तहत अस्थावां-अर्जुनी रेलखंड का कार्य पूरा होने के बाद परिचालन शुरू है। सुबेह-विरा रेलखंड का निर्माण भी पूरा हुआ।

दो वंदे भारत मिली

रेलवे ने फतेहपुर से गोरखपुर, दानापुर से जौनपुर के बीच वंदे भारत, अयोध्या से पटना के बीच नमो भारत रैपिड रेल शुरू किया। रेलवे ने अलावा बिहार के बीच राज्यों एवं महानगरों का संपर्क बढ़ाने शुरू किया गया, जबकि राजेंद्र नगर से नई दिल्ली, लोकमान्य तिलक से सहरसा, दरभंगा से गोरखपुर, मालदा टाउन से गंगासागर, सीतामढ़ी से आनंद विहार, दिल्ली से सीतामढ़ी, गया से पोरबंदर, पटना से सहरसा, मदार से दरभंगा, मुजफ्फरपुर से गोरखपुर के बीच अमृत भारत का संचालन शुरू हुआ।

हर संकुल स्तरीय संघ जीविका बैंक में देगा 25 लाख अंशदान

400 करोड़ से अधिक राशि मिलेगी, जीविका के राज्य में 1677 संकुलस्तरीय संघ

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। जीविका का हर संकुल स्तरीय संघ जीविका बैंक (निधि) में 25 लाख रुपये का अंशदान देगा। इससे जीविका निधि का आकार बढ़ेगा और ज्यादा से ज्यादा दीदियों को लोन मिल सकेगा।

राज्य में 1677 संकुल स्तरीय संघ हैं, जिनके द्वारा 400 करोड़ से अधिक रुपये बैंक में दिये जाएंगे। जीविका बैंक में राज्य सरकार द्वारा पहले ही 155 करोड़ दिये गये हैं। आगे और भी राशि राज्य सरकार देगी। इससे अधिक-से-अधिक जीविका सदस्यों (दीदियों) को बैंक के माध्यम से लोन उपलब्ध कराया जा सकेगा। मालूम हो कि प्रदेशभर में जीविका समूहों का चार से पांच ग्राम पंचायतों पर एक संकुल स्तरीय संघ गठित है।

राज्य सरकार द्वारा जीविका के सदस्यों (दीदियों) को लोन देने के लिए उक्त बैंक का गठित किया गया है, ताकि दीदियों को सुगमता से और जल्द लोन मिल सके और वह सभी अपना व्यवसाय और रोजगार को और अधिक विकसित कर सकें। इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी और उनका परिवार आर्थिक रूप से समृद्ध होगा।

जीविका से मिली जानकारी के अनुसार संकुल स्तरीय संघ के बैंक खाते में करीब 1400 करोड़ से अधिक की राशि जमा है। वहीं, इससे चार-पांच गुना अधिक राशि लोन के रूप में वितरित की गई है। यह बताता है कि प्रदेश का जीविका समूह निरंतर और सक्षम हो रहा है। जीविका के पदाधिकारी बताते हैं कि संकुल स्तरीय संघ के पास मुख्य रूप से दो माध्यम से राशि आती है। पहला तो राज्य सरकार उन्हें पूंजी देती है। वहीं, संघ नीचे के समूहों ग्राम संगठन और जीविका समूहों के सदस्यों को लोन उपलब्ध कराता है, जिससे उन्हें ब्याज की रकम प्राप्त होती है। इस राशि का फिर पुनर्विनियोजन होता है, जिसका उपयोग दीदियों के लिए ही होता है।

औसतन पांच ग्राम पंचायत पर है एक संकुल स्तरीय संघ

14 सौ करोड़ से अधिक राशि संघों के बैंकों में जमा हैं

155 करोड़ राज्य सरकार ने जीविका बैंक को दिया है

राज्य में डेढ़ करोड़ जीविका दीदियां

मालूम हो कि राज्य में डेढ़ करोड़ जीविका दीदियां हैं। इनके द्वारा सालाना 14-15 हजार करोड़ का लोन सालाना विभिन्न बैंकों से लिया जाता है। लोन वापसी का रिकॉर्ड भी इनका शत-प्रतिशत है। इसकी जगह जीविका बैंक से लोन प्राप्त करने में दीदियों को काफी सहूलियत होगी। जीविका बैंक में हर काम ऑनलाइन होगा। आवेदन देने के 48 घंटे से लेकर सात दिनों तक राशि जीविका दीदी के खाते में भेज दी जाएगी। इसके माध्यम से दीदियों को 15 हजार, 75 हजार और दो लाख तक के लोन मिलेंगे। फरवरी से लोन के आवेदन लिये जाने की तैयारी जीविका द्वारा की जा रही है।

सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की परीक्षा स्थगित

पटना, वरीय संवाददाता। बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के पदों के लिए होने वाली लिखित परीक्षा अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी है।

सामान्य अध्ययन की परीक्षा 10 और 11 जनवरी 2026 को, जबकि वैकल्पिक विषय की परीक्षा 12 जनवरी और अनिवार्य विषय की परीक्षाएं 13, 15 और 16 जनवरी 2026 को आयोजित होनी थी। आयोग ने बताया है कि परीक्षा को अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया गया है।

स्थगन के पीछे तकनीकी या प्रशासनिक कारण का उल्लेख नहीं किया गया है। अभ्यर्थियों के लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि परीक्षा रद्द नहीं हुई है, बल्कि स्थगित हुई है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा आयोजन की तिथि की घोषणा जल्द की जाएगी। नया शेड्यूल वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जारी होगा।

सिपाही भर्ती में अब निगेटिव मार्किंग नहीं

कैबिनेट फैसला

लखनऊ, विशेष संवाददाता। राज्य सरकार ने यूपी पुलिस का हिस्सा बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने आरक्षी व बंदी रक्षक के पदों पर भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा में निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था समाप्त कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेश इस प्रस्ताव को मंजूरी दी।

इसके लिए कैबिनेट बाई सर्कुलेशन से उप्र पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली 2025 तथा उप्र कारागार प्रशासन व सुधार विभाग जेल वार्डर संवर्ग सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2025 को स्वीकृति प्रदान की गई है। आरक्षी व बंदी रक्षक के पदों पर भर्ती परीक्षा में अभी तक गलत उत्तर देने पर निगेटिव मार्किंग करते हुए नंबर काटे जाने की व्यवस्था थी। आरक्षी पद पर भर्ती परीक्षा में सही उत्तर देने पर दो नंबर देने और गलत उत्तर पर आधा नंबर काटने की व्यवस्था थी। बंदी रक्षक के पद पर भर्ती परीक्षा में भी निगेटिव मार्किंग होती थी। शासन ने इसे समाप्त करने का फैसला किया था, जिसके तहत सेवा नियमावली में बदलाव किया गया है। उप्र पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड नियमावली में संशोधन संबंधी अधिसूचना जल्द जारी करेगा।

■ यूपी पुलिस में भर्ती का सपना देख रहे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत

पुलिस मोटर परिवहन के मुख्य आरक्षी परीक्षा का परिणाम घोषित

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस मोटर परिवहन शाखा में मुख्य आरक्षी 176 पदों की पांच अक्तूबर को हुई विभागीय परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। इस बारे में बोर्ड की वेबसाइट uppbpb.gov.in पर अभ्यर्थी परीक्षा परिणाम देख सकते है। अगले चरण की प्रयोगात्मक तकनीकी दक्षता परीक्षण के प्रवेश पत्र के बारे में सूचना जल्दी बोर्ड की वेबसाइट पर दी जाएगी।

जीएसटी दरों में कमी का लाभ उठाने के लिए ऑर्डर में रिकॉर्ड तेजी दर्ज

रिपोर्ट : औद्योगिक उत्पादन दो साल के नए शिखर पर पहुंचा

नई दिल्ली, एजेंसी। खनन और विनिर्माण क्षेत्रों के मजबूत प्रदर्शन से नवंबर महीने में देश के औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि दर दो साल के उच्च स्तर 6.7 प्रतिशत पर पहुंच गई।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के मुताबिक, औद्योगिक उत्पादन को मापने वाला औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) नवंबर, 2024 में पांच प्रतिशत बढ़ा था। इससे पहले औद्योगिक उत्पादन का उच्च स्तर नवंबर, 2023 में 11.9 प्रतिशत दर्ज किया गया था। त्योहारों से पहले देश में मांग और खपत को बढ़ावा देने के लिए कई उपभोक्ता वस्तुओं पर जीएसटी की दरों में 22 सितंबर 2025 से कटौती की गई थी। इससे जीएसटी दरों में कमी का लाभ उठाने के लिए विनिर्माण ऑर्डरों में तेजी आई। इसके साथ एनएसओ ने अक्तूबर 2025 के लिए औद्योगिक उत्पादन वृद्धि के आंकड़े को भी संशोधित किया है। अक्तूबर के लिए आईआईपी वृद्धि को बढ़ाकर 0.5 प्रतिशत कर दिया गया है जबकि पिछले महीने जारी अस्थायी अनुमान 0.4% का था। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, नवंबर 2025 में विनिर्माण क्षेत्र का उत्पादन आठ प्रतिशत बढ़ा, जो एक साल पहले इसी महीने में 5.5 प्रतिशत था।

औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी का आम लोगों पर असर

औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी का मतलब है कि अर्थव्यवस्था की सेहत बेहतर हो रही है। इसका सीधा लाभ नौकरी, आय, व्यापार और सरकारी सेवाओं के जरिए आम आदमी तक पहुंचता है।

1 रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावना

जब फैक्ट्रियां और उद्योग ज्यादा उत्पादन करते हैं, तो उन्हें अधिक मजदूर, तकनीशियन और कर्मचारियों की जरूरत होती है। नए रोजगार पैदा हो सकते हैं।

2 आमदनी और खर्च करने की क्षमता में सुधार के आसार

उद्योगों की स्थिति बेहतर होने पर वेतन में वृद्धि, ओवरटाइम और बोनस मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इससे लोगों की खरीदने की ताकत सुधरती है।

3 सरकार की आय बढ़ने से सुविधाएं और बेहतर होंगी

उद्योगों के अच्छे प्रदर्शन से कर संग्रह बढ़ता है। सरकार के पास शिक्षा, स्वास्थ्य पर खर्च के लिए ज्यादा संसाधन होते हैं, जिसका फायदा लोगों को मिलता है।

4 महंगाई पर मिला-जुला असर

ज्यादा उत्पादन होने से वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ती है, जिससे कई सामानों के दाम स्थिर रह सकते हैं। यदि कच्चा माल महंगा है या ब्याज दरें ऊंची हैं, तो महंगाई पूरी तरह कम होना जरूरी नहीं।

5 छोटे कारोबार और एमएसएमई क्षेत्र को सहारा

बड़े उद्योगों की रफ्तार बढ़ने से छोटे उद्योगों, ट्रांसपोर्ट, पैकेजिंग और सप्लाई चेन को भी काम मिलता है। इससे स्थानीय कारोबार को फायदा होता है।

6 शेयर बाजार, निवेश पर असर

औद्योगिक उत्पादन में तेजी से बाजार में भरोसा बढ़ता है। म्यूचुअल फंड और शेयर में निवेश करने वालों को फायदा हो सकता है। हालांकि, असर हर व्यक्ति पर एक जैसा नहीं होता।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्कूल मान्यता उपविधि में संशोधन किया

नए सत्र से स्कूल बिना एनओसी के भी मान्यता को आवेदन कर सकेंगे

बदलाव

पटना, कार्यालय संवाददाता। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने स्कूल मान्यता उपविधि में संशोधन किया है, जो नए शैक्षणिक सत्र यानी 2026-27 से मान्यता प्राप्त करने वाले स्कूलों पर लागू होगा। नए शैक्षणिक सत्र से संबद्धता के लिए विद्यालय बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के भी आवेदन कर सकेंगे।

अब तक स्कूलों को मान्यता प्राप्त करने के लिए राज्य शिक्षा विभाग से एनओसी प्राप्त करना अनिवार्य था। लेकिन अब स्कूल बिना शिक्षा विभाग से मान्यता के सीधे सीबीएसई के सरस पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। हालांकि पुरानी व्यवस्था भी इसके साथ जारी रहेगी।

आवेदन प्राप्त होने के बाद सीबीएसई बोर्ड स्वयं संबंधित राज्य के शिक्षा विभाग से संपर्क करेगा और आवश्यक स्वीकृति मांगेगा। विभाग को बोर्ड से पत्र प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर अपनी प्रतिक्रिया बोर्ड को देनी होगी। अगर बोर्ड को प्रतिक्रिया नहीं प्राप्त होगी तो बोर्ड एक रिमाइंडर लेटर विभाग को भेजेगा, जिस पर 15 दिनों के अंदर प्रतिक्रिया देनी होगी। अगर इसके बाद भी प्रतिक्रिया बोर्ड को नहीं मिलेगी तो बोर्ड द्वारा यह माना जाएगा कि विभाग को आपत्ति नहीं है।

30 दिनों के अंदर शिक्षा विभाग को देनी होगी अपनी प्रतिक्रिया

- अब तक शिक्षा विभाग से एनओसी के बाद ही स्कूलों को सीबीएसई से मिलती थी मान्यता
- अब एनओसी के साथ या बिना भी स्कूल पोर्टल पर कर सकेंगे आवेदन
- बोर्ड विभाग से संपर्क कर मांगेगा स्वीकृति

ऐसे में सीबीएसई संबंधित स्कूल को मान्यता प्रदान करने के लिए स्वतंत्र होगा। इस नए प्रावधान का उद्देश्य मान्यता प्रक्रिया में तेजी लाना और अनावश्यक विलंब को कम करना है। अब तक के नियम के कारण कई स्कूल का आवेदन अधिकारी के स्तर पर हीं फंसा रह जाता था। इससे स्कूलों को बार-बार दौड़ लगानी पड़ती थी। इससे मान्यता मिलने में भी विलंब होता था।

नए साल से बिहार बोर्ड देगा ये सौगात : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति भी नए साल में अपने विद्यार्थियों को कई सौगात देने जा रहा है, जिसे छात्र हित को देखते हुए शुरू किया जा रहा है। बिहार बोर्ड नए साल से सत्यापन की व्यवस्था ऑनलाइन कर देगा। एक जनवरी से ही यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। नौकरी लगने या किसी संस्थान में प्रवेश के लिए संबंधित संस्थान की ओर से सत्यापन के लिए डाक से जो आवेदन आते थे वे अब ऑनलाइन ही होंगे। सत्यापन की व्यवस्था पेपरलेस होने से विलंब नहीं होगा। बोर्ड जनवरी में ही विद्यार्थियों के लिए चैटबोट की सुविधा देने जा रहा है। इससे अभ्यर्थियों को त्वरित उनके सवालों का जवाब मिलेगा।

तीसरी कक्षा से ही कंप्यूटेशनल थिंकिंग, एआई की पढ़ाई होगी

2026 से सीबीएसई साल में दो बार 10वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित करेगा। साथ ही नए सत्र से तीसरी में एआई और कंप्यूटेशनल थिंकिंग विषय की पढ़ाई की शुरुआत करेगा। आईसीएसई बोर्ड नए सत्र से कई वैकल्पिक विषयों को नौवीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए जोड़ेगा। इसमें एआई, हेल्थ एजुकेशन, रोबोटिक्स, आतिथ्य प्रबंधन विषय शामिल होंगे।

केवल जीएसटी पोर्टल पर नोटिस अपलोड कर देना कानूनी रूप से पूर्ण सूचना नहीं : हाईकोर्ट

व्यापारियों को राहत: गाजियाबाद की मेसर्स बैम्बिनो एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड सहित 13 कंपनियों ने दायर की थी याचिका

अमर उजाला ब्यूरो

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जीएसटी पोर्टल पर केवल नोटिस या आदेश अपलोड कर देना कानूनी रूप से पूर्ण सूचना नहीं मानी जा सकती। नोटिस या आदेश करदाता की जानकारी में आने के बाद ही अपील दायर करने की समय-सीमा शुरू होगी। इस टिप्पणी संग न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह, न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने गाजियाबाद की मेसर्स बैम्बिनो एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड सहित 13 याचिकाएं स्वीकार कर लीं।

याचियों ने शिकायत की कि कारण बताओ नोटिस और अंतिम आदेश उन्हें न देकर विभाग ने जीएसटी पोर्टल पर अपलोड कर दिया। इससे उन्हें समय पर नोटिस और आदेश की जानकारी नहीं हो सकी। विभाग ने वसूली की कार्रवाई शुरू की तो उन्हें आदेश का पता चला पर तब तक अपील करने की निर्धारित 120 दिनों की अवधि समाप्त हो चुकी थी। इसके खिलाफ याची फर्मों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद माना कि बिना उचित सूचना के एकपक्षीय आदेश पारित करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। कोर्ट ने संज्ञान लिया कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां हिंदी मुख्य भाषा है, जीएसटी पोर्टल पूरी तरह अंग्रेजी में है। ऐसे में छोटे और मध्यम व्यापारियों के लिए पोर्टल के विभिन्न टैब (अलग-अलग विंडो) में जाकर नोटिस खोजना कठिन है।

कोर्ट ने इन सभी मामलों में एकपक्षीय आदेशों को रद्द कर व्यापारियों को अपील दायर करने के लिए नया अवसर प्रदान किया। साथ ही निर्देश दिया कि यदि करदाता विवादित टैक्स की 10 प्रतिशत राशि जमा करते हैं तो उनके मामलों की नए सिरे से सुनवाई की जाए।

कोर्ट ने कहा- पोर्टल पूरी तरह अंग्रेजी में है, जबकि राज्य की मुख्य भाषा हिंदी है, ऐसे में छोटे व मध्यम व्यापारियों के लिए अलग-अलग विंडो में जाकर नोटिस खोज पाना कठिन

कोर्ट ने कहा-टैक्स देने वाले ने पोर्टल या ई-मेल को कब एक्सेस किया, इसका मैकेनिज्म नहीं

विभाग की ओर से दलील दी गई कि राज्य/केंद्रीय जीएसटी अधिनियम की धारा-169(1) के तहत छह तरीके प्रदान किए गए हैं। 1-सीधे या मैसेंजर द्वारा (2) स्पीड पोस्ट (3) ई-मेल (4) कॉमन पोर्टल पर उपलब्ध कराना (5) अखबार में प्रकाशन (6) चिपकाकर। इस पर कोर्ट ने कहा कि यह पता लगाने का कोई मैकेनिज्म नहीं है कि टैक्स देने वाले ने पोर्टल या ई-मेल को कब एक्सेस किया। ऐसे में पोर्टल पर नोटिस या आदेश अपलोड संचार तब तक नहीं माना जाएगा, जब तक कि संबंधित को इसकी जानकारी न हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्रीय अधिकारी अभी भी भौतिक रूप से नोटिस भेज रहे हैं, जबकि राज्य के अधिकारी पूरी तरह से डिजिटल मोड पर चले गए हैं। इससे करदाताओं को अपील करने में दिक्कत हो रही है।

उन्नाव दुष्कर्म मामला : दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश रोका
जेल में ही रहेगा कुलदीप सेंगर, चार हफ्ते में मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले

अपने ही आदेश पर शीर्ष अदालत की रोक : जांच के लिए विशेषज्ञ समिति, केंद्र सरकार और चार राज्यों से मांगा जवाब

अच्छे जज से भी हो सकती है गलती सेंगर की सजा के निलंबन पर रोक

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के उन्नाव दुष्कर्म मामले में पीड़िता के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा निलंबित करने और जमानत देने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। पीड़िता की याचिका पर शीर्ष कोर्ट ने सेंगर को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब भी मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश तिन जजों ने दिया है, वह अच्छे जजों में से हैं, लेकिन गलती किसी से भी हो सकती है। कोर्ट अदालत ने साफ किया कि सेंगर को जेल नहीं भेजा जाएगा।

पूर्व मुख्यमंत्री सीबीआई (एनकाउंटर), जांच और सहयोगी और सीबीआई की अपील पर सेंगर ने सीबीआई की सीबीआई की अपील पर सुनवाई की। सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से हाईकोर्ट के 23 दिसंबर के आदेश पर रोक लगाने का आग्रह करते हुए कहा कि यह जमानत लड़की के साथ दुष्कर्म का गंभीर मामला है। पिता की हत्या सुनने के बाद पीड़िता ने कहा, हम सबसे में अन्याय के अंतिम दरवाजे जो हैं, जिनकी सोच जानते हैं। इन सवालों में मामलों कार्यवाही की परिवार की कमियां हैं।

पीठ ने कहा कि दुष्कर्म कोर्ट या हाईकोर्ट के दोषी या निलंबित किसी की सजा निलंबित करने का जमानत पर रिहा करने के मामलों में अपराधी पर जब सजायाफ्ता की मुहर लगा कर नहीं लगाई जाती है। यह आदत सामान्य है, अपील सेंगर दूसरे मामले में भी जेल में है। पीठ ने कहा, जब सजा उसकी की देखते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हैं। अगर हम निलंबित आदेश के साथ रोक नहीं लगा सकते। पीठ ने कहा जो तर्क दिया कि पीड़िता को सजा दे कानूनी इलाज करने का सम्पूर्ण अधिकार है। उसे कोर्ट के अनुकूल लेने की जरूरत नहीं है।

आज भी धमकियां...फांसी मिलने तक चैन से नहीं बैठूंगी : पीड़िता

मुझे सुप्रीम कोर्ट के न्याय विश्वास है। मुझे सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, लेकिन मेरी सुरक्षा खतरे में है। मेरे साथ सेंगर को फांसी नहीं हो जाती, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। अब मेरे साथ फांसी होगी, तभी मुझे और मेरे परिवार को न्याय मिलेगा। इसे आज भी धमकियां मिल रही हैं। यह लोग चाहते हैं, मेरा चैन से साथ रहने का समय है। -दुष्कर्म पीड़िता

सिपाही लोकसेवक तो विधायक क्यों नहीं

हाईकोर्ट का आदेश मिल जाने से पीड़ित है, वह देश के बेहतरीन जजों में गिने जाते हैं, लेकिन गलती किसी से भी हो सकती है। ऐसे फैसले हो सकता है कि सुप्रीम कोर्टहाईकोर्ट को लोकसेवक मान चाहे, लेकिन विधायक या सांसद को इस दायरे में नहीं मान लिया जाए। -सोलिसिटर तुषारमेहता, सॉलिसिटर

कोर्टरूम लाइव : लोकसेवक मतलब प्रभावशाली व्यक्ति

सॉलिसिटर जनरल मेहता : हाईकोर्ट ने यह कहने में गलती की कि जजों के साथ सीधी अदालत में जमानत नहीं होती। सीबीआई जैसे का फाइनली कार्यवाही नहीं पता जा सकता। जोधपुर ने इसे जीवनभर नहीं लिए गए है, या सीबीआई या इन्वेस्टर के लिए लोकसेवक का अर्थ बड़ा व्यापक है जो बहुत प्रभावशाली पोस्ट में हो। इसमें सरपंच और पंचायत से लेकर है। अदालत के समक्ष ऐसा महत्वपूर्ण विधायक या और बहुत प्रभुत्व रखता है।

सेंगर के वकील सिद्धार्थ दवे और उन्नत्रिहरन : लिखकर की मनमानी व्याख्या नहीं करना चाहिए, क्या हम कि कानून में स्पष्ट रूप से लोकसेवक न हो।

पीठ : अगर यह जजमान लोकसेवक मानते हैं तो कानूनों का कानूनी व्याख्या कार्यवाही होगा, लेकिन लोकसेवक-लोकसेवक को तुरंत लिए जाएंगे। कोर्ट अपनी सीमित या लोकसेवक के कुछ [illegible]

अरावली की 100 मीटर से छोटी पहाड़ियों पर भी नहीं होगा खनन

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। अरावली पहाड़ियों को लेकर उठे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने 20 राज्यों के अरावली पहाड़ियों पर रोक लगा दी है। उसने पिछले के उठाए कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों व पर्वतश्रृंखलाओं की एकसमान परिभाषा को स्वीकार किया था। इसके बाद अरावली के विस्तार वाले जिलों में उसमें 100 मीटर की अरावली पहाड़ी माना गया, जिसकी ऊंचाई आसपास की जमीन से 100 मीटर तो है। इस परिभाषा से छोटी पहाड़ियों पर खनन की अनुमति मिलने का खतरा था, क्या रोक कोर्ट के नए आदेश के बाद 31 पर रोक लग जाएगी।

सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने उस याचिका के मामले जांच के लिए विशेषज्ञों की समिति बनाने की सीबीआई कोर्ट बनाने का प्रस्ताव दिया। समिति उन क्षेत्रों के विस्तृत मानचित्र भी तैयार करेगी, जिन्हें अरावली क्षेत्र से बाहर रखा जाएगा। यह अदालत ने विशेष महत्व दिया कि यह इसे बड़ा खतरे में अरावली की पर्वतश्रृंखला को सुरक्षित ही रखता है। अरावली की पहाड़ी हुई परिभाषा से पहले सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ी की एकसमान परिभाषा को स्वीकार किया था। कोर्ट ने कहा कि अरावली पहाड़ी को 100 मीटर से ऊंचा माना जाएगा। इसके बाद राजस्थान, गुजरात, हरियाणा व मध्यप्रदेश की पहाड़ियों में खनन को लेकर विवाद उठा था। कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों के संरक्षण और पर्यावरण से जुड़े मामलों में कोर्ट की मदद करने के लिए एक समिति का गठन किया है। कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की परिभाषा को स्पष्ट करने के लिए केंद्र सरकार, गुजरात, हरियाणा व मध्यप्रदेश की पहाड़ियों में खनन के मामलों में कोर्ट की मदद करने का आदेश दिया। यह मामला इस विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि अरावली की परिभाषा में सांस्थिक भ्रमता में दिया गया समान्य रूप से परिभाषा को सुरक्षित रखा जा सकता है।

पहाड़ी या पहाड़ी श्रृंखला के बीच समान्यतः जमीन छोटी पहाड़ियों में अलग हो गई थी।

नई परिभाषा स्पष्ट करने की जरूरत

अरावली की परिभाषा को लेकर किसी अदालत और आयोग की सिफारिश को जारी कुछ राज्यों ने विरोधी के प्रकरण दी थी कि उनकी पहाड़ होती है। इसमें कोर्ट ने यह विवाद विरोधी का कोर्ट के निर्देश का पालन करने से पालन और स्पष्टीकरण की जरूरत है। -सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष कोर्ट ने कहा-कुछ चिंताओं की जांच जरूरी

- यह अरावली की परिभाषा को 500 मीटर तक सीमित करने से अरावली क्षेत्र सिकुड़ जाता है? क्या इससे निर्बाध खनन को अनुमति मिल जाएगी?
- अगर हां तो यह सुनिश्चित करने के लिए, कि संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण हो, कोई पारिस्थितिक नियंत्रण या संतुलन न हो?
- अगर यह अरावली क्षेत्र 100 मीटर या उससे ऊंचाई के हैं और उसके बाद 200 मीटर का अंतर है तो क्या ऐसे में निर्बाध खनन की बात मानुसार हो या उसमें हो?
- क्या नई परिभाषा से पर्यावरण का या फिर अरावली पर्वतों का संरक्षण बढ़ेगा? जिससे किसी रोक टोक खनन चाहे रहने में अरावली का रोक है।
- 12,081 पहाड़ियों में से सिर्फ 8,040 के या 100 मीटर की ऊंचाई की तय परिभाषा पहाड़ का पूरा करने वाली पर्वतश्रृंखलाओं को बिना रोक-टोक खनन या पर्यावरण को नुकसान हो सकता है।

केंद्र ने कहा-खनन पर पूर्ण रोक के निर्देश

मुकुल रोहतगी ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि राज्यों को खनन रोकने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। नई दिशा-निर्देश दिया गया कि अगले कोई खनन गतिविधि न की जाए। अदालत ने कहा इसका मतलब है कि समिति की सिफारिशों और इस कोर्ट के निर्देशों का कि खनन जारी है। समिति के गठन तक रोक जारी रहेगी।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री बोले-अरावली के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने फैसले के बाद कहा, केंद्र सरकार अरावली के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कोर्ट सीबीआई का दिया, अरावली में अवैध अवैध एवं रोक लगाने और सुरक्षा का समन्वय करने के लिए नई समिति के गठन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का स्वागत है। हम अरावली के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए ने सभी नई हरियाणा सहयोग प्रदान करने को प्रतिबद्ध है।

समिति की रिपोर्ट और कोर्ट की टिप्पणियों पर गहन मंथन का बाद है। कोर्ट ने अरावली पहाड़ी और पर्वतश्रृंखला और परिभाषा में एकसमान परिभाषा को स्वीकार करने के बाद कोर्ट की नजर आने पर अनुरोध किया। यह मामला इस विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि अरावली की परिभाषा में सांस्थिक भ्रमता में दिया गया समान्य रूप से परिभाषा को सुरक्षित रखा जा सकता है।

व्यापारियों की मजबूत खरीदारी से चांदी की कीमतों में लगातार पांचवें कारोबारी सत्र में तेजी

चांदी ने पहली बार छुआ 2.40 लाख का स्तर, सोना रिकॉर्ड उच्च स्तर से फिसला

अमर उजाला ब्यूरो/एजेंसी

नई दिल्ली। चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी का सिलसिला पांचवें कारोबारी सत्र में भी जारी रहा। सोमवार को दिल्ली सराफा बाजार में चांदी 3,650 रुपये के भारी उछाल के साथ पहली बार 2.40 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई।

ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक, कारोबारियों की मजबूत खरीदारी से चांदी की कीमतें एक बार फिर नए शिखर पर पहुंच गईं। हालांकि, सोना रिकॉर्ड उच्चतम स्तर से 500 रुपये सस्ता होकर 1,41,800 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव आ गए। पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 2,36,350 रुपये प्रति किलोग्राम और सोना रिकॉर्ड 1,42,300 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था।

एलकेपी सिक्योरिटीज के उपाध्यक्ष शोध विश्लेषक (जिंस-मुद्रा) जतिन त्रिवेदी ने कहा, आपूर्ति में कमी के बीच औद्योगिक मांग बढ़ने से चांदी में तेजी जारी है। हालांकि, वैश्विक बाजारों में सोने में गिरावट के बीच निवेशकों ने मुनाफावसूली की, जिससे पीली धातु में गिरावट आई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 70 डॉलर टूटकर 4,463 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। चांदी में भी 4.06 डॉलर की गिरावट रही।

3,650 रुपये बढ़े चांदी के दाम सोमवार को

1,41,800 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव बंद हुआ सोना

इस साल 1.50 लाख रुपये से अधिक बढ़ गए चांदी के दाम

वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच निवेश के सुरक्षित विकल्प और चुनिंदा उद्योगों में मांग बढ़ने से इस साल चांदी ने रिटर्न के मामले में सोने को भी पीछे छोड़ दिया है। चांदी की कीमतों में इस साल 1,50,300 रुपये प्रति किलोग्राम या 167.55 फीसदी की बढ़ोतरी देखने को मिली है। 31 दिसंबर, 2024 को घरेलू बाजार में चांदी 89,700 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव बंद हुई थी।

■ घरेलू बाजार में सोने की कीमतें कैलेंडर वर्ष 2025 में अब तक 62,850 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़ी है। यानी पीली धातु ने निवेशकों को 79.60 फीसदी का रिटर्न दिया है। 31 दिसंबर, 2024 को सोना 78,950 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था।

बिकवाली से सेंसेक्स 346 अंक टूटा, 1.82 लाख करोड़ डूबे

तेल-गैस एवं आईटी शेयरों में बिकवाली, विदेशी निवेशकों की पूंजी निकासी और साल के अंत में कमजोर कारोबार होने से सोमवार को घरेलू शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स लगातार चौथे कारोबारी सत्र में गिरावट दर्ज करते हुए 345.91 अंक टूटकर 84,695.54 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 403.59 अंक गिरकर 84,637.86 तक आ गया था। निफ्टी तीसरे सत्र भी नुकसान में रहा और 100.20 अंक फिसलकर 25,942.10 पर बंद हुआ। सूचीबद्ध कंपनियों की पूंजी 1.82 लाख करोड़ घटकर 472.15 लाख करोड़ रुपये रह गई।

■ *सेंसेक्स की 30 में 22 कंपनियों के शेयर गिरावट में रहे। अदाणी पोर्ट्स सर्वाधिक 2.22 फीसदी नुकसान में बंद हुआ। टाटा स्टील आठ शेयर 1.83 फीसदी तक बढ़त में रहे।*

2,759.8 करोड़ के शेयर बेचे

विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने सोमवार को घरेलू बाजार में शुद्ध रूप से 2,759.89 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। हालांकि, घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 2,643.85 करोड़ की शुद्ध खरीदारी की।

■ बीएसई स्मॉलकैप सूचकांक 0.58 फीसदी टूट गया, जबकि मिडकैप में 0.45 फीसदी गिरावट रही। सेक्टोरल इंडेक्स में यूटिलिटीज सर्वाधिक 0.91% टूट गया।

दवाओं की थोक बिक्री का रखना होगा वीडियो रिकॉर्ड, गोदामों की जियो टैगिंग

कोडीनयुक्त कफ सिरप तस्करी के खुलासे के बाद नियम होंगे सख्त, केंद्र से मांगे दिशानिर्देश

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। कोडीनयुक्त कफ सिरप की तस्करी के खुलासे के बाद दवाओं के थोक बिक्री लाइसेंस की प्रक्रिया व खरीद-फरोख्त के नियम और सख्त होंगे। थोक प्रतिष्ठानों की जियो टैगिंग जरूरी होगी। प्रतिष्ठानों की भंडारण क्षमता से लेकर खरीद-बिक्री के पूरे विवरण की फोटो और वीडियो भी रखना होगा। इससे संबंधित प्रस्ताव खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने शासन को भेजा है।

नशीले कफ सिरप कांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने थोक दवाओं की बिक्री के नियमों को और पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद एफएसडीए की ओर से भेजे गए प्रस्ताव में कई बिन्दुओं को शामिल किया गया है। इसके तहत दवाओं के थोक प्रतिष्ठान के टेक्निकल पर्सन के अनुभव प्रमाण का ड्रग इंस्पेक्टर को सत्यापन करना होगा। केंद्र सरकार कोडीन युक्त काफ सिरप की थोक आपूर्ति और बिक्री की निगरानी के लिए दिशा निर्देश जारी करे इसको भी प्रस्ताव में शामिल किया गया है।

एफएसडीए ने शासन को भेजा प्रस्ताव

थोक बिक्री की लाइसेंस प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने की कवायद

फर्जी बिलिंग पर लगेगी लगाम

- कोडीनयुक्त कफ सिरप मामले की जांच में खुलासा हुआ था कि फर्में विक्रय बिल पेश नहीं कर सकीं। फर्जीवाड़ा करने वाले केवल कागजों पर मौजूद फर्मों के जरिये सिरप का क्रय-विक्रय दिखाती रहीं। किसी भी फुटकर औषधि प्रतिष्ठान को कोडीनयुक्त कफ सिरप की सप्लाई का कोई साक्ष्य नहीं मिला।
- वर्ष 2024-25 में प्रदेश में इस सिरप की आपूर्ति वास्तविक चिकित्सीय जरूरत से कई गुना अधिक की गई। इसे देखते हुए लाइसेंस प्रणाली से लेकर सिरप की बिक्री व निगरानी के लिए सख्त नियम-कानून बनाने की जरूरत बताई गई है।

नशीला सिरप मामला

85 आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी

कोडीनयुक्त कफ सिरप के फर्जीवाड़े मामले में बड़े पैमाने पर कार्रवाई हो चुकी है। प्रदेश के 36 जिलों में सिरप को अवैध तरीके से बेचे जाने की पुष्टि हुई। 161 फर्मों पर केस दर्ज हुए हैं। जांच में सामने आया है कि सात सौ करोड़ से अधिक संदिग्ध आपूर्ति की गई। जांच समिति की तफ्तीश में लगातार सिंडीकेट का नया दायरा सामने आ रहा है। अब तक 79 प्राथमिकी दर्ज हो चुकी हैं और 85 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।

पीएमश्री विद्यालयों में बनेंगे खेल मैदान

ओपेन जिम, बैडमिंटन कोर्ट व बास्केटबॉल जैसी खेल सुविधाओं का होगा विस्तार

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश में पहले और दूसरे चरण में चयनित 532 परिषदीय पीएमश्री कंपोजिट विद्यालयों में खेलकूद सुविधाओं का व्यापक विस्तार किया जाएगा। इसके तहत बच्चों को बेहतर खेल मैदान उपलब्ध कराने के साथ-साथ बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल से जुड़ी सुविधाएं, ओपेन जिम और झूले लगाए जाएंगे। इसके लिए शासन ने कुल 15.57 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया है।

प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ खेलकूद गतिविधियों में भी दक्ष बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पहले जहां खेल सामग्री की खरीद के लिए बजट उपलब्ध कराया गया था, वहीं अब पीएमश्री योजना के तहत चयनित 532 विद्यालयों में आधुनिक खेल मैदान विकसित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड से प्राप्त बजट के तहत प्रत्येक विद्यालय को 2.65 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इस राशि से बैडमिंटन कोर्ट, ओपन जिम, नेट व पोल की स्थापना तथा खेल क्षेत्र का विकास किया जाएगा, जिससे छात्रों को विद्यालय परिसर में ही बेहतर खेल सुविधाएं मिल सकें। साथ ही परिसर में हरित क्षेत्र का विकास किया जाएगा और पहले से लगे पेड़ों का संरक्षण भी सुनिश्चित किया जाएगा।

छात्र पढ़ाई के साथ खेलकूद में भी होंगे दक्ष

15 मार्च तक पूरा करें काम : मोनिका

महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने लखनऊ, अंबेडकरनगर, अमेठी, अयोध्या, बहराइच, रायबरेली, सीतापुर, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर नगर और कानपुर देहात सहित 61 जिलों को पत्र जारी किया है। इसमें निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक और विद्यालय प्रबंध समिति संयुक्त रूप से खेल मैदान के विकास के लिए स्थल का चयन करें। खेल मैदान, झूले, ओपेन जिम और कोर्ट निर्माण का कार्य 15 मार्च तक हर हाल में पूरा किया जाए।

नए साल में टीईटी की अनिवार्यता से राहत दे सरकार : शिक्षक संघ

लखनऊ। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने केंद्र और प्रदेश सरकार से शिक्षकों को नए साल में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनिवार्यता से राहत देने की मांग की है। संघ का कहना है कि पिछले चार महीनों से देश और प्रदेश भर के शिक्षक टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब तक इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। शिक्षकों को उम्मीद है कि नए वर्ष में सरकार इस पर सकारात्मक निर्णय लेगी।

संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील कुमार पांडेय ने बताया कि शिक्षकों ने ज्ञापन सौंपने, हस्ताक्षर अभियान चलाने, सांसदों और विधायकों के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भेजने जैसे कई प्रयास किए हैं। इसके अलावा शिक्षक दिल्ली कूच कर चुके हैं और इस मुद्दे पर शिक्षा मंत्री से भी मिलकर टीईटी से छूट की मांग रखी गई है।

अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने उठाई मांग

उन्होंने कहा कि शिक्षक न केवल शिक्षण कार्य कर रहे हैं, बल्कि दो महीनों से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में भी सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। साथ ही सरकार की विभिन्न योजनाओं को धरातल पर उतारने में भी शिक्षकों की अहम भूमिका है। संघ ने कहा कि अब सरकार का दायित्व बनता है कि शिक्षकों के योगदान का सम्मान करते हुए नए वर्ष में टीईटी अनिवार्यता से छूट का आदेश जारी कर उनकी सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करे। वहीं, शीतलहर को देखते हुए बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए मुख्यमंत्री द्वारा एक जनवरी तक विद्यालय बंद रखने के निर्णय का संघ ने स्वागत किया है। ब्यूरो

स्मार्ट प्रीपेड मीटरों की गुणवत्ता की हो थर्ड पार्टी जांच : वर्मा

लखनऊ। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने घरों में लगाए जा रहे स्मार्ट प्रीपेड मीटरों में खामी का आरोप लगाया है। परिषद के मुताबिक 22 दिसंबर तक प्रदेश में कुल 56.82 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं। इनमें से 37.43 लाख मीटर उपभोक्ताओं की बिना सहमति के प्रीपेड मोड में बदल दिए गए हैं। परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने स्मार्ट प्रीपेड मीटरों में बड़े पैमाने पर तकनीकी कमियां होने का आरोप लगाते हुए इनकी थर्ड पार्टी जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट के अनुसार सभी स्मार्ट प्रीपेड मीटरों का साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट (एसएटी) अनिवार्य है। इस टेस्ट के बाद ही यह प्रमाणित होता है कि ये मीटर सभी तकनीकी मानकों पर सही हैं। लेकिन बिजली कंपनियों ने 34.32 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटरों का ही साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट पूरा किया है। इससे साफ है कि साढ़े बाइस लाख से ज्यादा मीटर बिना जरूरी टेस्ट के ही संचालित किए जा रहे हैं। ऐसे में यह दावा करना कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर पूरी तरह सही तरीके से काम कर रहे हैं, पूरी तरह भ्रामक है। ब्यूरो

बैंकों का सकल एनपीए कई दशक के न्यूनतम स्तर पर

आरबीआई की रिपोर्ट...मजबूत बहीखाते, लाभप्रदता और बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता से मिला समर्थन

मुंबई। वाणिज्यिक बैंकों का प्रदर्शन वित्त वर्ष 2024-25 में मजबूत बना रहा और मार्च के अंत तक सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (जीएनपीए) का अनुपात घटकर 2.2 फीसदी पर आ गया। यह कई दशकों का न्यूनतम स्तर है। आरबीआई ने सोमवार को जारी रिपोर्ट 'भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति 2024-25' में कहा, 2024-25 के दौरान बैंकिंग क्षेत्र अच्छा बना रहा। इसे मजबूत बहीखाते, लगातार लाभप्रदता और बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता का समर्थन मिला। बैंक ऋण और जमा वृद्धि दहाई अंकों में बनी रही। हालांकि, इसमें कुछ नरमी देखी गई। सभी बैंक समूहों में पूंजी और नकदी बफर नियामकीय आवश्यकताओं से काफी ऊपर बने रहे। रिपोर्ट में कहा गया, बैंकिंग क्षेत्र के मजबूत बुनियाद जोखिमों के खिलाफ एक सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं, जो विवेकपूर्ण विनियमन के साथ मिलकर लगातार ऋण प्रवाह के लिए अनुकूल हालात बनाते हैं। एजेंसी

शुद्ध लाभ में 14.8 फीसदी वृद्धि

आरबीआई की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 2024-25 में वाणिज्यिक बैंकों का शुद्ध लाभ बढ़ा। हालांकि, इसकी गति पिछले वर्ष की तुलना में धीमी रही। सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का कुल शुद्ध लाभ 2024-25 में सालाना आधार पर 14.8 फीसदी बढ़कर 4.01 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया। वित्त वर्ष 2023-24 में इनका लाभ 32.8 फीसदी बढ़कर लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपये रहा था।

लाभप्रदता भी मजबूत स्थिति में

रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2024-25 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की लाभप्रदता मजबूत बनी रही। इसमें परिसंपत्तियों पर रिटर्न (आरओए) 1.4 फीसदी और इक्विटी पर रिटर्न (आरओई) 13.5 फीसदी रहा। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में इन बैंकों का आरओए 1.3 फीसदी और आरओई 12.5 फीसदी रहा।

डिजिटलीकरण के चलते एटीएम की संख्या में गिरावट

नई दिल्ली। डिजिटलीकरण में वृद्धि के चलते 2024-25 में ऑटोमैटिक टेलर मशीनों (एटीएम) की संख्या में मामूली गिरावट आई। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार, एटीएम की कुल संख्या 2023-24 के 2,53,417 से घटकर 2024-25 में 2,51,057 रह गई। सरकारी बैंकों के नेटवर्क विस्तार के चलते शाखाओं की संख्या में दो फीसदी से अधिक की वृद्धि हुई।

रिपोर्ट के अनुसार, निजी क्षेत्र के बैंकों का एटीएम नेटवर्क 79,884 से घटकर 77,117 रह गया। सरकारी बैंकों का नेटवर्क 1,34,694 से घटकर 1,33,544 रह गया। एजेंसी

भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेअर अर्थ भंडार

करीब 69 लाख टन के मजबूत भंडार के बावजूद देश का उत्पादन प्रमुख देशों की तुलना में सबसे कम

नई दिल्ली। रेअर अर्थ अयस्क भंडार के मामले में भारत इस समय तीसरे स्थान पर है। हालांकि, इसका उत्पादन प्रमुख वैश्विक देशों की तुलना में सबसे कम है, जो संसाधन उपलब्धता और वास्तविक उत्पादन के बीच भारी अंतर को दर्शाता है। आंकड़ों से पता चला है कि भारत के पास लगभग 69 लाख टन रेअर अर्थ ऑक्साइड (आरईओ) भंडार है। इससे पहले चीन और ब्राजील हैं।

एमिकस के आंकड़ों के अनुसार, चीन के पास 4.4 करोड़ टन भंडार है। ब्राजील के पास 2.1 करोड़ टन का भंडार है। ऑस्ट्रेलिया (57 लाख टन), रूस (38 लाख टन), वियतनाम (35 लाख टन) और अमेरिका (19 लाख टन) शामिल हैं। अपने मजबूत भंडार के बावजूद भारत का उत्पादन सीमित है। 2024 में भारत ने केवल 2,900 टन दुर्लभ धातुओं का उत्पादन किया, जो वैश्विक स्तर पर सातवें स्थान पर रहा। चीन ने 2.7 लाख टन का उत्पादन किया, जिससे वह वैश्विक स्तर पर अग्रणी बन गया। अमेरिका 45,000 टन के साथ दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक था।

भारत के पास वैश्विक रेअर अर्थ खनिजों का करीब 6-7 फीसदी भंडार है। फिर भी वैश्विक उत्पादन में इसका योगदान एक फीसदी से भी कम है। देश के अधिकांश भंडार मोनाजाइट से भरपूर तटीय रेत में पाए जाते हैं, जिनमें रेडियोधर्मी तत्व थोरियम भी मौजूद होता है। इससे खनन और प्रसंस्करण अधिक जटिल हो जाता है और सख्त नियमों के अधीन हो जाता है। नियामक चुनौतियों ने ऐतिहासिक रूप से देश में रेअर अर्थ खनिजों के खनन को धीमा कर दिया है। दशकों तक उत्पादन काफी हद तक सीमित रहा और मुख्य रूप से इंडियन रेयर अर्थ्स लि. (आईआरईएल) नियंत्रित करता था। एजेंसी

चीन 90 फीसदी को करता है नियंत्रित

चीन वैश्विक दुर्लभ पृथ्वी शोधन क्षमता का लगभग 90 फीसदी और भारी रेअर अर्थ तत्वों के करीब संपूर्ण प्रसंस्करण को नियंत्रित करता है। इससे चीन को संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में एक बड़ा लाभ मिलता है। भारत की प्रसंस्करण और शोधन क्षमता बहुत सीमित है। वार्षिक उत्पादन केवल कुछ हजार टन रहा है और वैश्विक रेअर अर्थ धातुओं के व्यापार में भारत की भूमिका लगभग नगण्य रही है।

मकानों की बिक्री में लगातार दूसरे साल रही गिरावट

नई दिल्ली। ऊंची कीमतों के चलते लोगों की खरीदने की क्षमता कम होने से इस वर्ष लगातार दूसरे साल नए मकानों की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई है। 500 अरब डॉलर के इस उद्योग में 2024 में चार फीसदी की कमी दर्ज की गई थी। 2025 में इसमें 14 फीसदी की भारी गिरावट आई है।

एनारॉक के आंकड़ों से पता चला है कि देश के सात प्रमुख शहरों में आवास की बिक्री इस वर्ष 14 फीसदी की गिरावट के साथ लगभग 5.96 लाख यूनिट रह गई। बिक्री बुकिंग का मूल्य 6 फीसदी बढ़कर 6 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गई। एजेंसी

बैंक-वित्तीय संस्थान नहीं कर पाएंगे उत्पादों की मिस-सेलिंग

आरबीआई विज्ञापन, बिक्री और मार्केटिंग के नए मानदंड जारी करने की तैयारी में

मुंबई। बैंक और वित्तीय संस्थान आने वाले समय में उत्पादों की मिस-सेलिंग नहीं कर पाएंगे। आरबीआई इस तरह की बिक्री रोकने के लिए विनियमित संस्थाओं को विज्ञापन, विपणन और बिक्री संबंधी मानदंड जारी करेगा। केंद्रीय बैंक ने कहा, उत्पादों और सेवाओं की गलत बिक्री का ग्राहकों और वित्तीय क्षेत्र दोनों पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।

रिपोर्ट के अनुसार, वसूली एजेंटों की नियुक्ति और ऋण वसूली से संबंधित आचरण पर मौजूदा निर्देशों की समीक्षा करने और इस संबंध में मानकीकृत निर्देश जारी करने का भी प्रस्ताव है। आरबीआई गृह मंत्रालय सहित अन्य हितधारकों के साथ मिलकर डिजिटल और साइबर धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने और ग्राहक सुरक्षा को मजबूत करने के उपायों को विकसित और कार्यान्वित करने के लिए निरंतर काम कर रहा है। फिर भी, विनियमित संस्थाओं को मजबूत आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने, सभी स्तरों पर पर्याप्त शिकायत निवारण अधिकारियों की नियुक्ति सुनिश्चित करने और डिजिटल वित्तीय साक्षरता बढ़ाने की जरूरत है। आरबीआई ऐसे गलत कार्यों को रोकने के लिए एआई का भी उपयोग कर रहा है। एजेंसी

घरेलू विमानन उद्योग को 18,000 करोड़ रुपये तक हो सकता है घाटा

मुंबई। यात्रियों की संख्या में गिरावट और अन्य कारकों के चलते घरेलू विमानन उद्योग को चालू वित्त वर्ष 2025-26 में 17,000-18,000 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हो सकता है। रेटिंग एजेंसी इक्रा ने इससे पहले 9,500-10,500 करोड़ रुपये के घाटे का अनुमान लगाया था।

एजेंसी ने इस वर्ष जून में एअर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान दुर्घटना और इस महीने की शुरुआत में इंडिगो की हजारों उड़ानें रद्द होने सहित कई कारकों के कारण घरेलू हवाई यात्री यातायात वृद्धि के अपने पूर्वानुमान को घटाकर 0 से 3 फीसदी कर दिया है। इक्रा ने कहा, सीमा पार तनाव बढ़ने

के कारण वर्ष के दौरान उड़ानों में व्यवधान और इंडिगो के विमानों के रद्द होने का असर दिखेगा। इसके अलावा, जून में एअर इंडिया विमान दुर्घटना की त्रासदी ने यात्रियों को तुरंत बाद की अवधि में यात्रा करने से हिचकने पर मजबूर कर दिया था। इंडिगो में 3 से 8 दिसंबर तक परिचालन संबंधी व्यवधानों के कारण भी अनुमान में संशोधन किया गया है। एजेंसी

औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर दो साल के उच्च स्तर पर

खनन और विनिर्माण क्षेत्रों के मजबूत प्रदर्शन से नवंबर, 2025 में देश के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर दो साल के शीर्ष पर पहुंच गई। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के मुताबिक, त्योहारों से पहले मांग और खपत बढ़ाने के लिए कई उपभोक्ता वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कटौती करने से विनिर्माण ऑर्डरों में तेजी आई। ब्यूरो

6.7%

औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर नवंबर में पहुंची

- 11.9% रही थी वृद्धि दर इससे पहले नवंबर, 2023 में
- पांच फीसदी बढ़ा था औद्योगिक उत्पादन सूचकांक नवंबर, 2024 में

विनिर्माण क्षेत्र में 23 में से 20 समूहों में सालाना आधार पर सकारात्मक वृद्धि।

इनके उत्पादन में उछाल

08% बढ़ा विनिर्माण क्षेत्र का उत्पादन, एक वर्ष पहले 5.5% था

- 5.4 फीसदी पहुंच गई खनन क्षेत्र की वृद्धि दर 1.9 फीसदी से बढ़कर
- 10.4 फीसदी बढ़ा कैपिटल गुड्स सेगमेंट में उत्पादन
- इन्फ्रा/निर्माण क्षेत्र के उत्पादन की वृद्धि दर बढ़कर 12.1 फीसदी

इनमें गिरावट

- 1.5% रह गई बिजली उत्पादन की वृद्धि दर 4.4% से घटकर
- 10.3% बढ़ा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का उत्पादन, एक साल पूर्व 14.1%
- प्राथमिक वस्तुओं के उत्पादन में भी रही गिरावट

घुसपैठिये कांग्रेस का वोटबैंक, असम की तरह ही पूरे देश से बाहर निकालेंगे : शाह

असम में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा-सवा लाख बीघा भूमि बांग्लादेशियों से मुक्त कराई गई

अमर उजाला ब्यूरो

गुवाहाटी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस असम के लोगों, उनकी संस्कृति, भूमि और पहचान के लिए खतरा उत्पन्न करने वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों को अपना वोट बैंक मानती है। साथ ही कहा, हमारा संकल्प है कि हम न केवल असम, बल्कि पूरे देश से चुन-चुनकर घुसपैठियों को निकालने का काम करेंगे। उन्होंने राज्य की करीब सवा लाख बीघा भूमि घुसपैठियों से मुक्त कराने के लिए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा की तारीफ भी की।

केंद्रीय गृह मंत्री सोमवार को असम के नगांव जिले में श्रीमंत शंकरदेव जी की जन्मस्थली बटाद्रवा थान पुनर्विकास परियोजना का लोकार्पण करने के बाद एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। एक दिन के दौरे पर असम पहुंचे शाह ने कई अन्य कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा, असम की संस्कृति इन घुसपैठियों के कारण दबती जा रही थी लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिमंत बिस्वा सरमा ने इस संस्कृति को घुसपैठियों के प्रभाव से मुक्त कराया है। आज मृदंग और ताल की आवाज के साथ नामघर में भक्ति संगीत गूंजता है।

शाह ने कहा कि वर्षों तक घुसपैठियों के कब्जे में रहे नगांव में विश्व प्रसिद्ध श्रीमंत शंकरदेव के जन्मस्थान को खाली कराकर उसे फिर से विकसित करने का काम आज पूरा हुआ है। जहां शंकरदेव जी ने जन्म लिया और जहां से नव-वैष्णव धर्म को न केवल असम बल्कि पूरे पूर्वोत्तर में धर्म के रूप में प्रचारित करने का काम किया, उस नगांव की भूमि पर आना किसी भी व्यक्ति के लिए बड़ी बात है। बटाद्रवा थान में महापुरुष शंकरदेव जी का आविर्भाव क्षेत्र भी बनाया गया है। इसमें सभी नव वैष्णव धर्म की परंपराओं को जमीन पर उतारने का काम किया गया है।

असम बटाद्रवा थान पुनर्विकास परियोजना का लोकार्पण करने के बाद समारोह में गृह मंत्री शाह।

बोरदोलोई ने असम को भारत में बनाए रखने के लिए नेहरू को किया मजबूर

शाह ने कहा कि ईश्वर की भक्ति करना, अच्छा जीवन जीना और धर्म के आधार पर इस देश को अपनी मातृभूमि मानकर चलने का संदेश श्रीमंत शंकरदेव जी ने दिया। यह पवित्र स्थान केवल एक पूजाघर और नामघर ही नहीं है, बल्कि यह असमिया सद्भाव का जीवंत प्रतीक है। वहीं, भारत रत्न गोपीनाथ बोरदोलोई का स्मरण करते हुए उन्होंने कहा, अगर वे नहीं होते तो हमारा असम और पूरा पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा न होता। गोपीनाथ ने असम को भारत में रखने के लिए देश के प्रथम प्रधानमंत्री को मजबूर कर दिया।

एक भारत के संदेश को मूर्त रूप दे रहे पीएम मोदी

शाह ने कहा कि भारत को तोड़ने की चाह रखने वालों को श्रीमंत शंकरदेव ने 500 साल पहले एक भारत का संदेश दिया था, जिसे आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। शंकरदेव जी के पवित्र स्थान पर घुसपैठिए कब्जा कर बैठे थे, क्या यह ठीक था? उन्होंने कहा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान तक में घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया था लेकिन असम सरकार ने उन्हें खदेड़ने का काम किया जबकि विपक्षी पार्टियों ने वर्षों तक इन्हें संरक्षण दिया।

आईएमडीटी कानून पर विपक्षी दलों को घेरा

शाह ने आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टियां असम की संस्कृति की बात तो करती थीं, लेकिन 1983 में आईएमटीटी कानून लाकर उन्होंने घुसपैठियों को यहां बसने का कानूनी रास्ता दे दिया। विपक्ष की सरकार इतने साल रही, लेकिन उन्होंने असम आंदोलन के शहीदों के लिए कुछ नहीं किया। राज्य की मौजूदा सरकार ने असम आंदोलन के शहीदों की याद में भव्य शहीद स्मारक क्षेत्र का निर्माण किया है। असम की जनता 70 साल की ऐसी उपेक्षा कभी नहीं भूलेगी। उन्होंने कहा कि पूरे उत्तर-पूर्व और विशेषकर असम के विकास के लिए मोदी जी के नेतृत्व में 11 प्रकार के विकास कार्य हुए हैं।

अवैध प्रवासियों के खिलाफ आंदोलन के शहीदों को अर्पित की श्रद्धांजलि...शाह ने असम में अवैध प्रवासियों के खिलाफ आंदोलन के शहीदों को शहीद स्मारक क्षेत्र में श्रद्धांजलि अर्पित की। इस महीने के शुरू में इस स्मारक का उद्घाटन किया गया था।

2026 बनेगा भविष्य का शिल्पकार

संयुक्त राष्ट्र द्वारा तीन समुदायों के लिए घोषित अंतरराष्ट्रीय नववर्ष भविष्य के शिल्पकार हैं, जिन्हें सफल बनाना सबका दायित्व है। मानवता आनंद उल्लास, व आशाओं से लबालब भविष्य की इच्छा के साथ खिलती है। भारत के पास विश्व के सुनहले भविष्य के द्वार खोलने की क्षमता है।

वर्ष 2026 अद्भुत रंगों से सराबोर होगा। किसी वर्ष को इतनी संज्ञाएं, उपमाएं, और भाव कदाचित ही मिले होंगे, जितने 2026 को मिल गए। वर्ष 2026 में संयुक्त राष्ट्र (यूएन) जीवन-विकास के तीन अत्यंत महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालेगा, जो विश्व भर में जीवन, आजीविका, और पारिस्थितिकी तंत्र को उत्कृष्ट आकार देते हैं। सम्मिलित अंतरराष्ट्रीय वर्षों के माध्यम से, यूएन विश्व की सरकारों, समुदायों, और व्यक्तियों को अपने घर की विशिष्टताओं को सँवारने तथा प्रकृति व मानव कल्याण हेतु अनेक कार्यक्रमों में संलग्न होने के लिए आमंत्रित करता है। वर्ष 2026 में चतुर्दिक कल्याण के लिए तो संयुक्त राष्ट्र ने जैसे अपने हृदय-पटल ही खोल दिए हों!

वीर सिंह
प्रो. एमेरिटस, कॉलेज ऑफ कृषि एवं प्रौद्योगिकी, विश्वविद्यालय

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 को त्रिआयामी अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है: अंतरराष्ट्रीय चरवाह और पशुपालक वर्ष, सतत विकास के लिए स्वयंसेवकों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, और महिला किसान का अंतरराष्ट्रीय वर्ष। एक वर्ष में तीन अंतरराष्ट्रीय वर्षों का आनुष्ठान। प्रत्येक अनुष्ठान सतत विकास में एक आवश्यक, किंतु विस्मृत-से योगदानकर्ता पर प्रकाश डालता है।

विश्व में सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक, और पारिस्थितिक विकास में चरवाहों, चरवाहों, महिला कृषकों और स्वयंसेवकों का महत्वपूर्ण योगदान है। परंतु विडंबना है कि ये सभी योगदानकर्ता हमारी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के हाशिये पर हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को इन विस्मृतों के नाम कर उनकी उपेक्षा के कारण बनी खाई को भरने का सराहनीय प्रयास किया है।

चरवाह पृथ्वी के लगभग आधे भू-भाग पर फैले हैं। विश्व के पर्वतीय क्षेत्रों में तो लगभग 70 प्रतिशत हिस्से पर चरागाह ही हैं। विण्टिट वनों, घास के मैदानों, सवाना, अर्द्धभूमि, टुंड्रा, और सरस्थलों की गोद में बसे ये अनूठे पारिस्थितिक तंत्र जैव विविधता के घर हैं। करोड़ों पशुपालकों की आजीविका के आधार हैं। इनकी जैव-विविधता में पौधों और जंतुओं की अनेक दुर्लभ, संकटग्रस्त, और लुप्तप्राय प्रजातियां हैं, जो तब तक संरक्षित

हैं, जब तक ये सुरक्षित हैं। चरागाहों पर निर्भर पशुपालक अपने पशुधन के जरिये करोड़ों लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। लगभग 150 देशों में रहने वाले और विश्व की कम से कम एक-चौथाई भूमि का प्रबंधन करने वाले ये पशुपालक लगभग एक अरब पशुओं को पालते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में तो समुदायों की सारी कृषि क्रियाएं पशुधन पर ही निर्भर हैं। चरवाहों की जीवनशैली प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करती है, स्थानीय व स्वदेशी सामुदायिक ज्ञान को जीवंत और संवर्धित रखती है, तथा सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करती है। चरागाहों तथा चरवाहों के अंतरराष्ट्रीय वर्ष में चरवाहा समुदायों के लिए भूमि व प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करने, उनकी नीतिशीलता को समर्थन देने तथा चरागाह प्रबंधन, पुनरुद्धार, पशु सेवाओं एवं उचित मूल्य शृंखलाओं को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। समवेशी संवाद और सहयोग को प्रोत्साहित करके, इस वर्ष का उद्देश्य पशुपालकों की आजीविका में सुधार लाना व टिकाऊ चरागाह प्रबंधन तथा सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाना है।

कृषि उत्पादन में महिला किसानों की भूमिका पर प्रायः चर्चा नहीं होती। खेतों में बीज बोने से लेकर रोपे बनाने तक और संपूर्ण सस्य क्रियाओं के ज्ञान से लेकर नवाचार तक महिलाएं केंद्रीय भूमिका में हैं। अनेक आदिवासी और पर्वतीय क्षेत्रों में तो संपूर्ण कृषि जिम्मा महिलाओं द्वारा ही संचालित होती है। महिलाओं की बहुसंख्य लघु और सीमांत किसान, मौसमी श्रमिक, मछुआरे, पशुपालक, मधुमक्खी पालक, वनपाल, प्रसंस्करणकर्ता, व्यापारी, वैज्ञानिक, परंपरिक ज्ञानधारक और ग्रामीण उद्यमी कई भूमिकाओं में देखी जा सकती है। उनका महत्वपूर्ण योगदान खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सरोकारों तथा संस्कारों को अक्षुण्ण रखना है। फिर भी, उन्हें प्रायः वह मान्यता नहीं मिलती, जो मिलनी चाहिए।

अंतरराष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष का उद्देश्य कृषि में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देना, उनके सशक्तीकरण को बढ़ावा देना तथा खाद्य सुरक्षा में योगदान देना है। महिला किसानों को संसाधनों तक पहुंच, भूमि स्वामित्व और निर्णय लेने के मामलों में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस वर्ष का उद्देश्य इन असमानताओं को दूर करना तथा कृषि में उनकी भागीदारी को समर्थन देने वाली नीतियों को प्रोत्साहन देना है। अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष लैंगिक अंतर को कम करने, संसाधनों और सेवाओं तक पहुंच में सुधार लाने तथा कृषि खाद्य प्रणालियों में महिला नेतृत्व को समर्थन देने को बढ़ावा देगा।

विश्व कल्याण के लिए जो अपना सर्वस्व देने को तैयार रहता है, उसके अंदर एक स्वयंसेवक छिपा होता है। मानव समाज में स्वयंसेवकों की कमी नहीं। प्रति दिन लाखों स्वयंसेवक लोगों को परामर्श देकर, स्वास्थ्य प्रणालियों का समर्थन करके, पर्यावरण संरक्षण प्रक्रियाओं को बल देकर, अथवा आपत्त स्थितियों में राहत देकर सामाजिक भलाई के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। स्वयंसेवा सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति को एक सटीक दिशा देती है। स्वयंसेवकों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष अधिकाधिक लोगों को स्वयंसेवा के लिए प्रोत्साहित करेगा। यह इस बात पर प्रकाश डालने का अवसर है कि कैसे प्रकार स्वयंसेवा लोगों को जोड़ती है, स्थानीय समाधान को आगे बढ़ाती है तथा स्थायी प्रभाव पैदा करती है।

त्रिआयामी अंतरराष्ट्रीय नववर्ष सचमुच हमारे लिए भविष्य के शिल्पकार की तरह आ रहा है, जिसे सफल बनाना हमारा दायित्व है। मानवता सदैव एक आनंद, उल्लास, और आशाओं से लबालब भविष्य की प्रबल इच्छा के साथ खिलती है। जीवन का यही मूल है। त्रिआयामी कल्याणकारी उद्देश्यों को लेकर उपस्थित हुआ नववर्ष 2026 सुख, शांति, आनंद, सर्व कल्याण और संतोष के साथ जीने वाले समाज की आशाओं को सींचने का संकल्प लेकर आया है। भारत के सुनहले भविष्य के द्वार तभी खुलेंगे, जब अतिवाद के बिच-बीच निर्मूल होंगे। इसके लिए सार्थक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रयासों की आवश्यकता है। भारत संपूर्ण विश्व के लिए सुनहले भविष्य के द्वार खोलने की क्षमता रखता है। बस राजनीतिक इच्छा-शक्ति को जगाने भर की देर है।

editor@amarujala.com

दुनिया में भारी अशांति के बीच हमारी अर्थव्यवस्था सबसे अलग

सुधार, समायोजनीयता और संकल्प ने बढ़ाई विकास की गति

पिछले पांच वर्षों में आए कई वैश्विक झटकों ने दुनियाभर में अस्थिरता और अनिश्चितता का माहौल पैदा किया है। साल 2025 अब तक भू-राजनीतिक बिखराव, व्यापारिक अनिश्चितता, आपूर्ति शृंखला में बदलाव और तकनीकी वर्चस्व की जंग के नाम रहा है। दुनिया के इस अशांत माहौल के बीच, भारत की सूक्ष्म अर्थव्यवस्था सबसे अलग दिखती है। हालिया तिमाही में भारत की विकास दर 8.2 फीसदी रही है, जिसने बड़े-बड़े जानकारों के अनुमानों को भी पीछे छोड़ दिया है। राहत की बात है कि महंगाई और राजकोषीय घाटा नियंत्रण में है। तमाम बाहरी चुनौतियों के बावजूद, भारत की नीतियों का मुख्य उद्देश्य घरेलू अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत एवं लचीला बनाना रहा है।

अमिताभ कांत

पूर्व जी20 शेरपा और नीति आयोग के सीईओ

तमाम बाहरी चुनौतियों के बावजूद, भारत की नीतियों का मुख्य उद्देश्य घरेलू अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत एवं लचीला बनाना रहा है।

किसी भी मजबूत अर्थव्यवस्था की असली बुनियाद घरेलू मांग होती है। करोड़ों भारतीय परिवारों के लिए कर नीतियों में बदलाव, खपत बढ़ाने का बड़ा जरिया साबित हुआ है। इस साल भारत ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के टैक्स सुधारों को अपनाया है। फरवरी, 2025 में पेश किए गए बजट में 12 लाख रुपये तक की सालाना आय को करमुक्त किया गया था, जिससे लोगों के हाथों में ज्यादा पैसा आया। साथ ही, पुराने जटिल कानूनों की जगह नया आयकर अधिनियम-2025 लागू किया गया। इसके बाद सितंबर में जीएसटी को और आसान बनाते हुए इसे दो स्लैब में रखा गया। इन सुधारों का असर यह रहा कि त्योहारी सीजन में 6 लाख करोड़ रुपये की रिकॉर्ड बिक्री हुई। खास बात है कि टैक्स में राहत देने से सरकारी खजाने को नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि बाजार में बढ़ी मांग एवं खपत के कारण आने वाले समय में टैक्स संग्रह के और बढ़ने की उम्मीद है। हमारी अर्थव्यवस्था का करीब 55-60 फीसदी हिस्सा घरेलू खपत पर आधारित है। जैसे-जैसे खपत बढ़ती है, उद्योगों की उत्पादन क्षमता का भी बेहतर इस्तेमाल होने लगता है। उत्पादन जब अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच जाता है, तो अर्थव्यवस्था में निवेश भी बढ़ता है, जिसके कई सकारात्मक प्रभाव होते हैं।

श्रम कानूनों में सुधार से बढ़ेगी आय : *उपभोक्ता मांग लंबे समय तक तभी बनी रह सकती है, जब लोगों की आय में भी लगातार बढ़ोतरी हो। श्रम कानूनों में सुधार यह सुनिश्चित करेंगे। 29 पुराने और बिखरे कानूनों की जगह चार आधुनिक श्रम संहिताएं लागू होने से अब भारत का श्रम ढांचा व्यवसायों के लिए अधिक पारदर्शी और श्रमिकों के लिए ज्यादा सुरक्षित हो गया है। श्रम कानूनों में ये आवश्यक सुधार यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारा 64 करोड़ का विशाल कार्यबल समृद्ध बने एवं भारत की विकास की रफ्तार को और तेज बनाए।*

बिहार तकनीकी सेवा आयोग

जूनियर इंजीनियर के पदों पर उम्मीदवार करें आवेदन

2809 पद

आवेदन की अंतिम तिथि : 12 जनवरी, 2026
वेतनमान : रुपये 9,300 से लेकर रुपये 34,800 तक निर्धारित
यहां आवेदन करें : btsc.pariksha.nic.in

मध्य-प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ■ 474 पद

मेडिकल सोशल वर्कर व अन्य पदों पर करें अप्लाई

आवेदन की अंतिम तिथि
07 जनवरी, 2026

आयु-सीमा
न्यूनतम 18 वर्ष व अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित

यहां आवेदन करें
esb.mp.gov.in

इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज ■ 215 पद

टेक्नीशियन, ऑपरेटर आदि के पद खाली

आवेदन की अंतिम तिथि
12 जनवरी, 2026

वेतनमान
एमबीए, बीई, बीटेक व अन्य निर्धारित पात्रताएं

यहां आवेदन करें
itiltd.in

दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ■ 714 पद

मल्टी टास्किंग स्टाफ के पदों पर उम्मीदवार करें आवेदन
आवेदन की अंतिम तिथि : 15 जनवरी, 2026
आयु-सीमा : न्यूनतम 18 वर्ष व अधिकतम 27 वर्ष निर्धारित
यहां आवेदन करें : dsssb.delhi.gov.in

आईआईटी, मंडी में संभावनाएं ■ 31 पद

कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पदों पर रिक्तियां

आवेदन की अंतिम तिथि
06 जनवरी, 2026

पात्रताएं
बीएससी, बीई, बीटेक व अन्य निर्धारित योग्यताएं

यहां आवेदन करें
iitmandi.ac.in

आरसीएफएल में नौकरी के मौके ■ 10 पद

सीनियर इंजीनियर व मैनेजर के पद खाली

आवेदन की अंतिम तिथि
17 जनवरी, 2026

पात्रताएं
बीई, बीटेक व अन्य निर्धारित योग्यताएं

यहां आवेदन करें
rcfltd.com

यहां भी रोजगार की संभावनाएं ...

- **प्रसार भारती, नई दिल्ली :** कॉपीराइटर व कॉपी एडिटर के पदों पर निकली भर्ती।

  आवेदन की अंतिम तिथि : 09 जनवरी, 2026

- **prasarbharati.gov.in**
- **भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली :** सीनियर प्रोजेक्ट असिस्टेंट का पद खाली।

  आवेदन की अंतिम तिथि : 07 जनवरी, 2026

- **ird.iitd.ac.in**

अवसर यहां भी...

ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का मशीन लर्निंग फ्री कोर्स

अगर आप मशीन लर्निंग (एमएल) की अवधारणा और तकनीक की मूलभूत समझ हासिल करना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि इसकी शुरुआत कहां से करें, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त ऑक्सफोर्ड होम स्टडी सेंटर की ओर से शुरू किया गया मशीन लर्निंग शॉर्ट टर्म कोर्स आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। इस 200 घंटे के कोर्स में आप सीखेंगे कि मशीन लर्निंग (एमएल) क्या है और स्वास्थ्य सेवा से लेकर वित्त तक विभिन्न क्षेत्रों में मशीन लर्निंग इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? इंटरैक्टिव पाठों और व्यावहारिक अभ्यासों के माध्यम से आप मशीन लर्निंग में एक मजबूत आधार विकसित करेंगे और जानेंगे कि यह शक्तिशाली तकनीक भविष्य को कैसे आकार दे रही है। इस कोर्स की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे आप कभी भी अपनी सुविधानुसार कर सकते हैं और यह निःशुल्क है। साथ ही इस कोर्स को करके अपने सीवी को बेहतर बना सकते हैं। आप अपनी पात्रताओं की जांच कर आधिकारिक लिंक tinyurl.com/3cdtyzfd पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से इस कोर्स में दाखिला ले सकते हैं।

46वां इंटरनेशनल इलस्ट्रेशन कॉन्टेस्ट

46वें इंटरनेशनल इलस्ट्रेशन कॉन्टेस्ट के लिए दुनिया भर के कलाकारों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इस कॉन्टेस्ट की थीम बिल्ली रखी गई है। आप कॉन्टेस्ट के लिए बिल्लियों का एक प्यारा व आकर्षक चित्र बनाएं, जिसमें उनकी खूबसूरती, चंचलता और शरारती अंदाज साफ दिखाई दे। कॉन्टेस्ट के विजेताओं को बतौर ग्रैंड प्राइज 2000 डॉलर का नकद पुरस्कार, दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले विजेता को 500 डॉलर का नकद पुरस्कार, तीसरे से लेकर पांचवां स्थान प्राप्त करने वाले विजेता को 200-200 डॉलर का नकद पुरस्कार, छठे से लेकर दसवां स्थान प्राप्त करने वाले विजेता को 100-100 डॉलर का नकद पुरस्कार, साथ अन्य विजेताओं को भी कई अन्य लाभ दिए जाएंगे। कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए आवेदक आधिकारिक लिंक clipstudio.net/en/cspcontest46 पर जाकर 05 जनवरी, 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।

डाटा साइंस पर स्प्रिंग इंटर्नशिप प्रोग्राम-2026

यदि आप डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में व्यावहारिक कौशल और मार्गदर्शन प्राप्त करने के इच्छुक छात्र या डाटा साइंटिस्ट हैं, तो आप 21 जनवरी, 2026 से कोलकाता स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान में आईडीईएएस टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब द्वारा आयोजित स्प्रिंग इंटर्नशिप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में आवेदन के लिए जरूरी है कि आप किसी भी कॉलेज या विश्वविद्यालय के स्नातक या स्नातकोत्तर कोर्स में अध्ययनरत हों। इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के दौरान आपको डाटा संरचनाएं और एल्गोरिदम, पाइथन प्रोग्रामिंग व संचार कौशल आदि सीखने का अवसर मिलेगा। साथ ही उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण और अनुभवी मेंटरों के मार्गदर्शन में व्यावहारिक प्रोजेक्ट कार्य में शामिल होने का मौका भी मिलेगा। इसमें छात्रों को समयानुसार दो इंटर्नशिप प्रोग्राम, मूलभूत इंटर्नशिप (4 सप्ताह) व उन्नत इंटर्नशिप (10 सप्ताह) का विकल्प दिया गया है। छात्र अपनी अर्हता की जांच करते हुए आधिकारिक लिंक ideas-tih.org/springinternship2026 पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से 14 जनवरी, 2026 तक पंजीकरण कर सकते हैं।

30 दिसंबर, 1986

आज का दिन

ब्रिटिश सरकार ने कोयला खदानों में जहरीली गैसों का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सेंसर का उपयोग करने की घोषणा की। पहले यह काम कनारी चिड़ियों की मदद से किया जाता था।

- 1922 : सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ की स्थापना हुई थी। इसकी राजधानी मॉस्को थी।
- 1965 : फर्डिनेंड मार्कोस ने फिलीपींस के दसवें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी।
- 1975 : अमेरिकी गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स का जन्म हुआ था।
- 2014 : जर्मन मूल की अभिनेत्री लुईस रेनर का निधन हुआ था।

व्रत त्योहार

आज : पौष शुक्ल पक्ष दशमी/एकादशी
कल : शिशिर ऋतु, सूर्य उत्तरायणे, दक्षिण गोले।
राहुकाल : दिन में 12.00 से 13.30 तक

कल का पंचांग

सूर्योदय : 07.18
सूर्यास्त : 17.30
(भारतीय मानक समयानुसार)

विक्रमी संवत 2082, 10 पौष मास शक 1947, पौष मास 17 प्रविष्टे, 10 रज्जव हिजरी 1447, पौष शुक्ल पक्ष द्वादशी 25.47 तक उपरांत त्रयोदशी, कृतिका नक्षत्र 25.29 तक उपरांत रोहिणी नक्षत्र, साध्य योग 21.12 तक उपरांत शुभ योग, वव करण 15.23 तक उपरांत वालव करण, चंद्रमा वृष राशि में 09.20 बजे।

amarujala.com/astrology

राशिफल

पं. विनोद त्यागी

मेष : भाग्य सहायक रहेगा। योजना में सफलता मिलेगी। नौकरी में उन्नति का लाभ मिल सकता है।

वृष : मानसिक चिंतन बना रहेगा। पूर्व नियोजित कार्य अधूरे रहेंगे। ऋण में वृद्धि होगी। सेहत का ध्यान रखें।

मिथुन : सामाजिक मान-सम्मान बढ़ेगा। नई योजना में सफलता मिलेगी। सुख साधनों में वृद्धि हो सकती है।

कर्क : सरकारी क्षेत्र में बनता कार्य अटक सकता है। नौकरी में मान सम्मान बना रहेगा। अर्थ प्राप्ति संभव है।

सिंह : उतावलेपन में निर्णय लेने से बचें। कानूनी मामले में परेशानी होगी। नौकरी में स्थिति यथावत रहेगी।

कन्या : राजनीतिक संबंध सहायक रहेंगे। भू-संपत्ति में वृद्धि हो सकती है। आर्थिक क्षेत्र में सावधानी बरतें।

तुला : रोजगार प्राप्ति के अवसर मिलेंगे। अटके कार्य में सफलता मिलेगी। नौकरी में अधिकारी अनुकूल रहेंगे।

वृश्चिक : क्रोध एवं वाणी पर नियंत्रण रखें। भू-संपत्ति के बनते कार्य अटक सकते हैं। अर्थ प्राप्ति के अवसर मिलेंगे।

धनु : मानसिक उलझन बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र में व्यस्तता बढ़ेगी। नए कार्य में पूंजी निवेश से बचें।

मकर : भविष्य के प्रति चिंतित रहेंगे। कार्य क्षेत्र में प्रतिष्ठा बनी रहेगी। संपत्ति संबंधी विवाद से बचें।

कुंभ : नौकरी में मान-सम्मान बढ़ेगा। कार्य विशेष में अनुकूल सफलता मिलेगी। किसी इच्छा की पूर्ति संभव है।

मीन : विरोधी पक्ष से सावधानी बरतें। नौकरी में स्थिति अनुकूल रहेगी। स्वजनों से वाद-विवाद संभव है।

जन्मदिन

गुरलीन चोपड़ा, अभिनेत्री

इस वर्ष उद्देश्य पूर्ति के लिए परिश्रम की अधिकता रहेगी। किसी नई योजना का प्रारंभ हो सकता है। आर्थिक दृष्टि से वर्ष अनुकूल रहेगा। विवाह या संतान सुख की इच्छा पूर्ण होगी। मकान या प्लॉट क्रय हो सकता है। शुभचिंतकों का सहयोग उन्नति में सहायक रहेगा। रोजगारपरक परीक्षाओं में सफलता मिलेगी।

सुडोकू

8				3	6		2	7
				2				4
					5	1		
	2					7		
	1	7				2	8	
		5					6	
		3	2					
1				8				
7	4		3	5				6

सुडोकू 81 वर्गों का ग्रिड है, जो 9 वर्गों के ब्लॉक में बंटा हुआ होता है। कुछ वर्गों के अंक लिखे हैं और खाली वर्गों में 1 से लेकर 9 तक के अंक लिखने होते हैं। कोई नंबर 1 पंक्ति, कॉलम या 9 वर्ग वाले छोटे ब्लॉक में दोबारा नहीं आ सकता है।

उत्तर

8	9	4	1	3	6	5	2	7
3	5	1	7	2	8	6	9	4
2	7	6	9	4	5	1	3	8
9	2	8	6	1	3	7	4	5
6	1	7	5	9	4	2	8	3
4	3	5	8	7	2	9	6	1
5	8	3	2	6	1	4	7	9
1	6	9	4	8	7	3	5	2
7	4	2	3	5	9	8	1	6

डेली हेल्थ कैप्सूल

स्वस्थ आंखों के लिए अदरक तेल की मालिश

अदरक के तेल से पैरों की मालिश करने से आंखों की बीमारियां दूर होती हैं। इससे शरीर भी तरोताजा रहता है।

आजकल स्क्रीन टाइम के बढ़ने से तनाव, थकान और आंखों की कमजोरी की समस्या आम हो गई है। इससे निजात पाने और आंखों को स्वस्थ रखने के लिए आप अदरक के तेल से नियमित तौर पर पैरों की मालिश कर सकते हैं। इसे पादाभ्यंग कहा जाता है। आयुर्वेद के अनुसार, पैरों में कई महत्वपूर्ण मर्म और नाड़ियां होती हैं, जो सीधे आंखों

से जुड़ी होती हैं। पैरों पर इस तेल से मालिश करने से आंखों का तनाव दूर होता है, रोशनी तेज होती है और ड्राई आई जैसी समस्याओं से भी बचाव होता है। अदरक के तेल की प्रकृति गरम होने के कारण इससे रक्त संचार तेज होता है। इससे वात दोष संतुलित रहता है। इस तेल की मालिश से आंखों तक पोषण पहुंचता है और थकान कम होती है। रात के समय (सोने से पहले) पैरों की हल्की मालिश करने से आंखें स्वस्थ रहती हैं और नींद भी अच्छी आती है। मालिश के लिए अदरक का तेल लें या तिल के तेल में अदरक मिलाकर इसे हल्का गुनगुना करें और पैरों के तलवों, एड़ियों और उंगलियों पर 10 से 15 मिनट तक मालिश करें। आप चाहे तो मालिश के बाद गरम पानी से पैर धो लें, फिर मोजे पहनकर सो जाएं।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ

अदरक के तेल को नारियल, जैतून या तिल के तेल में मिलाकर पतला करें। सीधे लगाने से जलन हो सकती है। एजर्ली का पता लगाने के लिए पैच टेस्ट करें। बीमारी है तो चिकित्सक से सलाह लें। -डॉ. आर.पी. पाराशर वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक

जुरेल का लिस्ट ए में पहला शतक, बड़ौदा को 54 रन से हराकर यूपी की तीसरी जीत

विजय हजारे ट्रॉफी : ध्रुव ने 101 गेंद में बनाए 160 रन, दिल्ली की जीत में नहीं चला पंत का बल्ला

राजकोट/जयपुर। विजय हजारे ट्रॉफी के तीसरे दौर में सोमवार को उन दो विकेटकीपर-बल्लेबाजों पर निगाहें थीं जो सफेद गेंद के प्रारूप में भारतीय टीम में जगह बनाने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। सोमवार को इस परीक्षा में दिल्ली के ऋषभ पंत के मुकाबले यूपी के ध्रुव जुरेल ने अपने बल्ले से छाप छोड़ी। जुरेल ने लिस्ट ए में अपना पहला शतक जड़ते हुए उत्तर प्रदेश को ग्रुप बी में बड़ौदा पर 54 रन से जीत दिला दी।

यह यूपी की लगातार तीसरी जीत है और वह ग्रुप में शीर्ष पर है। जुरेल ने 101 गेंदों में नाबाद 160 रन की पारी खेली जिसमें उन्होंने 15 चौके और आठ छक्के लगाए। जुरेल की इस पारी की बदौलत यूपी ने सात विकेट पर 369 रन बनाए। जवाब में उसने जीशान अंसारी (3/53) की शानदार गेंदबाजी के दम पर बड़ौदा को 50 ओवर में 315 रन पर समेटकर जीत हासिल कर ली। ग्रुप डी में दिल्ली को भी सौराष्ट्र पर तीन विकेट से जीत मिली, लेकिन ऋषभ पंत का बल्ला नहीं बोला। उन्होंने 26 गेंद में सिर्फ 22 रन ही बनाए। प्रियांश आर्य (45 गेंद में 78) और तेजस्वी दहिया (51 गेंद में 53) रन की बदौलत दिल्ली ने 321 रन के लक्ष्य को 48.5 ओवर में हासिल कर लिया। दिल्ली भी ग्रुप डी में तीन जीत के साथ शीर्ष पर है। एजेंसी

ध्रुव ने 160 रन की पारी में 15 चौके और आठ छक्के लगाए।

विराट एक और मैच खेलेंगे

सौराष्ट्र के खिलाफ मैच में विराट कोहली नहीं खेले। विराट ने पहले दो मैचों में दिल्ली के लिए 131 और 77 रन की पारियां खेलीं, लेकिन डीडीसीए के अध्यक्ष रोहन जेटली के मुताबिक विराट छह जनवरी को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेंगलूरु में होने वाले मैच में रेलवे के खिलाफ खेलेंगे।

- *सौराष्ट्र ने विश्वराज सिंह जडेजा के 115 रन और रुचिर अहीर के नाबाद 95 रन से सात विकेट पर 320 रन बनाए। नवदीप सैनी ने 41 रन पर तीन विकेट लिए। दिल्ली को अंतिम 12 ओवर में 73 रन चाहिए थे और चार विकेट हाथ में थे। यहां से हर्ष त्यागी (49) और नवदीप सैनी (34*) ने साझेदारी कर दिल्ली को जीत दिला दी।*

उत्तराखंड से हारा पंजाब

पंजाब के कप्तान अभिषेक शर्मा (30) बल्ले से कमाल नहीं दिखा पाए जिसके चलते पंजाब को उत्तराखंड के हाथों ग्रुप सी में पांच विकेट से हार मिली। पंजाब ने 8 विकेट पर 269 रन बनाए। सलिल अरोड़ा ने 65, कृष भगत ने 51 रन बनाए। मयंक मिश्रा ने 36 रन पर दो विकेट लिए। कुनाल चंदेला के 114 गेंद में 118 रन की पारी से उत्तराखंड ने 47.4 ओवर में 5 विकेट पर 270 रन बनाकर जीत हासिल कर ली। शाश्वत डंगवाल ने 38 गेंद में नाबाद 51 रन की पारी खेली। अभिषेक ने 39 रन पर दो विकेट लिए।

- इसी ग्रुप में मुंबई ने छत्तीसगढ़ को नौ विकेट से हराया। शार्दुल ठाकुर (4/13), शम्स मुलानी (5/31) की गेंदबाजी से छत्तीसगढ़ 142 पर सिमट गया। मुंबई ने 24 ओवर में एक विकेट पर 144 रन बनाकर जीत हासिल कर ली। पिछले मैच में चोटिल हुए रघुवंशी ने नाबाद 66, सिद्धेश लाड ने 48 रन बनाए।
- ग्रुप डी में हरियाणा ने गुजरात को 26 रन से हराया। हरियाणा ने मयंक शांडिल्य के 86, हिमांशु राणा के 57, सामंत जाखड़ के 49 रन से 49.4 ओवर में 299 बनाए। जवाब में उसने गुजरात को 47.1 ओवर में 273 रन पर समेट दिया। अंशुल कंबोज ने 49 पर तीन और पार्थ वत्स ने 16 रन पर तीन विकेट लिए।

ध्रुव ने रिंकू और प्रशांत वीर के साथ निभाईं शतकीय साझेदारियां

63 रन की पारी खेली यूपी के कप्तान रिंकू ने

बड़ौदा के खिलाफ यूपी को अभिषेक गोस्वामी (51) और अर्यन जुयाल (26) ने 77 रन की साझेदारी कर अच्छी शुरुआत दी। 92 रन पर तीन विकेट खोने के बाद ध्रुव और पिछले मैच में शतक लगाने वाले कप्तान रिंकू सिंह ने मोर्चा संभाल लिया। दोनों ने 131 रन की साझेदारी की। रिंकू 67 गेंद में दो चौकों और तीन छक्कों की मदद से 63 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद ध्रुव ने छठे विकेट के लिए प्रशांत वीर (35) के साथ 122 रन की साझेदारी कर यूपी को 300 के पार कराया। राज लिंबानी ने 74 रन पर चार विकेट लिए। ध्रुव ने रविवार सलाम को जमकर निशाना बनाया। उन्होंने सात ओवर में 40 रन दिए थे, लेकिन अंतिम तीन ओवर में उन्होंने 62 रन लुटाए और 10 ओवर में 102 रन देकर एक विकेट लिया। बड़ौदा के लिए शाश्वत (60) और कप्तान क्रुनाल पंड्या (82) ने अच्छी पारियां खेलीं। विप्रज, समीर ने दो-दो विकेट लिए।

जीएसटी पोर्टल पर नोटिस अपलोड करना पर्याप्त तामील नहीं : कोर्ट

हाईकोर्ट ने कहा-पोर्टल अंग्रेजी में...राज्य की मुख्य भाषा हिंदी है, छोटे व मध्यम व्यापारियों के लिए नोटिस खोजना कठिन

अमर उजाला ब्यूरो

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जीएसटी पोर्टल पर केवल नोटिस या आदेश अपलोड कर देना कानूनी रूप से पूर्ण सूचना नहीं मानी जा सकती। नोटिस या आदेश करदाता की जानकारी में आने के बाद ही अपील दायर करने की समय-सीमा शुरू होगी। इस टिप्पणी संग न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह, न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने गाजियाबाद की मेसर्स बैम्बिनो एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड सहित 13 याचिकाएं स्वीकार कर लीं।

याचियों ने शिकायत की कि कारण बताओ नोटिस और अंतिम आदेश उन्हें न देकर विभाग ने जीएसटी पोर्टल पर अपलोड कर दिया। इससे उन्हें समय पर नोटिस और आदेश की जानकारी नहीं हो सकी। विभाग ने वसूली की कार्रवाई शुरू की तो उन्हें आदेश का पता चला पर तब तक अपील करने की निर्धारित 120 दिनों की अवधि समाप्त हो चुकी थी। इसके खिलाफ याची फर्मों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद माना

कि बिना उचित सूचना के एकपक्षीय आदेश पारित करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। कोर्ट ने संज्ञान लिया कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां हिंदी मुख्य भाषा है, जीएसटी पोर्टल पूरी तरह अंग्रेजी में है। ऐसे में छोटे और मध्यम व्यापारियों के लिए पोर्टल के विभिन्न 'टैब' में जाकर नोटिस खोजना कठिन है। कोर्ट ने इन सभी मामलों में एकपक्षीय आदेशों को रद्द कर व्यापारियों को अपील दायर करने के लिए नया अवसर प्रदान किया। साथ ही निर्देश दिया कि यदि करदाता विवादित टैक्स की 10 प्रतिशत राशि जमा करते हैं तो उनके मामलों की नए सिरे से सुनवाई की जाए।

कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्रीय अधिकारी अभी भी भौतिक रूप से नोटिस भेज रहे हैं, जबकि राज्य के अधिकारी पूरी तरह से डिजिटल मोड पर चले गए हैं। इससे करदाताओं को अपील करने में दिक्कत हो रही है।

अपंजीकृत की शुद्धता साबित करना दावेदार की जिम्मेदारी

प्रयागराज। हाईकोर्ट ने कहा कि अपंजीकृत वसीयत की शुद्धता साबित करने का भार उत्तराधिकार का दावा पेश करने वाले पक्षकार पर ही होता है। हालांकि, कानून की नजर में खरी वसीयत वही है जो पंजीकृत हो। इस टिप्पणी संग न्यायमूर्ति संदीप जैन की अदालत ने भतीजों की ओर से पेश अपंजीकृत वसीयत के आधार पर किए गए दावे को खारिज कर दिया। साथ ही वाराणसी ट्रायल कोर्ट की ओर से बेटी सुधा व दूसरी बेटी के बच्चों के नाम की गई पंजीकृत वसीयत को वैध मानने वाले आदेश पर अपनी मुहर लगा दी। मामला वाराणसी के नवाबगंज क्षेत्र स्थित आवासीय मकान सहित अन्य संपत्तियों के उत्तराधिकार से जुड़े पुराने विवाद से है। ब्यूरो

बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की कैविएट प्रक्रिया में खामी, दिए निर्देश

प्रयागराज। हाईकोर्ट ने राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) की कैविएट प्रक्रिया में गंभीर खामी पाए जाने पर इसे सुधारने के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं। न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की एकलपीठ ने कहा कि कैविएट दायर होने के बावजूद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की रजिस्ट्री की ओर से कैविएटर या उसके अधिवक्ता को कोई सूचना नहीं दी जाती। इससे न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित होती है। मथुरा निवासी त्रिभुवन गोयल की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह टिप्पणी की। ब्यूरो

दौड़ लगाकर विद्यार्थी आत्मनिर्भर भारत, राष्ट्रीय एकता का देंगे संदेश

देश के सभी शिक्षण संस्थानों में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर रन फॉर स्वदेशी का आयोजन

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। देश के सभी शिक्षण संस्थानों में 12 जनवरी को रन फॉर स्वदेशी का आयोजन होगा। स्वामी विवेकानंद की 164वीं जयंती के मौके पर राष्ट्रीय युवा दिवस के तहत यह राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आयोजित होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने इस संबंध में सभी राज्यों को पत्र लिखा है। इसमें दो से पांच किलोमीटर की दौड़ के माध्यम से युवाओं को स्वदेशी मूल्य, आत्मनिर्भर भारत, शारीरिक फिटनेस, अनुशासन और राष्ट्रीय एकता के प्रति जागरूक किया जाएगा।

यूजीसी के सचिव प्रो. मनीष जोशी ने इस संबंध में राज्यों और विश्वविद्यालयों को पत्र भेजा है। इसमें स्वामी विवेकानंद की 164वीं जयंती (राष्ट्रीय युवा दिवस)

यूजीसी ने शिक्षण संस्थानों को पत्र लिख दिया निर्देश

के मौके पर सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया है।

इसके तहत 12 जनवरी पर रन फॉर स्वदेशी का आयोजन किया जाएगा। इसमें दो, तीन और पांच किलोमीटर दौड़ का आयोजन किया जाएगा। प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी मिलेगा। इसमें कॉलेज के छात्र, एनएसएस, एनसीसी, युवा क्लब, संकाय सदस्यों के अलावा आम लोग भी शामिल हो सकते हैं। सबसे पहले स्वामी विवेकानंद के संदेशों और आत्मनिर्भरता पर आधारित प्रेरक भाषण भी होगा। उच्च शिक्षण संस्थानों को कार्यक्रम से संबंधित जानकारियां यूजीसी को भेजनी अनिवार्य होगी।

स्कूलों और खेल परिसरों में लावारिस कुत्तों के प्रवेश रोकने के निर्देश जारी

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार पहली बार तीन दिवसीय भव्य सांस्कृतिक एवं साहित्यिक महोत्सव 'दिल्ली शब्दोत्सव 2026' का आयोजन 2 से 4 जनवरी को मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में करेगी। महोत्सवसुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक चलेगा। यह पूरी तरह निःशुल्क रहेगा। दिल्ली सरकार के कला, संस्कृति एवं भाषा मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि दिल्ली शब्दोत्सव भारत की ज्ञान परंपरा, साहित्यिक चेतना और सांस्कृतिक विरासत का जीवंत उत्सव है। महोत्सव में देशभर से 100 से अधिक प्रतिष्ठित वक्ता, लेखक और विचारक भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान 40 से अधिक पुस्तकों का विमोचन, 6 बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम और 2 भव्य कवि सम्मेलन आयोजित होंगे। उद्घाटन में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्यअतिथि रहेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रहेंगी। महोत्सव में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, सांसद सुधांशु त्रिवेदी, सेवानिवृत्त एयर चीफ मार्शल राकेश भदौरिया, डॉ. सच्चिदानंद जोशी, चंद्रप्रकाश द्विवेदी, मुकुल कनेटकर, माधवी लता सहित अनेक प्रतिष्ठित हस्तियां शामिल होंगी। इसके अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा की उपस्थिति भी प्रस्तावित है। संवाद

स्वदेशी डिजिटल हवाई संचार प्रणाली को विकसित करने साथ आए सेना व आइआइटी

बेंगलुरु, प्रेट्र : भारतीय वायुसेना के साफ्टवेयर विकास संस्थान (एसडीआइ) ने हवाई अनुप्रयोगों के लिए एक स्वदेशी डिजिटल संचार प्रणाली के संयुक्त डिजाइन और विकास के लिए आइआइटी मद्रास के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने, रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और भारत की रणनीतिक क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में अहम कदम है।

सोमवार को जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, समझौता ज्ञापन पर एसडीआइ कमांडेंट एयर वाइस मार्शल आर. गुरुहरि, आइआइटी मद्रास के निदेशक प्रोफेसर वी. कामकोटि और प्रवर्तक टेक्नोलाजीज फाउंडेशन के सीईओ डा एमजे शंकर रमन द्वारा हस्ताक्षर किए गए। इस साझेदारी के माध्यम से वायुसेना का लक्ष्य आइआइटी मद्रास के सहयोग से नेटवर्किंग और एन्क्रिप्शन के लिए उन्नत एल्गोरिदम विकसित करना है।

- भारतीय वायुसेना और आइआइटी मद्रास ने समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए
- आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम

ये प्रणालियां गतिशील हवाई वातावरण में सुरक्षित, विश्वसनीय और उच्च-प्रदर्शन डाटा विनिमय के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो आधुनिक सैन्य अभियानों और नेटवर्क आधारित युद्ध के लिए आवश्यक हैं। स्वदेशी रूप से इस तकनीक को विकसित करने का यह समझौता आयातित प्रणालियों पर निर्भरता को कम करने, तकनीकी संप्रभुता को बढ़ावा देने और भारत के रक्षा बलों की परिचालन दक्षता को मजबूत करने का प्रयास है।

एयर वाइस मार्शल आर. गुरुहरि ने कहा, 'आइआइटी मद्रास के साथ यह साझेदारी महत्वपूर्ण रक्षा संचार प्रौद्योगिकियों में पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में एक दूरदर्शी कदम है। अकादमिक उत्कृष्टता को परिचालन विशेषज्ञता के साथ मिलाकर हम ऐसे नवोन्मेषी, स्वदेशी समाधानों का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं जो हमारी वायुसेना की क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएंगे और एक मजबूत एवं आत्मनिर्भर भारत में योगदान देंगे।'

प्रोफेसर वी. कामकोटि ने कहा, 'भारतीय वायुसेना के लिए साफ्टवेयर विकास संबंधी यह समझौता अकादमिक और रक्षा संस्थानों के बीच तालमेल का एक बेहतरीन उदाहरण है। आइआइटी मद्रास उन्नत संचार प्रौद्योगिकियों और साइबर सुरक्षा में अपनी विशेषज्ञता का योगदान देकर मजबूत, स्वदेशी समाधान तैयार करने में गर्व महसूस करता है। यह आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगा।

संसदीय समिति की बैठक में किसी सदस्य ने वीबी-जीराम जी पर नहीं उठाया सवाल

- बैठक में सदस्यों ने मनरेगा की कमियों और वीबी-जीराम जी के प्रभावी क्रियान्वयन पर किया मंथन
- इसे सुचारू रूप से अपनाने के तरीकों और अगले छह महीनों में की जाने वाली कार्रवाई पर चर्चा की

नई दिल्ली, प्रेट्र : ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने सोमवार को संप्रग शासन के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) की कमियों और अब नरेन्द्र मोदी सरकार के विकसित भारत गारंटी फार रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) कानून वीबी-जीराम जी को सुचारू रूप से अपनाने के तरीकों पर मंथन किया। मनरेगा के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा के साथ ही इसके अनुभवों को ध्यान में रखते हुए समिति ने इस बाबत भी विमर्श किया कि नए कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अगले छह महीनों में क्या कार्रवाई की जाए। बैठक के दौरान किसी भी सदस्य ने वीबी-जीराम जी अधिनियम का विरोध नहीं किया।

हालांकि, उनमें से कई ने यह चिंता जरूर व्यक्त की कि पुराने कानून के तहत कई राज्यों में नामांकन केवल लगभग 50 प्रतिशत ही था। सदस्यों ने यह भी कहा कि वीबी-जीराम जी कानून को लागू करने में कम से कम छह

महीने लगेंगे क्योंकि नियमों के तैयार होने के बाद ही इसे लागू किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि समिति के अधिकांश सदस्य इस बात को लेकर चिंतित थे कि अगले छह महीनों में सरकार द्वारा मनरेगा से वीबी-जीराम जी में कार्य नीतियों को स्थानांतरित करने के दौरान यह परिवर्तन कैसे होगा, इस अवधि के दौरान लाभार्थियों को भुगतान कैसे किया जाएगा और अतिरिक्त बजटीय सहायता की व्यवस्था कैसे की जाएगी।

गौरतलब है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार ने 2005 में पारित किया था। वीबी-जीराम जी विधेयक को हाल ही में समाप्त हुए शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष के जोरदार विरोध के बीच संसद में पारित किया गया। नए अधिनियम में ग्रामीण श्रमिकों के लिए 125 दिनों के कार्य दिवस का प्रविधान है। सोमवार को हुई संसदीय समिति की बैठक में नई प्रणाली और ढांचे पर भी चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार, कुछ विपक्षी सदस्यों ने स्वीकार किया कि मनरेगा में कुछ कमियां हैं, जिनके लिए समिति ने पहले कुछ सिफारिशें की थीं। कुछ विपक्षी सदस्यों ने कहा कि उन्होंने पहले कार्य दिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 करने का सुझाव दिया था।

'जीराम जी' से राज्यों की वित्तीय सेहत पर असर नहीं

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को 'विकसित भारत - ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका मिशन गारंटी' (वीबी-जीराम जी) में बदलने से राज्यों की वित्तीय स्थिति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्टेट बैंक आफ इंडिया (एसबीआइ) की तरफ से सोमवार को जारी रिपोर्ट में इस बदलाव की आलोचना को निराधार बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस योजना से राज्य कुल मिलाकर 'नेट गेनर' यानी फायदे में रहेंगे। यह आकलन भी इसमें किया गया है कि केंद्र सरकार जिस तरह से राज्यों से अपने राजस्व को साझा कर रही है उसे देखते हुए राज्यों को 17 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन प्राप्त होगा।

17 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन राज्यों को प्राप्त होगा

श्रमिकों को मिलेंगे रोजगार के बेहतर अवसर। प्रतीकात्मक

रिपोर्ट के मुताबिक, नई व्यवस्था में फंडिंग पैटर्न को 60:40 यानी केंद्र का हिस्सा 60 और राज्य का हिस्सा 40 प्रतिशत करने से राज्यों पर उधार या वित्तीय बोझ नहीं बढ़ने जा रहा, बल्कि राज्य वित्त व्यवस्था बेहतर करने को प्रोत्साहित होंगे। मनरेगा में यह अनुपात 90:10 का था।

खराब वित्तीय स्थिति वाले राज्यों पर ज्यादा बोझ पड़ने की बात भ्रामक पेज>>3

एसबीआइ की रिपोर्ट में दावा

- मनरेगा की कई खामियों को दूर करेगा वीबी-जीराम जी कानून
- 60:40 अनुपात से राज्यों को फायदा, मनरेगा में था 90:10
- 5.78 करोड़ से ज्यादा रोजगार सृजित होंगे नई योजना में
- उप्र, महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़ और गुजरात को होगा सर्वाधिक फायदा

ज्यादा धन वालों को निशाना बना रहे डिजिटल ठग

आरबीआइ के मुताबिक, अप्रैल-सितंबर 2025 में 21,367 करोड़ की धोखाधड़ी, पिछले वर्ष यह संख्या 16,659 करोड़ थी

- चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में फ्राड के मामलों की संख्या घटकर 5,092 रही
- अप्रैल-सितंबर 2024 के दौरान धोखाधड़ी के 18,386 मामले सामने आए थे

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : डिजिटल या साइबर ठग अब अमीरों को अपना निशाना बना रहे हैं। इसका संकेत के ताजा आंकड़े दे रहे हैं। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही के दौरान बैंकिंग धोखाधड़ी के मामले तो घटे हैं, लेकिन इनसे जुड़ी राशि में वृद्धि हुई है। सोमवार को आरबीआइ की तरफ से जारी 'ट्रेंड एंड प्रोग्रेस आफ बैंकिंग इन इंडिया 2024-25' रिपोर्ट में कहा गया है कि अप्रैल-सितंबर, 2025 के दौरान फ्राड से जुड़ी राशि पिछले साल की समान अवधि के 16,659 करोड़ रुपये के मुकाबले बढ़कर 21,367 करोड़ रुपये हो गई। जबकि इस दौरान फ्राड की संख्या 18,386 से घटकर 5,092 रह गई है।

रिपोर्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग की तारीख के आधार पर वित्त वर्ष 2024-25 में फ्राड के कुल मामलों की संख्या 23,879 रही, जिनमें शामिल राशि 36,771 करोड़ रुपये थी। आरबीआइ का तर्क है कि यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट के 27 मार्च, 2023 के फैसले के अनुपालन में पुराने मामलों की दोबारा रिपोर्टिंग से हुई है। अगर हम 2024-25 की तुलना इसके पिछले वित्त वर्ष से करें तो फ्राड राशि में तीन गुना से अधिक वृद्धि दिखती है।

खास बात यह है कि कर्ज से जुड़े फ्राड की राशि 31,911 करोड़ रुपये तक पहुंच गई, जो कुल राशि का बड़ा हिस्सा है। रिपोर्ट के अनुसार, 'फ्राड बैंकिंग संस्थानों की प्रतिष्ठा, परिचालन और व्यवसायिक जोखिमों के साथ-साथ ग्राहक विश्वास को कमजोर करते हैं।' बैंकिंग धोखाधड़ी की घटनाओं की तारीख के आधार पर कार्ड/इंटरनेट के जरिये होने वाले फ्राड की हिस्सेदारी संख्या के लिहाज से 56.8 प्रतिशत रही जबकि राशि के लिहाज से एडवांस (ऋण) से जुड़े फ्राड की हिस्सेदारी 35.1 प्रतिशत बताई गई है। धोखाधड़ी से जुड़े कुल मामलों में निजी बैंकों की हिस्सेदारी 59.3 प्रतिशत रही जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की राशि में हिस्सेदारी 70.7 प्रतिशत रही। कार्ड/इंटरनेट से जुड़े ज्यादातर फ्राड निजी बैंकों से जुड़े थे जबकि सरकारी बैंकों में कर्ज से जुड़े फ्राड ज्यादा हैं।

म्यूल खातों पर रोक के लिए हो रहा एआइ का प्रयोग

आरबीआइ की तरफ से इस रिपोर्ट में एक और विशेष जानकारी दी गई है जो बताता है कि धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई की जा रही है। खास तौर पर म्यूल अकाउंट (किसी दूसरे ग्राहकों के पुराने या बंद पड़े खातों का इस्तेमाल करना) पर रोक लगाने के लिए आरबीआइ ने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआइ) आधारित विशेष प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया है। इसे म्यूल हंटर डाट एआइ का नाम दिया गया है, जिसे आरबीआइ की सब्सिडियरी रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने बनाया है। यह म्यूल अकाउंट्स को तेजी से पहचानता है। इसे 17 दिसंबर 2025 को ही एक साथ 23 बैंकों में लागू किया गया है। ये कदम फ्राड को पहले से रोकने में मदद करेंगे।

कई दशकों के सबसे निचले स्तर 2.2 प्रतिशत पर आया बैंकों का सकल एनपीए

रिपोर्ट के अनुसार, बैंकों की वित्तीय स्थिति लगातार मजबूत हो रही है। मार्च, 2025 के अंत तक बैंकिंग सेक्टर का सकल एनपीए (सकल एनपीए) का अनुपात पिछले कई दशकों के सबसे न्यूनतम स्तर 2.2 प्रतिशत पर पहुंच गया। जबकि शुद्ध एनपीए का स्तर 0.5 प्रतिशत पर आ गया है। एक तरह से भारतीय बैंकों का मुनाफा बढ़ा है, इनकी जोखिमों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है और इनकी तरफ से वितरित कर्ज की लगातार लगातार तेज रफ्तार से बढ़ोतरी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार, 'मजबूत बैंकिंग सेक्टर इकोनमी के अवसरों और जोखिमों के खिलाफ एक सुरक्षा प्रदान करता है।' वैसे वाणिज्यिक बैंकों का शुद्ध मुनाफा वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़ा है लेकिन इसकी रफ्तार कुछ धीमी रही है। सभी वाणिज्यिक बैंकों का संयुक्त नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 14.8 प्रतिशत बढ़कर 4.01 लाख करोड़ रुपये का हो गया है।

वित्तीय उत्पादों की गलत बिक्री रोकने के लिए उठेंगे कदम

मुंबई, पीटीआइ : आरबीआइ ग्राहकों को वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की गलत बिक्री रोकने के लिए कड़े कदम उठाने जा रहा है। इस संबंध में वह जल्द ही विज्ञापन, विपणन और बिक्री से जुड़े नियामकीय संस्थाओं के नए नियम जारी करेगा। केंद्रीय बैंक ने सोमवार को जारी अपनी रिपोर्ट 'ट्रेंड एंड प्रोग्रेस आफ बैंकिंग इन इंडिया 2024-25' में कहा कि नियामकीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की गलत बिक्री से ग्राहकों और वित्तीय क्षेत्र दोनों पर गंभीर असर पड़ता है। रिपोर्ट में कहा गया कि रिकवरी एजेंट को कम पर रखने और लोन की रिकवरी से जुड़े व्यवहार मामलों पर मौजूदा निर्देशों की समीक्षा करने और एक सख्त नए एआइ निर्देश जारी करेगा।

डिजिटल लेनदेन बढ़ने के कारण एटीएम की संख्या घटी

मुंबई, पीटीआइ : आरबीआइ द्वारा सोमवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि डिजिटल लेनदेन बढ़ने के साथ वित्त वर्ष 2024-25 में एटीएम की संख्या में थोड़ी कमी आई है। सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा बैंकों का नेटवर्क बढ़ाने से बैंक शाखाओं की संख्या में भी प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि हुई है। 31 मार्च, 2025 तक एटीएम की कुल संख्या घटकर 2,51,057 हो गई, जो एक साल पहले इसी समय में 2,53,417 थी। निजी क्षेत्र के बैंकों का एटीएम नेटवर्क पिछले साल के 79,584 से घटकर 77,117 हो गया, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एटीएम नेटवर्क भी एक साल पहले इसी समय के 1,34,594 से घटकर 1,33,544 हो गया। 31 मार्च तक, देश में 1.64 लाख ग्राम थी।

जाति निर्धारण पर नई दृष्टि

डा. ऋतु सारस्वत

अंतरजातीय विवाह के मामलों में जाति निर्धारण आसपास के तथ्यों को नजरअंदाज नहीं कर सकता

हाल में शीर्ष अदालत के एक निर्णय ने खूब सुर्खियां बटोरीं और इसे एक ऐतिहासिक निर्णय के रूप में उल्लेखित किया गया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जायमाल्य बागची की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने पुडुचेरी की एक नाबालिग लड़की को उसकी मां की जाति के आधार पर अनुसूचित जाति (एससी) प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अनुमति दी, भले ही उसके पिता गैर-अनुसूचित जाति समुदाय से थे। पीठ ने टिप्पणी दी कि "मां की जाति उतनी ही महत्वपूर्ण पहचान है, जितनी पिता की।" इस संदर्भ में 5 मार्च, 1964 और 17 फरवरी, 2002 की राष्ट्रपति अधिसूचनाओं को केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के साथ पढ़ने पर यह पता चलता है कि जाति प्रमाण पत्र के लिए पात्रता मुख्य रूप से पिता की जाति और किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर व्यक्ति की आवासीय स्थिति द्वारा निर्धारित की जाती है। उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता ने यह दावा किया कि था कि उसका पति विवाह के बाद से ही उसके साथ उसके माता-पिता के घर रह रहा है। इस तर्क से इस तथ्य को सुस्पष्ट करना था कि उसके बच्चों ने कभी भी उच्च जाति के कथित सामाजिक लाभों का उपभोग नहीं किया।

इससे पूर्व देश की विभिन्न अदालतों ने मां की जाति के इस्तेमाल के संबंध में जब भी निर्णय दिए तो उसका मूलभूत आधार यह रहा कि क्या बच्चे उच्च जाति के सामाजिक एवं सांस्कृतिक लाभों से वंचित रहे। उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय पर तमाम तर्क-वितर्क के साथ अनेक आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। पहली आशंका तो यह है कि इससे आरक्षण व्यवस्था के लाभ के लिए एक नई परंपरा स्थापित हो जाएगी, जिसके दूरगामी नकारात्मक परिणाम सामने आ सकते हैं। इन आशंकाओं को एक सिरे से नकारा नहीं जा सकता, परंतु जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा, "हम कानून के प्रश्न को खुला रख रहे हैं। बदलते समय के साथ माता की जाति के आधार पर जाति प्रमाण पत्र क्यों जारी नहीं किया जाना चाहिए?" इस प्रश्न भरे वक्तव्य के गहरे निहितार्थ हैं, परंतु त्वरित रूप से निर्णय पर पहुंचने से पूर्व इस विषय पर एक गहन विमर्श की आवश्यकता है। यह महत्वपूर्ण है कि यह निर्णय इस बात को सामान्य सिद्धांत घोषित नहीं करता कि जाति हमेशा मां के माध्यम से ही विरासत में मिल सकती है। न ही यह निर्णय यह सिद्ध करता है कि मात्र जाति के आधार पर भविष्य में सभी अनुसूचित जाति अथवा जनजाति प्रमाण पत्र दावों को बाध्यकारी रूप से स्वीकार किया जाता रहेगा।

कोर्ट के फैसले के बाद जाति निर्धारण पर छिड़ी बहस। फाइल

इस मामले को अगर समझना है तो हमें उस निर्णय का भी विश्लेषण करना होगा, जो 20 जून, 2025 को बांबे उच्च न्यायालय के 'सुजल मंगला बिरवाडकर बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य मामले' में न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और डा. नीला गोखले की खंडपीठ ने दिया था। चंभर (अनुसूचित जाति) श्रेणी के तहत जाति वैधता प्रमाण पत्र की मांग करने वाली एक छात्रा की याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा था, 'यद्यपि तलाक के बाद सुजल का पालन-पोषण उसकी माता ने किया, किंतु केवल अनुसूचित जाति के माता का होना जाति-आधारित लाभों का दावा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।' कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता का पालन-पोषण विशेषाधिकार प्राप्त वातावरण में हुआ था। उसने केंद्रीय विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की और उसे सामाजिक रूप से किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा था। उसकी माता की आर्थिक स्थिति और परिवार की व्यावसायिक पृष्ठभूमि ने उसके दावे को और भी कमजोर कर दिया।

गौरतलब है कि छात्रा ने अपने पिता के गैर-अनुसूचित जाति 'हिंदू कृषि' समुदाय से होने के बावजूद अपनी माता की 'चंभर' जाति के आधार पर अनुसूचित जाति का दर्जा मांगा था। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि जाति-आधारित आरक्षण के लिए केवल जन्म-आधारित संबंध ही नहीं, बल्कि वास्तविक भेदभाव का प्रमाण आवश्यक है। ठीक यही विचार दृष्टि फरवरी 2025 को बांबे उच्च न्यायालय के ही 'स्वानुभूति जीवराज जैन बनाम महाराष्ट्र राज्य' मामले में सामने आई। इस मामले में न्यायालय ने अपने फैसले को स्पष्ट करते हुए यह कहा था कि जातिगत वैधता विवादों से संबंधित कानून को स्पष्ट करते हुए विभिन्न जातियों के माता-पिता से जन्मे बच्चे, जिनमें से माता या पिता में से कोई एक अनुसूचित जाति से संबंधित हों, बिना यह साबित किए कि उन्हें उस जाति से संबंधित वास्तविक सामाजिक भेदभाव, नुकसान या अभाव का सामना करना पड़ा है, स्वतः ही अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त करने का दावा नहीं कर सकते।

रमेशभाई दभाई नाइका बनाम गुजरात राज्य (2012) के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया कि अंतरजातीय विवाह के मामलों में जाति निर्धारण आसपास के तथ्यों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। वास्तव में यह एक तथ्य है कि कई बार परिवेश बहुत असर डालने वाला साबित होता है। जातिगत आरक्षण पर होने वाली बहस के बीच सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय अनेक आशंकाओं को जन्म दे रहा है। चूंकि इस सत्य से इन्कार नहीं कि भारत के सुदूर हिस्सों में आज भी सामाजिक ढांचा जातिगत भेदभाव के बीच गुंथा हुआ है और अनेक बार जातिगत भेदभाव की अनचाही पीड़ाएं गहरे घाव कर जाती हैं, इसलिए ऐसे गंभीर मुद्दों पर गहन विमर्श के पश्चात ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए।

(लेखिका समाजशास्त्री हैं)
response@jagran.com

पूरे देश से घुसपैठियों को भगाएंगे : शाह

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, असम में घुसपैठियों को खदेड़ने वाली सरकार चुनें

- कांग्रेस पर घुसपैठियों को अपना वोट बैंक समझने का लगाया आरोप
- कहा, असम के पहले सीएम ने राज्य को भारत में रखने को नेहरू को किया था मजबूर

गुवाहाटी, प्रेट्र: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को असम के लोगों से अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में घुसपैठियों को खदेड़ने वाली और राज्य के विकास के पक्ष में काम करने वाली सरकार चुनने की अपील की। उन्होंने कहा कि भाजपा असम ही नहीं पूरे देश से घुसपैठियों को भगाने के लिए प्रतिबद्ध है। शाह ने कांग्रेस को घेरा और उस पर आरोप लगाया कि वह घुसपैठियों को अपना वोट बैंक समझती है। इन घुसपैठियों के कारण असमिया लोगों की पहचान को खतरा पैदा हो गया है।

अमित शाह ने यहां पांच हजार सीटों की क्षमता वाले सभागार के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा, 'दस वर्ष पहले असम के लिए यह एक लंबे बुरे सपने जैसा था। बंद, नाकाबंदी, गोलीबारी और बम विस्फोट आम बात थी। कई विद्रोही समूह सक्रिय थे। आंदोलन हो रहे थे।' गृह मंत्री ने कहा कि भाजपा के दस वर्ष के शासन और केंद्र में नरेन्द्र मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल में असम ने प्रगति की है। उन्होंने कहा, 'पिछले दस वर्षों में भाजपा सरकार के नेतृत्व में असम में काफी प्रगति हुई है। भाजपा को अगले पांच वर्षों का आशीर्वाद दें और हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे वापस भेज दिया जाएगा। इससे असम की पहचान, भाषा, संस्कृति और भोजन की रक्षा होगी। अगले वर्ष मार्च-अप्रैल में होने वाले चुनाव में ऐसी सरकार चुनें, जो घुसपैठ को रोके और असम के विकास के लिए काम करे।'

गुवाहाटी में सोमवार को ज्योति विष्णु आडिटोरियम के उद्घाटन अवसर पर संबोधित करते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। प्रेट्र

शाह ने कांग्रेस को अमस में घुसपैठ की समस्या के लिए जिम्मेदार ठहराया और कहा, 'वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने घुसपैठ को बढ़ावा दिया, जिससे आज असम की पहचान को खतरा है।' उन्होंने अवैध प्रवासी (न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारण) (आइएमडीटी) अधिनियम का जिक्र करते हुए कहा, 'असम की संस्कृति और पहचान की बात करने वाले लोग खुद 1983 में एक एक कानून लाए थे।' सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में इस कानून को निरस्त कर दिया था, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का मानना था कि यह कानून अवैध प्रवासियों की पहचान और निर्वासन में सबसे बड़ी बाधा है। अमित शाह ने असम के पहले मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरदोलोई के योगदान को याद किया, जिन्होंने यह सुनिश्चित किया था कि राज्य भारत का हिस्सा बना रहे। उन्होंने कहा, 'गोपीनाथ बोरदोलोई ने ही जवाहरलाल नेहरू को असम को देश का हिस्सा बनाए रखने के लिए मजबूर किया था।'।

बलिदानियों को दी श्रद्धांजलि

अमित शाह ने गुवाहाटी में पुलिस आयुक्त कार्यालय के 111 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित नए भवन और शहर के लिए दो हजार सीसीटीवी कैमरों वाली निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया। उन्होंने नवनिर्मित पुलिस आयुक्त कार्यालय में सीआइडी द्वारा आपराधिक कानूनों पर लगाई गई एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। इससे पहले उन्होंने असम में अवैध प्रवासियों के खिलाफ चलाए गए आंदोलन (असम आंदोलन) के बलिदानियों को 'शहीद स्मारक क्षेत्र' में श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने राज्य के पहले मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरदोलोई, संगीत सम्राट भूपेन हजारिका, गायक जुबिन गर्ग और प्रसिद्ध अहोम जनरल लाचित बोरफुकन को श्रद्धांजलि दी।

सरकार ने केजी-डी6 विवाद में रिलायंस-बीपी से 30 अरब डालर का मुआवजा मांगा

- सरकार ने तीन-सदस्यीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण के समक्ष पेश किया दावा
- करीब 14 साल पुराने इस मामले पर सुनवाई सात नवंबर को हो चुकी है पूरी

नई दिल्ली, प्रेट्र: केंद्र सरकार ने कृष्णा-गोदावरी बेसिन के केजी-डी6 गैस क्षेत्र से प्राकृतिक गैस उत्पादन का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाने पर रिलायंस इंडस्ट्रीज और उसकी साझेदार बीपी से 30 अरब डालर से अधिक का मुआवजा मांगा है। घटनाक्रम से परिचित सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने यह दावा तीन-सदस्यीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण के समक्ष पेश किया है। करीब 14 साल पुराने इस मामले पर सुनवाई सात नवंबर को पूरी हो चुकी है।

माना जा रहा है कि न्यायाधिकरण अगले वर्ष किसी समय इस मामले में अपना फैसला सुना सकता है। फैसले से असंतुष्ट पक्ष के पास सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का विकल्प होगा। सरकार का आरोप है कि दोनों साझेदारों ने केजी-डी6 ब्लाक में जरूरत से ज्यादा बड़ी सुविधाएं विकसित कीं, लेकिन वे प्राकृतिक गैस उत्पादन के निर्धारित लक्ष्यों को हासिल कर पाने में नाकाम रहे। मध्यस्थता प्रक्रिया के दौरान सरकार ने उत्पादित नहीं की जा सकी गैस का मौद्रिक मूल्य मांगने के साथ ही प्रतिष्ठानों पर अतिरिक्त खर्च, ईंधन विपणन और ब्याज पर भी मुआवजा मांगा है।

हमें देश की न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा: रिलायंस

रिलायंस ने कहा कि उसके और बीपी के खिलाफ 30 अरब डालर का कोई दावा नहीं है और यह कहना तथ्यात्मक रूप से गलत है कि सरकार ने केजी-डी6 गैस फील्ड से कम उत्पादन के लिए उससे और उसके पार्टनर से 30 अरब डालर मांगे हैं। मामला पूरी तरह से विचाराधीन है। जो भी विवाद है, उसका निपटारा देश के कानून द्वारा तय किया जाएगा और देश की न्यायिक प्रक्रिया पर रिलायंस को पूरा भरोसा है। रिलायंस ने रिपोर्ट में तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने पर कड़ी आपत्ति जताई है।

विदेशी फंडों की निकासी से चौथे दिन भी लुढ़का सेंसेक्स

मुंबई, प्रेट्र: विदेशी फंडों की निकासी और आइटी व प्रमुख तेल-गैस शेयरों में बिकवाली के कारण बीएसई का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स सोमवार को लगातार चौथे दिन 345.91 अंक गिरकर 84,695.54 के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह, एनएसई का निफ्टी लगातार तीसरे दिन 100.20 अंक गिरकर 26 हजार के स्तर से नीचे आते हुए 25,942.10 पर बंद हुआ।

सेंसेक्स में अदाणी पोर्ट्स के शेयरों में सबसे ज्यादा 2.22 प्रतिशत की गिरावट रही। इसके अलावा, एचसीएल टेक, पावर ग्रिड, ट्रेंट, भारत इलेक्ट्रानिक्स, भारती एयरटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में गिरावट रही। जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के शोध प्रमुख विनोद नायर का कहना है कि बाजार में आगे बढ़ने के लिए कारकों की कमी प्रतीत होती है।

एपल ने 11 महीनों में 65 लाख से अधिक आइफोन-16 बेचे

- काउंटरपाइंट रिसर्च के मुताबिक, यह देश का सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन बना
- आइफोन-15 सबसे ज्यादा बिकने वाले स्मार्टफोन की सूची में पहले पांच में शामिल

मुंबई, आइएएनएस: एपल ने कैलेंडर वर्ष 2025 के पहले 11 महीनों के दौरान 65 लाख से अधिक आइफोन 16 बेचे। इस तरह यह देश का सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन बन गया। काउंटरपाइंट रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक, एपल ने इसी दौरान एंड्राइड स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों को पीछे छोड़ दिया। आंकड़ों पर नजर डालें तो आइफोन-15 सबसे ज्यादा बिकने वाले स्मार्टफोन की सूची में पहले पांच में शामिल है।

रिसर्च फर्म ने कहा कि एपल का प्रदर्शन एक ऐसे बाजार में खरीदारों के बदलते व्यवहार को दिखाता है, जहां पहले एंट्री लेव और मिड रेंज डिवाइस का दबदबा था। इसके अलावा, यह बदलाव एपल द्वारा लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने और चीन पर निर्भरता कम करने के लिए एक रणनीतिक कोशिश का भी नतीजा है। एपल ने हाल ही में बेंगलुरु, पुणे और नोएडा में तीन नए एपल स्टोर खोले हैं, इस तरह देश में इसके कुल पांच स्टोर हो गए हैं। नो कास्ट ईएमआइ, कैशबैक और बैंक स्कीम जैसे वित्तीय विकल्पों ने ग्राहकों के लिए हाई-एंड-फोन तक पहुंच को ज्यादा आसान बना दिया है। एपल ने नवंबर में दो अरब डालर के स्मार्टफोन निर्यात किए। एपल की ग्लोबल प्रोडक्शन वैल्यू में भारत में होने वाली मैन्यूफैक्चरिंग की हिस्सेदारी 12 प्रतिशत है।

चार कंपनियों को मिली आइपीओ की मंजूरी

नई दिल्ली, प्रेट्र: कैपिटल मार्केट रेग्युलेटर सेबी ने चार कंपनियों को आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आइपीओ) लाने की मंजूरी दी है। इन कंपनियों में नैक पैकेजिंग, शिवालय कंस्ट्रक्शन, टाइल्स व बाथवेयर बनाने वाली कंपनी वरमोरा ग्रेनिटो और बिहारी लाल इंजीनियरिंग शामिल हैं।

सेबी के डाटा के अनुसार, यह चारों कंपनियां आइपीओ के जरिये संयुक्त रूप से 1,400 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि जुटाएंगी। दूसरी ओर, इन्फ्रीक्रेश ने आइपीओ दस्तावेज वापस ले लिए हैं। वहीं, जल व अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र से जुड़े समाधान प्रदान करने वाली कंपनी बाग टेक्नोलाजीज ने आइपीओ के लिए सेबी के पास प्रारंभिक दस्तावेज जमा किए हैं। उधर, होरिजन इंडस्ट्रियल पार्क्स ने 2,600 करोड़ के आइपीओ के लिए सोमवार को सेबी के पास प्रारंभिक दस्तावेज जमा किए।

नवंबर में औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दो साल के उच्च स्तर 6.7 प्रतिशत पर

- जीएसटी दरों में कमी का लाभ उठाने के लिए मैन्यूफैक्चरिंग में दिखी तेजी, खनन में हुआ सुधार
- इससे पहले औद्योगिक उत्पादन का उच्च स्तर नवंबर, 2023 में 11.9 प्रतिशत दर्ज किया गया था

> अमेरिकी शुल्क और जुर्माने का असर कुछ मैन्यूफैक्चरिंग खंडों में दिखाई दे सकता है, जिससे जीएसटी दरों में बदलाव के सकारात्मक प्रभाव का असर कम हो सकता है। -**अदिति नायर**, मुख्य अर्थशास्त्री, इक्रा

नई दिल्ली, प्रेट्र: खनन और मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्रों के मजबूत प्रदर्शन से नवंबर महीने में देश के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर दो साल के उच्च स्तर 6.7 प्रतिशत पर पहुंच गई। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के मुताबिक, औद्योगिक उत्पादन को मापने वाला औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आइआइपी) नवंबर, 2024 में पांच प्रतिशत बढ़ा था। इससे पहले औद्योगिक उत्पादन का उच्च स्तर नवंबर, 2023 में 11.9 प्रतिशत दर्ज किया गया था।

त्योहारों से पहले देश में मांग और खपत को बढ़ावा देने के लिए कई उपभोक्ता वस्तुओं पर जीएसटी दरों में 22 सितंबर, 2025 से कटौती की गई थी। इससे जीएसटी दरों में कमी का लाभ उठाने के लिए मैन्यूफैक्चरिंग आर्डरों में तेजी आई। इसके साथ एनएसओ ने अक्टूबर 2025 के लिए औद्योगिक उत्पादन वृद्धि के आंकड़े को भी संशोधित किया है। अक्टूबर के लिए आइआइपी वृद्धि को बढ़ाकर 0.5 प्रतिशत कर दिया गया है जबकि पिछले महीने जारी अस्थायी अनुमान 0.4 प्रतिशत का था। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, नवंबर 2025 में मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र का उत्पादन आठ प्रतिशत बढ़ा, जो एक साल पहले इसी महीने में 5.5 प्रतिशत था। खनन क्षेत्र क उत्पादन भी नवंबर में 5.4 प्रतिशत बढ़ा। हालांकि, बिजली उत्पाद का प्रदर्शन कमजोर रहा। बिजल उत्पादन में पिछले महीने 1.. प्रतिशत की गिरावट रही। नवंब 2024 में यह 4.4 प्रतिशत बढ़ा था

बिजनेस से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

स्तन कैंसर जांच में जोखिम आधारित स्क्रीनिंग अधिक प्रभावी

अनुसंधान

एक नए शोध में दावा किया गया है कि स्तन कैंसर की जांच के लिए वार्षिक मैमोग्राम के बजाय रोगियों के जोखिम का आकलन करने वाला व्यक्तिगत दृष्टिकोण अधिक प्रभावी है। यह कैंसर को एडवांस स्टेज में जाने से पहले पकड़ने में मददगार साबित हो सकता है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय की ओर से 46,000 महिलाओं पर यह अध्ययन किया गया। यह जांच दृष्टिकोण को सिर्फ उम्र आधारित दृष्टिकोण से बदलकर एक व्यापक जोखिम आकलन से शुरू करने की सिफारिश करता है, ताकि प्रत्येक महिला को बेहतर इलाज मिल सके। यूसीएसएफ ब्रेस्ट केयर सेंटर की निदेशक लारा जे. एस्सरमैन ने कहा, "इन निष्कर्षों से स्तन कैंसर की जांच के लिए स्क्रीनिंग के दिशा-निर्देशों में महत्वपूर्ण बदलाव आना चाहिए और इस अभ्यास में भी परिवर्तन आना चाहिए।" एस्सरमैन ने आगे कहा, "व्यक्तिगत दृष्टिकोण जोखिम मूल्यांकन से शुरू होता है, जिसमें आनुवंशिक, जैविक और जीवनशैली कारकों को शामिल किया जाता है।" स्तन कैंसर महिलाओं में सबसे आम कैंसर है, जिसके वैश्विक स्तर पर अनुमानित 23 लाख मामले और 670,000 मौतें होती हैं। दशकों से, स्क्रीनिंग में यह मान लिया गया था कि सभी महिलाओं में जोखिम समान है और दिशानिर्देश मुख्य रूप से उम्र पर आधारित थे, जबकि इस बात के पुख्ता सुबूत हैं कि व्यक्तिगत जोखिम व्यापक रूप से भिन्न होता है। (आइएएनएस)

क्लीन स्वीप करने उतरेंगी बेटियां

भारत और श्रीलंका के बीच आज खेला जाएगा पांचवां और अंतिम टी-20 मैच

« हरमन के बीच भारत की उपकप्तान स्मृति मंधाना • पी

आज का मैच

भारत vs श्रीलंका

रात 7.00 बजे | स्थल: दिग्गजों का मैदान

प्रसारण: स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क, डिस्नी हॉटस्टार

भारत: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स, स्नेह राणा, दीप्ति शर्मा, तेजस्वी वर्मा, हरलीन देओल, अमनजोत कौर, अरुंधती रेड्डी, क्रांति गौड़, रेणुका सिंह, सिमरन शेख, यस्तिका भाटिया, श्रेयांका पाटिल, प्रतिका रावल।

श्रीलंका: चमरी अटापट्टू (कप्तान), हसिनी पेरेरा, नीलाक्षी डिसिल्वा, विश्मी गुणरत्ने, उदेशिका प्रबोधनी, कविशा दिलहारी, इनोका रणवीरा, मल्लिका सेवंदी, अचिनी कुलसूरिया, सुगंधिका कुमारी, प्रबोधनी मदुशिका, अमा कांचना, सोफिया डंकले, रश्मिका सेवंदी, गुलनी कवया।

4-0 से आगे है भारतीय महिला टीम पांच मैचों की इस सीरीज में

मैच में भी उसने दो बैल फेंके और सीरीज का एक मैच गंवाया। भारतीय टीम के लिए इस बुंदेलखंड में कई सकारात्मक पहलू भी रहे। तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर ने एक साल के अंतराल के बाद इस प्रारूप में वापसी करते हुए कई उपयोगी प्रदर्शन किए। उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की और बल्लेबाजी में भी उपयोगी योगदान दिया। उन्होंने अब तक पांच मैचों में तीन अर्धशतक बनाए हैं और उनका औसत 135.52 का है। भारतीय टीम के लिए इस और बड़ी बात थी अपने लड़ी गेंदबाज का कमर में कसावट की। बल्लेबाज की इस बल्लेबाजी ने पहले टी20 मैच में 48 गेंद पर 80 रन बनाए और वह उसने इस रन की बल्लेबाज शक्ति को कविता दिखाई। लेकिन चौथे मैच में खुद रन की बाद भरता और श्रीलंका टीमों ने एक अवसर में अपना सर्वाधिक स्कोर बनाया।

162 रन की चुनौतीपूर्ण को भी वह नहीं पा पाई। टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत की तरफ से पहले विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी है।

भारत ने पिछले मैच में दिग्गज के खिलाड़ी स्मृति मंधाना और जेमिमा रोड्रिग्स ने 15 गेंदों में नवाचार 42 रन बनाकर इस लेकिन को बड़ी मजबूत किया। पहले बीच मैच बना स्कोर बाकी है, लेकिन चौथे मैच में खुद रन की बाद भरता और श्रीलंका टीमों ने एक अवसर में अपना सर्वाधिक स्कोर बनाया।

बड़ौदा को 54 रन से हराया, ध्रुव ने जड़ा अविजित शतक, कप्तान रिंकू का भी अर्धशतक

उप्र ने लगातार तीसरे मैच मे बनाए 300+ रन

ध्रुव जुरेल • प्रेस

लखनऊ, हि.: उत्तर प्रदेश ने सोमवार को विजय हजारे ट्रॉफी के ग्रुप-डी मुकाबले में बड़ौदा को 54 रन से हराकर टूर्नामेंट में शानदार लगातार तीसरी जीत दर्ज की। इस जीत के नायक रहे युवा विकेटकीपर-बल्लेबाज ध्रुव जुरेल, जिन्होंने 101 गेंदों में 160 रनों की अविजित पारी खेली। उनकी इस अविजित पारी के दम पर उत्तर प्रदेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सात विकेट पर 360 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। जुरेल के अलावा कप्तान रिंकू सिंह (52) ने अर्धशतकीय पारी खेली। इसके जवाब में बड़ौदा की टीम 306 रन ही बना सकी। लगातार तीसरे मैच में 350 से ऊपर के स्कोर बनाकर उत्तर प्रदेश ने पहले मैच में हैदराबाद के खिलाड़ी 324 और दूसरे मैच में चंडीगढ़ के खिलाड़ी 350 रन बनाए थे।

पिछले मैच में शतक जड़ने वाले अर्जुन तेंदुलकर (26) के जल्द आउट होने के बाद ध्रुव जुरेल ने अपनी पारी में 15 चौके और आठ छक्के जड़े। इनके साथ ही रिंकू के साथ चौथे विकेट के लिए 131 रन की अहम साझेदारी की। इसके अलावा जुरेल ने अधिकतम बिना नौसिखिए खिलाड़ी बनने अनिकेत चितकोटी के साथ आठवें विकेट (36) के साथ छठे विकेट के लिए 122 रनों की साझेदारी की। कप्तान की ओर से बल्ले चलाने में नाबाद रहे रिंकू, लेकिन इस बार वह ओवर फेंकने में नहीं लौट पाए। इस जीत के साथ उत्तर प्रदेश की टीम के 12 अंक हो गए हैं।

नहीं चला अभिषेक का जादू, बंगाल की हार: लखनऊ के अकोना स्टेडियम में पंजाब के कप्तान अभिषेक शर्मा का शानदार शतक भी बंगाल को उत्तराखंड के खिलाड़ी कुल की जीत से नहीं बचा पाया। उत्तराखंड ने बंगाल के 300 रन के लक्ष्य को 49.4 ओवर में पार कर लिया। उत्तराखंड की ओर से कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन (103) और सुमित घर (151) ने अर्धशतकीय पारियां खेलीं। उत्तराखंड ने कप्तान मुकुल चौहान (116) के शानदार शतक की मदद से 49.4 ओवर में चार विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।

शार्दुल की शानदार गेंदबाजी ने मुंबई को दिलाई तीसरी जीत

लखनऊ: प्रकाश के कुंज में 5 मार्च को विजय हजारे ट्रॉफी के ग्रुप-डी मैच में मुंबई ने मैच में बड़ौदा को 8 विकेट से हराकर लगातार तीसरी जीत की हैट्रिक पूरी की। इस लोकप्रिय टूर्नामेंट का विजेता बनने के बाद शार्दुल ठाकुर ने गेंदबाजी की शानदार प्रतिस्पर्धा का फल दिखाया। उन्होंने 10 ओवरों में 41 रन देकर चार विकेट लिए। उनकी कप्तानी में टीम ने बड़ौदा के खिलाड़ी को पकड़ने में सफलता पाई। मुंबई ने 31 रन पर पहला विकेट गिरने के बाद बड़ौदा ने आखिरी छह विकेट 23 रन के अंदर गंवा दिए। उनकी ओर से अनुज गुप्ता (68*) और अनुज रावत (40) ने दूसरे विकेट के लिए 90 रनों की साझेदारी का सहारा 24 ओवरों में दी। मुंबई की ओर से विकेट के पहले दो विकेट लिए।

सौराष्ट्र पर दिल्ली की जीत में चमके प्रियांश आर्य और तेजस्वी दहिया

बीकानेर: अजमेर स्टेडियम में बीकानेर में खेले गए विजय हजारे ट्रॉफी के अंतिम ग्रुप-डी मैच में दिल्ली ने सौराष्ट्र को 5 विकेट से हरा दिया। विकेट कीपर की भूमिका निभाते हुए दिल्ली की टीम ने 50 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मैच में पहला और अंतिम जवाब दिल्ली की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। एक पारी में अर्द्ध शतक लगाकर एकतरफा में छह जमाने की रेलों के लिए मैच में होंगे।

दिल्ली ने कप्तान विराट कोहली के नेतृत्व में सौराष्ट्र को 124 रन पर 115 रन की पारी और रवीश अहीर 65 रन पर 35 रन की बनी बनाकर 50 ओवर में कुल विकेट पर 230 रन बनाए। दिल्ली ने पहले दो मैच में पराजय और अंतिम जवाब दिल्ली की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। एक पारी में अर्द्ध शतक लगाकर एकतरफा में छह जमाने की रेलों के लिए मैच में होंगे।

दिल्ली के कप्तान विराट कोहली ने शानदार खेलने में नवमान तो और 26 गेंद में 22 रन बनाकर विराट खेलने की गेंद का हल मोहित की बैग में गेंदें। विराट ने पंकज सलारिया की गेंद पर आउट होने से पहले अपने बेमेल के साथ दूसरे विकेट के लिए 66 रन की साझेदारी की थी। दिल्ली की टीम जीत में 12 अंक के साथ ग्रुप डी में पहले स्थान पर है।

मुकाबले में सौराष्ट्र 30 रन ही बना सके। सौराष्ट्र ने पांच विकेट में रन गिराए। सौराष्ट्र ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपने विकेट पर 230 रन का स्कोर खड़ा किया, जिसमें कप्तान अर्पेश (65) और कृष्णा भगत (51) ने अर्धशतक लगाए। उत्तरार्द्ध में कप्तान कुमार मोहित (115) के शानदार शतक की मदद से 47.4 ओवर में पांच विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।

मुकेश-अंकी की जोड़ी ने उड़ीसा को हराया: बंगलौर स्टेडियम में उड़ीसा के कप्तान मुकेश कुमार (2/37) की शानदार गेंदबाजी के दम पर बंगाल ने हुए की मुकाबले में चंडीगढ़ को हराया। चंडीगढ़ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान मनन वोहरा के शतक के दम पर 250 रन बनाए। वोहरा के अलावा चंडीगढ़ का कोई भी बल्लेबाज नहीं चला। इसके जवाब में बंगाल ने सुबह विकेटकीपर अभिषेक पोरेल (106) के शतक के दम पर 47.4 ओवर में चार विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। बंगाल ने यह मैच एक विकेट से जीता। वहीं, बिहार ने तमिलनाडु के खिलाड़ी विकेट से हराया। जम्मू-कश्मीर ने 311 रन बनाए थे, बिहार ने शतक मोहाली (199) और रोहन कुमार (114) के शतकों से अपना जीत हासिल कर ली।

सरकारी योजना के विपरीत चालू वित्त वर्ष में गैस की खपत घटी

- वर्ष 2030 तक देश की इकोनमी में गैस की हिस्सेदारी बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का लक्ष्य
- रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुसार, अप्रैल-अक्टूबर 2025 के दौरान गैस की खपत 4.6 प्रतिशत घटी
- एलएनजी कीमतों में उछाल रहा बड़ा कारण, गैस आधारित बिजली संयंत्र हुए प्रभावित
- अप्रैल से अक्टूबर तक भारत में प्राकृतिक गैस की खपत करीब 190 एमएमएससीएमडी रही

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : भारत में प्राकृतिक गैस की खपत में चालू वित्त वर्ष के पहले सात महीनों में कमी दर्ज की गई है। जो देश की अर्थव्यवस्था में गैस की हिस्सेदारी को मौजूदा सात प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने के लक्ष्य के अनुकूल नहीं है। क्रिसिल की तरफ से सोमवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल से अक्टूबर 2025 तक भारत में प्राकृतिक गैस की औसत खपत करीब 190 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन (एमएमएससीएमडी) रही है, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 200 एमएमएससीएमडी से 4.6 प्रतिशत कम है। हालांकि, सरकारी एजेंसी पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के आंकड़ों के मुताबिक इस अवधि में गैस की खपत में 8.6 प्रतिशत की गिरावट आई है। हालांकि, रिपोर्ट यह भी कहती है कि यह गिरावट स्थाई न हो, लेकिन यह साफ तौर पर बता रहा है कि देश में गैस की खपत बढ़ाने की योजना सही तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रही है।

क्रिसिल की रिपोर्ट बताती है कि स्पाट एलएनजी कीमतों में उछाल खपत में कमी का एक बड़ा कारण है। चालू वित्त वर्ष के दौरान इसकी कीमत औसतन 13 डालर प्रति एमएमबीटीयू (गैस मापने का मापक) रही है, जो पिछले साल के मुकाबले 34 प्रतिशत ज्यादा है। इसका सबसे ज्यादा असर प्राकृतिक गैस आधारित बिजली संयंत्रों पर पड़ा है। देश में तकरीबन 25 हजार मेगावाट क्षमता की गैस आधारित बिजली संयंत्र तैयार होने के बावजूद गैस नहीं होने की वजह से नहीं चल पाते हैं। इनमें से कुछ संयंत्र जब विदेश में गैस सस्ती होती है तो उसे खरीदते हैं और इन संयंत्रों को चलाते हैं। हालांकि, जब कीमत 13 डालर प्रति एमएमबीटीयू हो तो इसे आयात कर भारत लाना और इससे तैयार कर बिजली बनाना फायदेमंद नहीं होता। ऐसे में इन संयंत्रों को चलाने वाली कंपनियां महंगी गैस नहीं खरीदती।

समय से पहले मानसून आने को दिखा असर

यह पूरा परिदृश्य केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के विपरीत है। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक देश की कुल ऊर्जा खपत में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को मौजूदा 6-7 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया जाए। रिपोर्ट के मुताबिक समय से पहले मानसून आने से गर्मी में कूलिंग की जरूरत घटी। हालांकि, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) सेक्टर में मजबूती दिखी है। इस सेक्टर में गैस की खपत सालाना आधार पर 8.8 प्रतिशत बढ़कर 44 एमएमएससीएमडी हो गई है। देश में जितनी गैस की खपत होती है उसका 23 प्रतिशत सीजीडी में ही हो रही है। यह आश्चर्यजनक नहीं है क्योंकि देश में सीएनजी स्टेशनों के साथ ही घरेलू पीएनजी कनेक्शनों में भी तेजी से विस्तार हो रहा है।

राजस्व परिषद कैविएट प्रक्रिया में खामी को दूर करे : हाई कोर्ट

विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राजस्व परिषद की ओर से दायर कैविएट प्रक्रिया में खामियां पाई गई हैं। इसे दूर करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। एकलपीठ ने कहा कि जब कोई कैविएट दायर किया जाता है तो राजस्व परिषद की रजिस्ट्री द्वारा कैविएटर के वकील को नोटिस नहीं भेजा जाता है, इससे प्रक्रिया में समस्याएं उत्पन्न होती हैं।

मथुरा निवासी त्रिभुवन गोयल की याचिका निस्तारित करते हुए न्यायमूर्ति ने यह टिप्पणी की। याचिका राजस्व परिषद की ओर पारित अंतरिम निषेधाज्ञा के खिलाफ है। प्रतिवादी केशव देव केडिया की तरफ से दायर संक्षिप्त जवाबी हलफनामा में दलील दी गई है कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। कोर्ट ने कहा कि हम फिलहाल आपत्ति पर फैसला नहीं दे रहे हैं। हमने राजस्व परिषद के कार्यालय में कैविएट मैनेजमेंट के मुद्दे पर पक्षों

को सुना है। चाहे वह प्रयागराज हो या लखनऊ या अथवा सर्किट बेंच, यहां कैविएट मार्क करने की प्रक्रिया गलत लगती है। कैविएट दर्ज होने के बाद अपील, रिवीजन या बोर्ड के सामने शुरू की गई अन्य कार्यवाही के मेमो की शुरुआती जांच के दौरान कैविएट को मार्क करने और सूचना देने की कोई प्रक्रिया नहीं है। राजस्व परिषद कार्यालय में मामला शुरू होने के बाद अगर कार्यवाही में कोई कैविएट दर्ज किया जाता है तो उसे मार्क किया जाता है। बिना वकील या मामला शुरू करने वाली पार्टी को सूचना दिए कागजात संबंधित डिविजनल क्लर्क को भेज दिए जाते हैं, चाहे वह रिवीजन, अपील या अन्य कार्यवाही हो।

राज्य में औद्योगिक निवेश के लिए जापान जाएंगे मुख्यमंत्री योगी

सीएम बनने के बाद होगा योगी आदित्यनाथ का पांचवां विदेश दौरा

मनोज त्रिपाठी • जागरण

लखनऊ: राज्य में औद्योगिक निवेश लाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द जापान के दौरे पर जाएंगे। उनके साथ औद्योगिक विकास विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के मंत्री व अधिकारी भी दौरे पर जाएंगे। इन्वेस्ट यूपी ने मुख्यमंत्री के जापान दौरे की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी का यह पांचवां विदेश दौरा होगा। इसलिए उनके इस दौरे को अहम माना जाना जा रहा है। इस सिलसिले में इन्वेस्ट यूपी के अधिकारियों की एक टीम जापान का दौरा कर राज्य में निवेश लाने की नींव रख चुकी है।

राज्य की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डालर का आकार देने के लिए ज्यादा से ज्यादा विदेशी निवेश आकर्षित किया जाना जरूरी है। इसीलिए इन्वेस्ट यूपी पिछले छह माह से इस दिशा में प्रयास कर रहा है। इन्वेस्ट यूपी ने चाइना प्लस योजना के तहत निवेश के लिए उन देशों पर ज्यादा फोकस किया है कि जिन्होंने चीन में भारी निवेश कर रखा है। इन देशों को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आकर्षित करने के उद्देश्य से इन्वेस्ट यूपी ने छह देशों की विशेष डेस्क व टीमों का गठन किया है। यह टीमें संबंधित देशों के निवेशकों के साथ संपर्क कर उन्हें राज्य में निवेश के लिए प्रेरित कर रही हैं।

इसी सिलसिले में अक्टूबर में इन्वेस्ट यूपी की टीम ने अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी शशांक चौधरी के नेतृत्व में जापान का दौरा कर 40 से ज्यादा निवेशकों के साथ बैठकें कर निवेश लाने की नींव रखी थी। इसकी रिपोर्ट शासन को भेजी जा चुकी है।

इन्वेस्ट यूपी को जापान से 20 हजार करोड़ रुपये का औद्योगिक निवेश आने की उम्मीद है। इसी संदर्भ में मुख्यमंत्री के जापान दौरे की तैयारियां की जा रही हैं। अभी तक दौरे की तिथि निर्धारित नहीं की गई है। कोशिश है कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (जीबीसी)-5 से पहले यह दौरा हो जाए।

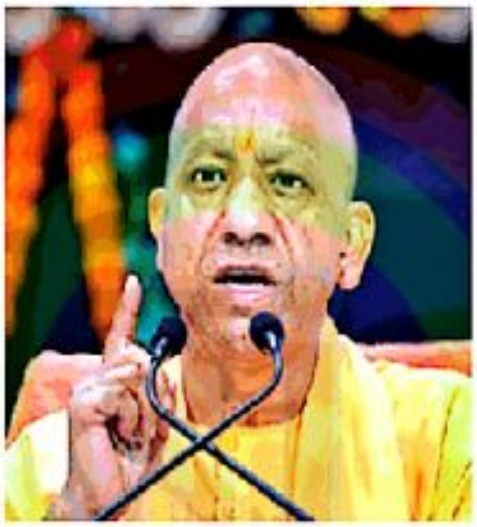

योगी आदित्यनाथ (फाइल)

- इन्वेस्ट यूपी ने शुरू की मुख्यमंत्री के दौरे की तैयारियां
- 20 हजार करोड़ रुपये का निवेश कर सकती हैं जापानी कंपनियां

यहां हो चुका योगी का दौरा

मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने अगस्त 2017 में पहला दौरा म्यांमार का किया था। उन्होंने यंगून में पर्यावरण पर अंतरराष्ट्रीय कान्फ्रेंस में शिरकत की थी। नवंबर 2017 में मारीशस में प्रवासी भोजपुरी सम्मेलन में हिस्सा लिया था। उनके इस दौरे में मारीशस जय श्रीराम के नारों से गूंज उठा था। दिसंबर, 2018 में मुख्यमंत्री नेपाल के जनकपुर में आयोजित राम सीता विवाह पंचमी समारोह में शामिल हुए थे। इसके बाद वर्ष 2019 में वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ रूस के दौरे पर गए थे।

लेखपाल भर्ती विज्ञापन पर श्वेत पत्र की मांग

राज्य ब्यूरो, जागरण● प्रयागराज : लेखपाल भर्ती परीक्षा 2025 के विज्ञापन को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी और छात्र आंदोलन समन्वय समिति के संयोजक प्रशांत पाण्डेय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर 16 दिसंबर को जारी विज्ञापन को निरस्त किए जाने और 28 दिसंबर को संशोधित विज्ञापन जारी करने पर कड़ा एतराज जताया है। उन्होंने इस पूरे प्रकरण पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग करते हुए आरोप लगाया कि राजनीतिक दबाव के चलते अनारक्षित वर्ग के मेधावी छात्रों के हितों से समझौता किया गया है।

प्रशांत पांडेय के अनुसार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 16 दिसंबर को विज्ञापन जारी कर लेखपाल के लिए अनारक्षित वर्ग के 4165 पद घोषित किए थे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद 28 दिसंबर को नया विज्ञापन जारी कर अनारक्षित पदों की संख्या घटाकर 3205 कर दी गई।

छात्र संगठनों का कहना है कि यह बदलाव न तो पारदर्शी है और न ही इसके पीछे कोई स्पष्ट प्रशासनिक कारण सामने आया है। उनका कहना है कि यदि पहले जारी विज्ञापन गलत था तो सरकार यह स्पष्ट करें कि उसमें क्या त्रुटि थी, उस त्रुटि के लिए जिम्मेदार कौन था और उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। यह भी बताया जाए कि नए विज्ञापन में अनारक्षित पदों की संख्या किस आधार पर घटाई गई। छात्र संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार इस मुद्दे पर शीघ्र श्वेत पत्र जारी नहीं करती या फिर 16 दिसंबर के विज्ञापन के अनुसार भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाती तो अनारक्षित वर्ग के छात्र न्यायालय की शरण लेने के साथ प्रदेशव्यापी आंदोलन को बाध्य होंगे।

●प्रतियोगी छात्रों ने लगाया अनारक्षित वर्ग के साथ अन्याय का आरोप

आरक्षण का हक मारते हैं भाजपाई : अखिलेश

राज्य ब्यूरो, जागरण● लखनऊ: सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा को आरक्षण विरोधी करार दिया है। उन्होंने सोमवार को एक्स पर लिखा कि भाजपाई वो घोटालेबाज लोग हैं जो संविधान द्वारा दिया गया आरक्षण भी सरेआम मार देते हैं। वहीं, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय से देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की हत्या के मामले का स्वतः संज्ञान लेने की मांग भी की है।

अखिलेश यादव (फाइल)

लेखपाल भर्ती के श्रेणीवार आरक्षण में गलती के बाद हाल ही में उसका संशोधित विज्ञापन जारी किया गया है। इसे लेकर सपा प्रमुख ने एक्स पर लिखा,' भाजपाई वो पीडीए विरोधी लोग हैं, जो जानबूझकर आरक्षण की हकमारी करते हैं और सोचते हैं कि पकड़ गए तो दे देंगे। वर्चस्ववादी भाजपाइयों के मन में भेदभाव का जो विष भरा है, वो कभी पीडीए के खिलाफ हिंसा, शोषण, अत्याचार, छुआछूत के रूप में बाहर आता है तो कभी आरक्षण मारने या गंगा जल से धुलवाने के कुत्सित रूप में।' एक अन्य पोस्ट में उन्होंने देहरादून की घटना को लेकर लिखा कि घटना नफरती लोगों की बेहद घृणित मानसिकता का दुष्परिणाम है। विघटनकारी सोच रोज किसी की जान ले रही है। वहीं सपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व सांसद नरेश उत्तम पटेल ने कहा है कि भाजपा में अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी पर्चा निकाल कर बनाए जाते हैं, जबकि सपा नेता बनाने का कारखाना है, विचारधारा की पार्टी है।

इंडिया पोस्ट: 48 स्टाफ कार ड्राइवर पद

- **अंतिम तिथि:** 19 जनवरी, 2026
- **शैक्षणिक योग्यता:** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अधिसूचना में वर्णित वांछित एवं अन्य समकक्ष योग्यता
- **वेबसाइट/आवेदन:** indiapost.gov.in

मेट्रो रेलवे, कोलकाता: 128 अप्रेंटिस पद

- **अंतिम तिथि:** 22 जनवरी, 2026
- **शैक्षणिक योग्यता:** किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से 10वीं/नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट एवं अन्य समकक्ष योग्यता
- **वेबसाइट/आवेदन:** mtp.indianrailways.gov.in

NHIDCL: 48 सीनियर मैनेजर एवं अन्य पद

- **अंतिम तिथि:** 13 जनवरी, 2026
- **शैक्षणिक योग्यता:** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से इंजीनियरिंग में डिग्री एवं अन्य समकक्ष योग्यता
- **वेबसाइट/आवेदन:** nhidcl.com

OSSC CGL: 1576 ग्रुप-बी और सी पद

- **अंतिम तिथि:** 18 जनवरी, 2026
- **शैक्षणिक योग्यता:** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से डिग्री एवं अन्य समकक्ष योग्यता
- **वेबसाइट/आवेदन:** ossc.gov.in

सरकारी नौकरियों में पूर्व सैनिकों का कोटा 10 से 25%, लेकिन भर्ती सिर्फ 1.9%

नई दिल्ली, प्रेट्र: संसद की एक समिति ने सोमवार को पूर्व सैनिकों के लिए पुनर्वास नीतियों और स्वास्थ्य सुविधाओं पर चर्चा की तथा सैनिकों की सेवानिवृत्ति के बाद रोजगार की संभावनाओं के बारे में विवरण उपलब्ध कराने की मांग की। सूत्रों ने बताया कि भाजपा सांसद राधामोहन सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा संबंधी स्थायी समिति की बैठक में सांसदों ने बताया कि सरकारी नौकरियों में केवल 1.9 प्रतिशत पूर्व सैनिकों की भर्ती की जा रही है, जबकि 10-25 प्रतिशत पूर्व सैनिकों को समाहित करने का प्रविधान है।

संसदीय समिति की बैठक में सरकारी नौकरियों में पूर्व सैनिकों की भर्ती का मुद्दा उठा

सूत्रों के अनुसार, संसदीय समिति के सदस्य और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूर्व सैनिकों को सैन्य अस्पतालों में इलाज कराने में आने वाली कठिनाइयों का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि जब पूर्व सैनिकों को निजी अस्पतालों में भेजा जाता है, तो उन्हें इलाज और प्रवेश में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई अस्पताल यह कहते हुए इलाज से इन्कार कर देते हैं कि सरकार ने पिछला बकाया नहीं चुकाया है।

राहुल गांधी ने यह मुद्दा भी उठाया कि पूर्व सैनिकों को कैंसर और किडनी के इलाज के लिए केवल 75 हजार रुपये मिलते हैं, जो बेहद अपर्याप्त है। उन्होंने सवाल किया कि इतनी छोटी राशि में कैंसर या किडनी का उपचार कैसे संभव है और सुझाव दिया कि इस सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए।

पीईटी परीक्षा में पूर्व घोषित कटआफ की सीएम से की मांग

राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज : प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा (पीईटी) में पूर्व घोषित और समान (कामन) कटआफ निर्धारित किए जाने की मांग को लेकर पीईटी अभ्यर्थियों की ओर से मुख्यमंत्री को एक विस्तृत प्रतिवेदन भेजा गया। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष और मुख्य सचिव को भी पत्र के जरिये मांगों की जानकारी दी गई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि पीईटी का उद्देश्य विभिन्न भर्तियों के लिए योग्य अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा तक पहुंच प्रदान करना है न कि अंतिम चयन करना। इसके बावजूद वर्तमान व्यवस्था में कटआफ न तो पहले से तय होती है और न ही घोषित की जाती है। इसकी वजह से अभ्यर्थियों को आर्थिक, मानसिक और व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

राजस्व परिषद कैविएट प्रक्रिया में खामी दूर करे : हाई कोर्ट

कोर्ट ने कहा, सदस्यों के साथ मिल कर अध्यक्ष उठाएं उचित कदम

विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राजस्व परिषद की ओर से दायर कैविएट प्रक्रिया में खामियां पाई गई हैं। इसे दूर करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की एकलपीठ ने कहा कि जब कोई कैविएट दायर किया जाता है तो राजस्व परिषद को रजिस्ट्री द्वारा कैविएटर के वकील को नोटिस नहीं भेजा जाता है, इससे प्रक्रिया में समस्याएं उत्पन्न होती हैं।

मधुप निवासी त्रिभुवन गौतम की याचिका निस्तारित करते हुए न्यायमूर्ति ने यह टिप्पणी की। याचिका राजस्व परिषद की ओर पारित अंतरिम निषेधाज्ञा के खिलाफ है। प्रतिवादी केशव देव केडिया की ओर से दायर संक्षिप्त जवाबी हलफनामा में दलील दी गई है कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। कोर्ट ने कहा कि हम तिलकाल आपत्ति पर फैसला नहीं दे रहे हैं। हमने राजस्व परिषद के कार्यालय में कैविएट मैनेजमेंट के मुद्दे पर चर्चा की सुन है। चाहे वह प्रयागराज हो या लखनऊ या अथवा सर्किट बेंच, यहां कैविएट मार्क करने की प्रक्रिया गलत लगती है। कैविएट दर्ज होने के बाद अपील, रिवीजन या कोई के सामने शुरू की गई अन्य कार्यवाही के मामले की शुरुआती जांच के दौरान कैविएट को मार्क करने और सूचना देने की कोई प्रक्रिया नहीं है। राजस्व परिषद कार्यालय में कोई खास मामला शुरू होने के बाद अगर कार्यवाही में कोई कैविएट दर्ज किया जाता है तो उसे मार्क किया जाता है। जिन वकील या मामला शुरू करने वाली पार्टी को सूचना

यह दिए हैं दिशा निर्देश

- आउटस्टेशन वाले वकीलों को कोई वकील नगर। स्टेशन) पर स्थानीय वकील नियुक्त करना होगा।
- वकीलों को अपना ई-मेल और मोबाइल नंबर देना होगा ताकि उन्हें नोटिस भिजवाया जा सके।
- वकीलों को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में शामिल होने की सुविधा प्रदान की जाए।
- आउटस्टेशन वकीलों को नोटिस भेजने के लिए कम से कम एक सप्ताह का समय दिया जाए।

दिए गए गए संबंधित डिविजनल क्लर्क को भेज दिए जाते हैं, चाहे वह रिवीजन, अपील या अन्य कार्यवाही हो। इसके बाद डिविजनल क्लर्क आर्डर-शीट के किनारे पर एक दिन पहले एंडोर्समेंट करता है, तब कागजात मोशन लिस्टिंग के लिए कोर्ट में भेजे जाते हैं।

कोर्ट ने राजस्व परिषद के चेयरमैन से कहा है कि वह सदस्यों के साथ मिल कर मामले में जरूरी कदम उठाएं। कोर्ट ने याचिका प्रतिपक्षी केशव देव केडिया की अन्य याचिका के साथ संबद्ध करते हुए अगली सुनवाई के लिए आठ जनवरी 2026 की तारीख नियत की है।

नंबर बढ़ने के अनुमान मात्र के आधार पर पुनर्मूल्यांकन नहीं करा सकते

विधि जागरण, प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी छात्र या छात्रा को यह लगता है कि पुनर्मूल्यांकन होने पर उसके अंक बढ़ सकते हैं तो मात्र अनुमान के आधार पर उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन नहीं कराया जा सकता। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उच्च इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट, 1921 में पुनर्मूल्यांकन का कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है। न्यायमूर्ति विवेक सरन की एकलपीठ ने बैच कमर की याचिका खारिज करते हुए कहा कि जब तक नियम इसकी अनुमति न दें, ऐसी मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता। याची ने इंटरमीडिएट परीक्षा में अपने अंकों से असन्तुष्ट होकर हिंदी और गणित विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कूटनी के लिए आवेदन किया था। उत्तर पुस्तिकाएं देखने के बाद उसे विश्वास हुआ कि अधिक अंक मिल सकते थे। इसके बाद उसने बोर्ड के क्षेत्रीय सचिव मेरठ के समक्ष पुनर्मूल्यांकन का आवेदन किया जो यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया गया कि उपनियम-12, नियम-21 (ड) के अंतर्गत पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है। इस आदेश को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। कोर्ट ने राजेश विश्वकर्मा अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का उल्लेख करते हुए कहा कि पुनर्मूल्यांकन तभी संभव है जब कानून या नियम इसकी अनुमति देते हों। जहां ऐसा प्रावधान मौजूद न हो वहां न्यायालय केवल दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों में ही हस्तक्षेप कर सकता है।

आवेदन की तिथि से ही अंतरिम भरण पोषण भत्ता

- परिवार न्यायालय कौशांबी का आदेश किया संशोधित

विधि जागरण, प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अंतरिम भरण-पोषण भत्ता आवेदन की तारीख से दिया जाना चाहिए, न कि आदेश की तारीख से। न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ल की एकलपीठ ने कौशांबी की सोनम यादव की याचिका स्वीकार कर परिवार न्यायालय का आदेश संशोधित करते हुए यह निर्णय दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि 'अगर आवेदन की तारीख से भरण-पोषण नहीं दिया जाता है तो इससे पत्नी को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है।'

मुकदमे से जुड़े तथ्यों के अनुसार, सोनम यादव ने अक्टूबर 2023 में सीआरपीसी की धारा 125 के तहत आवेदन किया। अगस्त 2024 में अंतरिम भरण-पोषण के लिए आवेदन किया गया। फैमिली कोर्ट ने अप्रैल 2025 में दिए आदेश कहा था कि भरण-पोषण उसके आदेश की तारीख से दिया जाएगा, न कि आवेदन की तारीख से। कौशांबी की परिवार अदालत द्वारा केस नंबर 573/2023 (सोनम यादव बनाम उत्तेजन यादव) में सुनाए गए आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। याची गायी के अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के रजनेश बनाम नेहा (2021) मामले का उल्लेख किया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आमतौर पर भरण-पोषण के लिए आवेदन की तारीख से भरण-पोषण दिया जाना चाहिए। यह नियम अंतरिम भरण-पोषण के लिए भी लागू होता है, जो मुख्य आवेदन के दौरान दिया जाता है। प्रतिवादी के वकील का तर्क था कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश केवल अंतिम भरण-पोषण आदेशों के लिए है न कि अंतरिम भरण-पोषण के लिए। अंतरिम भरण-पोषण के लिए अलग से विचार किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि आवेदन की तारीख से ही भरण-पोषण दिया जाना चाहिए, न कि आदेश की तारीख से। अगर आवेदन की तारीख से भरण-पोषण नहीं दिया जाता है तो इससे महिला को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। भरण-पोषण भत्ता संबंधी आदेश ऐसे महिलाओं-बच्चों के लिए होते हैं जो अपने पति या पिता द्वारा छोड़ दिए गए हैं अथवा जिनके पास रहने के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं। अभी तक कोई अंतिम आदेश नहीं आया है, लेकिन इस स्थिति में भी महिला को भरण-पोषण का अधिकार है और यह अधिकार आवेदन की तारीख से ही लागू होना चाहिए।

प्रयाग महिला विद्यापीठ प्रबंध समिति की विशेष अपील खारिज

विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रयाग महिला विद्यापीठ प्रबंध समिति की एक विशेष अपील खारिज कर दी है, जिसमें उसने शिक्षिका डा. रजनी त्रिपाठी को सेवानिवृत्ति देयों के भुगतान किए जाने संबंधी एकलपीठ के आदेश को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह तथा न्यायमूर्ति विवेक सरन की खंडपीठ ने कहा कि शिक्षिका को तीन महीने के अंदर देय राशि का भुगतान किया जाए। मुकदमे के अनुसार, डा. रजनी त्रिपाठी 30 जून 2024 को

सेवानिवृत्त हुईं। उनकी सेवानिवृत्ति से पहले 27 मई 2024 को प्रबंध समिति ने उनकी नियुक्ति को अवैध ठहराते हुए प्रस्ताव पारित किया। कहा गया कि वीआर द्वितीय वर्ष की मार्कशीट फर्जी है, इसका उपयोग कर उन्होंने 27 वर्षों तक नौकरी की। खंडपीठ ने कहा, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के मूल रिकार्ड की जांच के बाद पाया गया कि पत्नी ने 1800 में 577 अंक प्राप्त किए थे। कहा, योग्यता पर कोई संदेह नहीं है। कोर्ट ने कहा, शिक्षिका को उनकी 27 वर्षों की सेवा के लिए देय राशि का भुगतान किया जाना चाहिए। यह भुगतान उनकी सेवा का बदला है न कि उनकी शैक्षिक उपलब्धियों का पुरस्कार। एकलपीठ ने न्यायहित में यह आदेश दिया था। खंडपीठ ने हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया।

नोटिस या आदेश का पोर्टल पर अपलोड होना ही वास्तविक सूचना नहीं : हाई कोर्ट

जीएसटी विभाग का दावा वसूली आदेश किया रद, पुनर्विचार का निर्देश

विधि संवाददाता, जागरण, इलाहाबाद: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जीएसटी विभाग द्वारा सिर्फ आनलाइन पोर्टल पर नोटिस या आदेश अपलोड करने को 'सूचना' नहीं मानते हुए अर्जियां खारिज कर दावा वसूली करने की कार्यवाही रद कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने दर्जनों याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट का कहना है कि नोटिस या आदेश का सिर्फ सामान्य पोर्टल पर अपलोड हो जाना, करदाता तक उसकी वास्तविक सूचना नहीं माना जा सकता, जब तक कि उसे वास्तविक या रचनात्मक रूप से तामील न किया गया हो।

कोर्ट ने कहा, जीएसटी लागू होने के बाद से राज्य कर अधिकारियों ने नोटिस और आदेशों की फिजिकल डिलीवरी (डाक या हाथ से) का चलन लगभग पूरी तरह बंद कर दिया, जबकि केंद्रीय कर अधिकारी अब भी आफलाइन

मोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बदलाव से छोटे और मध्यम स्तर के व्यवसायी, जो पहले व्यापार कर/वैट कर व्यवस्था में फिजिकल नोटिस के अभ्यस्त थे, परेशानी में पड़ गए। उन्हें नोटिस या आदेश की जानकारी ही नहीं मिल पाती और अपील दाखिल करने की समय सीमा समाप्त हो जाती है। ऐसे में उनके खिलाफ एकतरफा वसूली आदेश पारित हो जाते हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जीएसटी अधिनियम की धारा 169(1) के खंड (क) से (ङ) तक के सभी मोड (हाथ से देना, स्पीड पोस्ट, ई-मेल, पोर्टल पर उपलब्ध कराना, अखबार में प्रकाशन) वैकल्पिक हैं। कर अधिकारी किसी का भी चुनाव कर सकते हैं। केवल अंतिम मोड 'चस्पा करने का उपयोग तभी हो सकता है जब पहले के पांचों मोड 'व्यावहारिक' न हो सके हों। सिर्फ पोर्टल पर सूचना डाल देने से यह नहीं माना जाएगा कि नोटिस/आदेश करदाता को प्राप्त हो गया है। अपील की मियाद तभी शुरू होगी जब आदेश करदाता को वास्तविक रूप से या रचनात्मक रूप से तामील किया गया हो, न कि सिर्फ अपलोड होने की तारीख से। कोर्ट ने जीएसटी नेटवर्क जीएसटीएन द्वारा संचालित कामन पोर्टल की खामियां भी बताईं। कहा हिंदी इंटरफेस का अभाव है। यह भी ट्रैक करने का साधन नहीं है कि करदाता ने नोटिस देखा या डाउनलोड किया। नोटिस/आदेश को आसानी से देख पाने के लिए उपयोगकर्ता-अनुकूल टैब्स भी नहीं हैं। एक ही करदाता वर्ग के लिए, एक ही जीएसटी कानून के तहत, राज्य और केंद्रीय अधिकारी सेवा के अलग-अलग तरीके अपना रहे हैं जो भ्रम और अनावश्यक मुकदमेबाजी पैदा कर रहा है।

एआइ के जनक आल्टमैन ने माना 'भस्मासुर' साबित होने लगा है ये

ओपनएआइ के सीईओ ने किया पांच करोड़ की नौकरी का एलान

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) के तेजी से बढ़ते दायरे और उसके संभावित दुष्प्रभावों को लेकर अब खुद ओपनएआइ के सीईओ सैम आल्टमैन चिंतित नजर आ रहे हैं। उन्होंने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर 'हेड आफ प्रिपेयर्डनेस' नाम के एक अहम पद के लिए भर्ती का एलान किया है, जिसका मकसद एआइ से पैदा होने वाले खतरों को समय रहते पहचानना और उनसे निपटना होगा। इस पद के लिए करीब 5.55 लाख डालर (लगभग पांच करोड़ रुपये, इक्विटी अलग से) का सालाना पैकेज प्रस्तावित किया गया है। कंपनी ने भी पहली बार खुले तौर पर माना है कि एआइ के मानसिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी उतने ही गंभीर हैं, जितने तकनीकी खतरे।

सैम आल्टमैन ने साफ किया कि यह एक बेहद तनावपूर्ण जिम्मेदारी होगी। चयनित व्यक्ति को यह समझना होगा कि एआइ किस तरह खतरनाक रूप ले सकता है और उसे कैसे नियंत्रित किया जाए। उनके मुताबिक, सबसे बड़ी चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ एआइ की ताकत का इस्तेमाल कर सकें, लेकिन हैकर्स और हमलावर इसका दुरुपयोग न कर पाएं। नया अधिकारी ओपनएआइ की जोखिम से निपटने की पूरी रणनीति संभालेगा और साइबर सुरक्षा, जैव सुरक्षा तथा खुद को बेहतर बनाने वाले एआइ सिस्टम जैसे संवेदनशील क्षेत्रों पर खास नजर रखेगा।

एआइ की वक्रदृष्टि

- दुनिया को एआइ के बुरे प्रभावों से बचाने वाले 'हेड आफ प्रिपेयर्डनेस' की बताई जरूरत
- एआइ एजेंट बन रहे नई चुनौती साइबर हमले और मानसिक स्वास्थ्य पर खतरे की चेतावनी
- ओपनएआइ ने माना- उन्नत एआइ माडल कंप्यूटर सुरक्षा में गंभीर कमजोरियां खोजने लगे

सैम आल्टमैन • फाइल

बढ़ रहे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मामले: एआइ की तमाम खूबियों के बीच हाल के महीनों में इससे जुड़ी नकारात्मक घटनाओं ने चिंता बढ़ा दी है। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में एआइ चैटबाट्स की भूमिका पर सवाल उठे हैं। कुछ मामलों में आरोप लगे हैं कि एआइ की सलाह ने हिंसक घटनाओं और आत्मघाती प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया। बता दें कि चैटजीपीटी को लेकर कई मुकदमे सामने आए हैं, जिनमें आरोप लगाया गया है कि एआइ चैटबाट ने किशोरों में आत्महत्या जैसे मामलों में भूमिका निभाई या लोगों के भ्रम और साजिशी सोच को बढ़ावा दिया। एक व्यक्ति के मर्डर-सुसाइड से जुड़े आरोप भी लगाए गए हैं।

कंप्यूटर में घुसने के रास्ते खोज चुका है एआइ: आल्टमैन ने एक्स पर लिखा कि एआइ एजेंट बहुत तेजी से विकसित हो रहे हैं, जिससे गंभीर चुनौतियां सामने आ रही हैं। उन्होंने माना कि एआइ आधारित साइबर हथियार भविष्य में बड़ा खतरा बन सकते हैं। इसी कारण ओपनएआइ अब सुरक्षा और जोखिम प्रबंधन पर पहले से ज्यादा जोर दे रहा है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि एआइ एजेंट एक उभरती हुई समस्या बन चुके हैं। ओपनएआइ के अनुसार, उसके कुछ उन्नत एआइ माडल अब कंप्यूटर सुरक्षा प्रणालियों में गंभीर कमजोरियां पहचानने लगे हैं।

एआइ से होने वाले साइबर खतरों की आशंका के बीच यह भर्ती और अहम मानी जा रही है। हाल ही में ओपनएआइ की प्रतिद्वंद्वी कंपनी एंथ्रोपिक ने दावा किया था कि चीन से जुड़े हैकर्स ने उसके एआइ टूल का इस्तेमाल कर दुनियाभर के करीब 30 संस्थानों- टेक कंपनियों, वित्तीय संस्थानों और सरकारी एजेंसियों- पर साइबर हमले किए, जिनमें मानवीय हस्तक्षेप बेहद कम था।

PdfLogy : Made With Readers Friendly 💁

Join us For All Study Materials ,Free Pdf and Notes

JOIN Telegram Group For FREE PDF & All Exams Updates

CLICK HERE

JOIN WhatsApp Channel

CLICK HERE

PDFLOGY
Made With Readers Friendly.....

Search On Google - PdfLogy.Blogspot.Com